

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. VI, Second Session, 2019/1941 (Saka)
No. 13, Wednesday, December 04, 2019/Agrahayana 13, 1941 (Saka)**

S U B J E C T**P A G E S****ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

* Starred Question Nos. 221 to 227 12-51

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos. 228 to 240 52-105

Unstarred Question Nos. 2531 to 2760 106-627

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 628-636

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 636

**AMENDMENTS TO DIRECTIONS BY THE SPEAKER,
LOK SABHA (DIRECTIONS 27 AND 42) UNDER THE
RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF
BUSINESS IN LOK SABHA** 636

**STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS
AND FERTILIZERS**

Action Taken Statements 637

STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL

1st and 2nd Reports 637

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 143rd Report of the Standing Committee on Commerce on Action taken by the Government on the recommendations/observations contained in 137th Report of the Committee on 'Trade with Association of South East Asian Nations (ASEAN)' pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry

Shri Som Prakash 638

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Reported Chinese incursion into the territory of India 639-642

MATTERS UNDER RULE 377 659-675

- (i) Need to start construction work on Nanjangud-Wayanad-Nilambur rail line

Shri Rahul Gandhi 659

- (ii) Need to make Maternity Benefit Scheme more beneficiary friendly

Shrimati Kanimozhi Karunanidhi 660

- (iii) Need to make Gorakhpur a Centre for UPSC examinations

Shri Ravi Kishan 661

- (iv) Need to take steps to revive jute industry in West Bengal

Shrimati Locket Chatterjee 662

- (v) Need to provide employment to locals by Public Sector undertakings

Shri Devusinh Chauhan 662

- (vi) Regarding establishing two new Indian Reserve Battalion (IRBs) at Davangere in Karnataka

Shri G.M. Siddeshwar 663

- (vii) Need to revive the closed cotton mill in Etawah Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Dr. Ram Shankar Katheria 663

- (viii) Need to take steps to start construction of Pune-Ahmednagar-Jalgaon railway line

Dr. Sujay Vikhe Patil 663

- (ix) Need to formulate an action plan to weed out 'Vilayati Babul' in the country particularly in Rajasthan

Shri Ramcharan Bohra 664

- (x) Regarding refund of people's money who invested in PACL Limited , a Pearl Group company

Shri Bhanu Pratap Singh Verma 664

- (xi) Regarding building multi-specialty Hospital in Siliguri

Shri Raju Bista 665

- (xii) Regarding eviction of families residing near railway property
- Shri N. K. Premachandran 665
- (xiii) Regarding vaccination for Foot and Mouth Disease (FMD) in West Bengal
- Dr. Subhas Sarkar 666
- (xiv) Regarding pending projects of Godda Parliamentary Constituency, Jharkhand
- Dr. Nishikant Dubey 666
- (xv) Need to develop Jaigaon in Alipurdwars Parliamentary Constituency, West Bengal as a Smart City
- Shri John Barla 667
- (xvi) Need to undertake repair of New Delhi - Lucknow National Highway-24 and also construct flyovers at various places on the National Highway
- Shri Rajesh Verma 667
- (xvii) Need to provide salary, allowances and other facilities to wardens of 'Nagrik Suraksha Corps' in Uttar Pradesh
- Shri Rajendra Agrawal 668

(xviii) Regarding NRC in Assam

Shri Abdul Khaleque 668

(xix) Regarding waste management solutions for Hyderabad

Shri Anumula Revanth Reddy 669

(xx) Need to boost Indian textile industry

Dr. T. R. Paarivendhar 669

(xxi) Need to redress grievances of Fair Price shop dealers

Prof. Sougata Ray 670

(xxii) Regarding withdrawing MEIS benefits for spices

Shri Lavu Srikrishna Devarayalu 671

(xxiii) Need to provide compensation to farmers who suffered loss of sugarcane due to flood and unseasonal rains in Maharashtra

Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane 671

(xxiv) Regarding vacancies in Maulana Azad National Urdu University at Gachibowli, Telangana

Dr. G. Ranjith Reddy 672

(xxv) Regarding setting up an airport at Rameswaram

Shri K. Navaskani 672

(xxvi) Need to include 11 communities of Sikkim in the list of Scheduled Tribes

Shri Indra Hang Subba 673

(xxvii) Regarding producing artificial meat

Shrimati Poonam Mahajan 674

(xxviii) Need to develop Sant Ravi Das Van Vihar in Basti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Harish Dwivedi 674

(xxix) Need to set up an industrial unit in Nanded Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Prataprao Patil Chikhlikar 675

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – 2019-2020 676-816

Dr. Shashi Tharoor 682-689

CUT MOTIONS 690

Shri Rajiv Pratap Rudy 692-702

Shri DNV. Senthilkumar S. 703-705

Prof. Sougata Ray	706-711
Shri Vinayak Bhaurao Raut	712-714
Shri P.V. Midhun Reddy	715-719
Shri Bhartruhari Mahtab	720-724
Dr. G. Ranjith Reddy	725-727
Shrimati Supriya Sadanand Sule	728-732
Shri Nihal Chand Chouhan	733-736
Shri Su Thirunavukkarasar	737-739
Shri P.K. Kunhalikutty	740-741
Adv. A.M. Ariff	742-744
Kunwar Danish Ali	745-746
Shri Hasnain Masoodi	749-757
Dr. Jitendra Singh	758-759
Shri Asaduddin Owaisi	760-762
Dr. Manoj Rajoria	763-764
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	765-768
Shri Kuldeep Rai Sharma	769-770
Shri N.K. Premachandran	771-773
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	773-774
Dr. Shrikant Eknath Shinde	775-786
Shri H. Vasanthakumar	787-790

Shri Saptagiri Shankar Ulaka	791-793
Shri Ritesh Pandey	794-796
Shri Jagdambika Pal	797-798
Shrimati Nirmala Sitharaman	799-816
Demands – Voted	816
 APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2019	 817-818
Motion to Consider	818
Clauses 2, 3 and 1	818
Motion to Pass	818
 <u>ANNEXURE – I</u>	
Member-wise Index to Starred Questions	819
Member-wise Index to Unstarred Questions	820-825
 <u>ANNEXURE – II</u>	
Ministry-wise Index to Starred Questions	826
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	827

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, December 04, 2019/Agrahayana 13, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 221, श्री सदाशिव किसान लोखंडे ।

(Q. 221)

अनेक माननीय सदस्य : अध्यक्ष जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, we have given notice for an Adjournment Motion. ...*(Interruptions)*

श्री सदाशिव किसान लोखंडे : अध्यक्ष महोदय, देश में मोबाइल की संख्या बढ़ती जा रही है । देश में हर आदमी के पास एक-दो मोबाइल उपलब्ध हैं । आज भी देश में लगभग 5 लाख 54 हजार लाइसेंस मोबाइल टावर्स के लिए दिए गए हैं । मेरा एक ही सुझाव है कि जिस टावर स्टेशन के लिए मोबाइल टावर लगाए गए हैं, उनसे विकिरणें निकलती हैं, जिनसे बीमारियां बढ़ रही हैं । इसके लिए मेरा प्रश्न है कि सरकार द्वारा मोबाइल विकिरण के प्रभाव से उत्पन्न खतरों के डर को भारतीयों के दिमाग से निकालने के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं? अगर प्रयास नहीं किए गए हैं तो उनके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, मेरी ओर से जन्मदिन की बधाई स्वीकार करें । आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं ।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, मेरी ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं । महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि देश में पिछले 18-19 वर्ष पहले जहां 3.58 परसेंट टेली डेंसिटी थी, आजकल वह बढ़कर 88.90 हो गयी है । स्वाभाविक है कि मोबाइल फोन के इस विस्तार से डिजिटल इंडिया कम्यूनिकेशन को काफी फायदा हुआ है । लेकिन एक बात सदन को भी समझनी होगी कि मोबाइल के लिए टावर जरूरी है और टावर के बिना मोबाइल नहीं चल सकता है । हम लोगों ने क्या किया है? मैं बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी भी है, जो पिछले 25-30 साल

की है, कि इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता है। लेकिन हमने हिन्दुस्तान में इसके जो नॉर्म्स रखे हैं, वे वर्ल्ड के नॉर्म्स से टेन टाइम्स अधिक कड़े रखे हैं। हमने पेनल्टी का भी प्रावधान रखा है। हम उसकी जांच करते हैं और अभी तक हमने करीब 20 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है, जो 20 लाख रुपये प्रति बीटीएस है। हमने करीब 12.50 करोड़ रुपये रिकवर भी किए हैं। यह सतत प्रक्रिया है और इस दिशा में और भी काम करने की आवश्यकता है। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि अगर मोबाइल का विस्तार करना है तो टावर जरूरी हैं और टावर नॉर्म्स के अनुसार चलें, इसकी हम चिंता करेंगे।

श्री सदाशिव किसान लोखंडे: अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि बीटीएस के संबंध में दूर संचार मंत्रालय द्वारा निर्देश बनाए गए हैं। इन निर्देशों के उल्लंघन के लिए दस लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बीटीएस मालिकों को सेल्फ सर्टिफिकेट देना होता है। इन स्टेशनों पर विकिरणों के नियमों के अनुसार अगर इनसे विकिरण निकलते हैं, संबंधित मोबाइल हेण्डसेट का निर्माण करने वाली कम्पनी की जिम्मेदारी है। इससे पता चलता है कि कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। लोगों का कहना है कि बीटीएस स्टेशनों के आस-पास के छोटे-छोटे गांवों में चिड़िया नहीं रही है। वहां के गरीब लोगों को बीमारी हो रही है, बुजुर्गों को बीमारी हो रही है। मेरा प्रश्न है कि मोबाइल विकिरण का प्रभाव पक्षियों, छोटे जानवरों, बच्चों पर पड़ रहा है तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? मेरा एक सुझाव है कि मैं जिस गांव में रहता था, वहां छोटी-छोटी चिड़िया रहती थीं, लेकिन आज गांवों में चिड़िया नहीं है। मोबाइल टावरों की वजह से गांवों में चिड़िया नहीं रही हैं, इसका कारण क्या है?

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही विनम्रता से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि उनके प्रश्न के दो अंग हैं। हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस बात का प्रावधान किया है। हमारी वेबसाइट है। अगर किसी भी ग्राहक को लगता है, तो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफार्म से जांच करके हमें यह बता सकते हैं कि इनके यहां अधिक एमिशन हो रहा है। हम उस पर कार्रवाई करेंगे।

महोदय, जहां तक चिड़ियों का सवाल है। मैं इस सदन को बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में चिड़िया बहुत स्वस्थ हैं। चिड़ियों का माइग्रेशन होता रहता है। यह एक फिनामिना है, बाकी हम इस पर बताएंगे। आप दिल्ली में हम लोगों के बंगलों में देखिए, मैं सुबह देखता हूं, तो नई-नई चिड़िया भी दिखाई पड़ती हैं। इसलिए इसके आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करना ठीक नहीं है। लेकिन आपके गांव में किसी के पास एविडेंस है कि उसको दिक्कत हुई है, तो आप हमें बताइए और हम उसकी जांच कराएंगे।

SHRI BRIJENDRA SINGH : Sir, given the sensitivity around EMF radiation, has the Government taken any steps to identify the sites for common use by all telecom operators instead of each one setting up his site everywhere?

दूसरा, आपने कहा है कि जो नार्म्स हैं, हमने उनको वर्ष 2011 से दस गुना इम्प्लीमेंट किया है। क्या इससे जो टावर्स की उपलब्धता है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? जैसे कॉल ड्रॉप उससे सीधे-सीधे प्रभावित होता है।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, the question of the hon. Member is in distinction to the question of the earlier hon. Member. I quite see his point that we need to have one tower catering to many licences so that there is no proliferation of towers. Therefore, we have already allowed the tower sharing principles.

As regards the specific problem about the issue not being settled, this norm not being followed, I can only tell you that my Department undertakes audit and a hefty penalty of Rs.20 crore has been imposed upon delinquent operators and nearly Rs.13 crore have been recovered. If the hon. Member has any specific suggestion to give, I am willing to consider that.

(Q. 222)

श्री राकेश सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही विस्तारित और अच्छा उत्तर दिया है, जिससे मेरे मूल प्रश्न का समाधान हो गया है। लेकिन फिर भी मेरी जानकारी में और इजाफा हो, इसके लिए मेरे दो प्रश्न हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, हर देश का अपना एक संचार तंत्र होता है और होना भी चाहिए। लेकिन देश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और ऐसा वातावरण बना रहे, इसके लिए निजी क्षेत्र का नेटवर्क होना भी आवश्यक है, ताकि दिन-प्रतिदिन इसमें सुधार होते रहें। इसी प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के सम्मिलन की दिशा में जो कदम आगे बढ़ाए हैं, वह स्वागत योग्य हैं। इसके कारण जहां पर प्रबंधन के खर्चों में कमी होगी, वहीं तकनीक का स्तर भी सुधरेगा।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस सम्मिलन के पश्चात् कर्मचारियों में गुणवत्ता सुधार और पफार्मेंस बढ़ाने के साथ-साथ विशेष रूप से कॉल ड्रॉप को रोकने के लिए मोबाइल नेटवर्क के रेगुलर ऑप्टिमाइजेशन का कोई ब्लू प्रिंट क्या सरकार तैयार करेगी?

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैं माननीय सदस्य को उनकी टिप्पणियों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार की सोच बहुत स्पष्ट है कि हम निजी क्षेत्र का स्वागत करते हैं। लेकिन एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए एक पीएसयू का रहना बहुत जरूरी है। मैं बीएसएनएल की तारीफ इसलिए करूंगा कि अगर कश्मीर में बाढ़ आती है, तमिलनाडु में बाढ़ आती है, नेपाल में भूकंप आता है या ओडिशा में तूफान आता है, तो ऐसे में हमें यह समझना पड़ेगा कि बीएसएनएल ही फ्री सेवा करता है।

दूसरी बात, जो डिफेंस का पूरा नेटवर्क है, वह भी बीएसएनएल ही मेनटेन करता है। इसलिए, हमारी सरकार की माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी की अगुवाई में साफ सोच है कि बीएसएनएल और

एमटीएनएल स्ट्रैटिजिक एसेट्स हैं, इसलिए हमें इनको मजबूत करना है और हम कर भी रहे हैं। लेकिन मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल में 1,65,000 कर्मचारी हैं और एमटीएनएल में 21,000 कर्मचारी हैं। हमको इम्प्लॉयी कॉस्ट रेवेन्यू का 75 प्रतिशत खर्चा करना पड़ता है और एमटीएनएल को रेवेन्यू का 87 प्रतिशत करना पड़ता है। जबकि एयरटेल 2.95 प्रतिशत खर्चा करता है, वोडाफोन 5.59 प्रतिशत और जियो 4.27 प्रतिशत करता है। इसमें कैसे स्वस्थ कंपीटीशन होगा। इसलिए हमने रिवाइवल में एक बहुत ही अच्छा लोकप्रिय वीआरएस पैकेज दिया है। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों ने स्वेच्छा से लगभग 92 हजार वीआरएस ऑप्ट किया है, कल अंतिम तारीख थी। हम उनको बहुत ही अच्छा वीआरएस दे रहे हैं। इसी में माननीय राकेश सिंह जी ने प्रश्न किया है, हम बीएसएनएल और एमटीएनएल को मर्ज भी कर रहे हैं। मर्जर की वैधानिक औपचारिकताओं में समय लगेगा, इसलिए हम पहले उनकी एक सब्सिडरी बना रहे हैं। गुणवत्ता के सुधार के दृष्टिकोण में यही है। जैसा मैंने पहले सदन में कहा था, मेरी सरकार का एक कमिटमेंट है कि हम इन्हें प्रोफेशनल प्रोफिटेबल बनाएंगे। आपको याद होगा कि सन् 2016 में भी हमने इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लाया था। हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी।

श्री राकेश सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर से सरकार को बधाई देना चाहूंगा। जिस जर्जर अवस्था में बीएसएनएल और एमटीएनएल सरकार को मिले थे, उसके बावजूद भी उसको लगातार प्रतिस्पर्धा में बनाए रखना और इस स्थिति में ला कर खड़ा करना कि मेरे जैसा व्यक्ति आज भी एमटीएनएल और बीएसएनएल पर ही विश्वास रखे, यह देश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है।

अध्यक्ष जी, सन् 2004 से 2014 तक जब देश में संचार नैटवर्क के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का वातावरण बन रहा था और निजी क्षेत्र की कंपनियां तकनीक के मामले में लगातार अपडेट हो रही थीं, तब बीएसएनएल और एमटीएनएल नई तकनीक और नई प्रबंधन व्यवस्था न मिलने के कारण लगातार पिछड़ रही थीं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसका परिणाम अभी भी दिखाई दे रहा है। जिसके

कारण आज सरकार को कठिनाई हो रही है। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि अब वॉयस का स्थान डेटा ने ले लिया है। डेटा का उपयोग बढ़ाने के लिए या रेवन्यु बढ़ाने के लिए फाइबर टू द होम को अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार की कार्ययोजना क्या है, कृपया स्पष्ट करें।

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष जी, अगर सरकार का यह कमिटमेंट है और सदन के सम्मानित सदस्यों की यह भावना है, अगर इस हाऊस की प्रक्रिया को बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारी देख रहे होंगे तो मैं उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि अच्छा काम कर के इस सदन की अपेक्षाओं के अनुरूप उतरें। जहां तक तकनीक का सवाल है, यह मैं बहुत ही पीड़ा से कहूंगा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को 4जी नहीं मिल पाया। हमने इस रीहैबिलिटेशन में एक फैसला किया है कि सरकार उनको 4जी स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराएगी, ताकि वे तकनीकी रूप से आगे बढ़ पाएं।

जहां तक ऑप्टिकल फाइबर टू द होम की बात है, कभी अलग से विस्तार से सवाल पूछेंगे। हमारा एक भारत नेट का कार्यक्रम चलता है, जिसमें हम देश की सारी ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं। उसमें हमको काफी सफलता मिली है। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि भारत की जो डिजीटल दुनिया है, यह मजबूत भी हो, प्रोफेशनल भी हो, कंज्यूमर्स के हित में भी हो और देश को विकास में भी आगे बढ़ाए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मेरे पास सप्लिमेंटरी प्रश्न पूछने की लंबी सूची रहती है। यह तो सदन को तय करना है, मेरा तो एक सुझाव है कि प्रश्न भी हम बहुत शॉर्ट में टू द पॉइंट पूछें और जवाब भी उतना हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सप्लिमेंट्री लोगों को अलाऊ कर सकें। तब ज्यादा डिबेट हो पाएगी और ज्यादा प्रश्नों की संख्या ले पाएंगे। सदन अगर सहमत हो तो इस पर एक बार विचार करना चाहिए। मेरा मत है कि हम सप्लिमेंटरी भी ज्यादा से ज्यादा पूछ सकें, ज्यादा लोगों का उसमें इनवॉल्वमेंट हो और सभी लोगों का नंबर भी आए। इसलिए मेरा माननीय सदस्यगण से इस सत्र के बाद अगले सत्र में ...(व्यवधान) आप बैठ जाइए। आपको अभी सलाह देने को नहीं कहा था मैंने। जब

आपको सलाह देने के लिए कहूँ, तब देना। अभी मैं सदन से सहमति मांग रहा हूँ। मैं बीएसी के अंदर और सभी राजनैतिक दलों से इसकी चर्चा करूँगा कि सभी दलों के नेता अपने-अपने सदस्यों को इसका फिर अभ्यास करने की कोशिश करें।

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह: महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, लेकिन सही बात यह है कि ईमानदारी पूर्वक माननीय मंत्री जी को यह स्वीकार करना चाहिए कि आज गांवों में और आम लोगों में बीएसएनएल का एक नाम पड़ गया है कि 'भाई साहब नहीं लगेंगे।' 'भाई साहब नहीं लगेंगे', यह आम बात है। कॉल ड्रॉप की अगर सबसे ज्यादा शिकायत किसी नेटवर्क में है, तो वह बीएसएनएल के नेटवर्क में है।...(व्यवधान) एमटीएनएल के नेटवर्क में भी यह शिकायत है। दिल्ली में हम लोगों के पास एमटीएनएल का फोन है, अगर उससे 50 बार फोन लगाते हैं तो मात्र 5 बार फोन लगता है और 5 सेकेंड बात करने के बाद कट जाता है।...(व्यवधान) आप श्री जी की बात कर रहे हैं, तो श्री जी स्पेक्ट्रम सबसे पहला बीएसएनएल को मिला था। श्री जी को शुरू करने में अगर सबसे ज्यादा विलंब किसी ने किया, तो वह बीएसएनएल ने किया। आज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की आपकी योजना है, आप प्रतिस्पर्धा का स्वागत करते हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इस प्रतिस्पर्धा में आपका एमटीएनएल और बीएसएनएल भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहे, इसके लिए आप कौन सा कदम उठा रहे हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, अनुभवी सदस्य राजीव बाबू की पीड़ा को मैं समझता हूँ। मैंने इस बात को कभी अस्वीकार नहीं किया कि कमजोरियाँ हैं और उन्हें सुधारने की जरूरत है।

सर, पीएसयू की एक समस्या रही है, जो मैं सदन के सामने बहुत ईमानदारी से स्वीकार करूँगा कि जब प्राइवेट सेक्टर आए, तो उनसे प्रतिस्पर्धा के लिए जो आउटलुक होना चाहिए, उसमें कमी थी।

राजीव जी, मैं आपको एक बात बहुत विनम्रता से कहूँगा कि जब नेपाल में भूकम्प आता है, कश्मीर में बाढ़ आती है, वहाँ के लोग फँसते हैं, तो फ्री सेवा बीएसएनएल ही देता है, प्राइवेट वाले नहीं देते हैं, यह हमें समझना पड़ेगा।... (व्यवधान) आप मुझे उत्तर देने दीजिए।

महोदय, माननीय सदस्य ने जो एक बात कही, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और होना चाहिए था। क्योंकि यह पूरा डिजिटल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, इसलिए थ्री जी के बाद फोर जी की आवश्यकता थी। अब उनको फोर जी नहीं मिला, उसके कारणों में जाएंगे तो बहुत गंभीर बातें सामने आएंगी। हमने पूरे इस पुनरुत्थान की प्रक्रिया में यह फैसला किया है कि उनको फोर जी भी मिले, उनका वर्क लोड भी कम हो, वे प्रोफेशनल हों, सरकार का उन्हें सहयोग हो। हमें लगता है कि इसके बाद इसका अच्छा नतीजा आएगा।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Thank you very much, Mr. Speaker, Sir. In the last part of the answer, the hon. Minister has stated that 5G services will also be made available to BSNL and MTNL on the same principle followed for allotment of spectrum for 4G services.

Sir, the poorest connectivity is in national capital in Delhi. We are not even getting connectivity especially as far as BSNL is concerned. Can the Government assure that the 4G/5G services will be provided within a stipulated time?

The second part of my supplementary question, Mr. Speaker, Sir, is this. As far as BSNL and MTNL are concerned, there is a custom and tradition that a Telecom Advisory Committee is chaired by the Member of Parliament. Six months have elapsed. So far, the TAC has not been constituted. Formerly, it was being chaired by the Member of Parliament from Lok Sabha. Unfortunately, last time,

you changed the criteria by which it will be rotated by Rajya Sabha and Lok Sabha. In this regard, will an assurance be given in the House because we are representing the constituency? We are directly answerable to the public at large. So kindly give an assurance. Will the Government give an assurance that TAC will be constituted at the earliest in which the Lok Sabha Member will be the permanent Chairman of TAC?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: As far as 5G is concerned, it is an evolving scenario ...(Interruptions) He talked about 5G. Let the technological parameters be concretised. Surely, it will be open also for BSNL.

As far as Delhi experience is concerned, hon. Premchandranji is a very experienced Parliamentarian. I know him for the last so many years. You please also appreciate one problem. Installing a tower in Delhi is very difficult. Earlier I was the Minister of this Department in 2014-19. I had to run so much to get a tower installed in the Reception of the Parliament to improve the connectivity here. Security issues are there; other issues are there. आप जरा शांत रहिए। आप कभी तो शांत रहिए।...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: महोदय, ये आप पर अंगुली उठा रहे हैं।...(व्यवधान)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: ...(Interruptions) I am only explaining. Why is he interrupting? I fail to understand.

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको भी मौका दूँगा।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Therefore, Sir, I am only giving a suggestion that installation of tower also requires a lot of other consultation process. We are working to further improve the installation so that Delhi's network becomes more and more improved. By the way, you should not blame only BSNL. I have always been telling that other operators also need to improve their services for which we are taking meetings with them. ...(*Interruptions*)

As regards the TAC part asked by the hon. Member and which was left out, I must reply to it. We are in the process of finalizing the TAC, but I cannot, as a Minister, discriminate between a Rajya Sabha MP and a Lok Sabha MP. They are also representatives, but I take your point. ...(*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: This is the right of the Lok Sabha. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जो दोबारा खड़े हो रहे हैं, उनका जवाब नहीं देना है।

श्री असादुद्दीन ओवैसी: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि जवाब के दौरान वजीर साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में टॉवर लगाने के लिए कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, मैंने कहा कि स्पीकर साहब पर ऊंगली मत उठाइए, यह मेरा सवाल था, और कुछ नहीं।

माननीय अध्यक्ष: आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैं संसद और अपने अध्यक्ष जी का बहुत ही सम्मान करता हूं इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।

SHRIMATI NUSRAT JAHAN: Thank you, Sir. As we all know the revenue generation of BSNL is degrading and the organisation is getting weakened day-by-day due to non-availability of 4G spectrum. I would like to ask this from the hon. Minister. Has the Government received any request from BSNL Management to allocate 4G spectrum to provide better data services to the consumers? If so, has the Government taken any action in this regard? If not, then why not? Thank you, Sir.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Hon. Speaker, Sir, as I had explained in the earlier part of my reply, in the whole package of reviving BSNL, absence of 4G was itself noted as an important reason for not very satisfactory services. Therefore, the Government is committed to give them proper 4G spectrum also for which a decision has been taken.

(Q. 223)

SHRIMATI PRATIMA MONDAL : Sir, hon. Railway Minister, in his reply, stated that various steps have been taken by the Zonal Railways to curb death of animals while crossing railway track including provision of fencing at isolated locations and Honey bee sound systems have been installed at locations, which are prone to crossing of elephants.

I would like to draw the attention of this House that Jalpaiguri, Darjeeling and Cooch Behar areas in West Bengal have a large wildlife population, and comprise nine forest Divisions. So, I would like to know this from the hon. Railway Minister, through you. Have these areas been fenced and protected? How many of the Honey bee sound systems have been installed? Is any work still left to be done? Thank you, Sir.

SHRI SURESH C. ANGADI : Sir, this is an ongoing process in all the forests throughout the country. The Railways has taken proper care to safeguard the interest of animals including in the wildlife areas mentioned by the hon. Member. I can get the figures from the concerned Zone. मेरे पास अभी फीगर नहीं है। अभी फीगर लेकर I can provide it to the hon. Member.

प्रो. सौगत राय: अध्यक्ष महोदय, वहां रेग्युलर बेसिस पर हाथी मरते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती पूनम महाजन

सेकंड सप्लीमेंटरी

SHRIMATI PRATIMA MONDAL: Sir, though, I have specifically asked with regard to the West Bengal forest areas, I am not satisfied with the answer that you have given.

SHRI SURESH C. ANGADI : I have replied to the query asked by the hon. Member. I had been to the North-East Zone, and I spoke to the General-Manager during my visit over there. They have practically shown to me, in the exhibition, as to how the elephants can be made to stay away from those areas. ...*(Interruptions)* As regards the figures that she has sought from me, I will provide it to her after collecting the same. ...*(Interruptions)*

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि उनका प्रश्न पश्चिम बंगाल के बारे में था और जवाब नहीं मिला, इसलिए वे सेटिसफाइड नहीं हैं।

आप प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इसमें पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नहीं है, इन्होंने पूरे देश के बारे में पूछा है। अभी आपने स्पष्ट जलपाईगुड़ी के बारे में कहा है। देश में सवा लाख किलोमीटर रेलवे लाइनें हैं, सवा लाख किलोमीटर रेलवे लाइनों का डाटा मंत्री जी यहां लाकर पेश नहीं कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* आप आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री जी प्रिपेयर्ड नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री कल्याण बनर्जी: अभी तो मंत्री जी ने जवाब दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री गौरव गोगोई: माननीय सदस्य को अपने क्षेत्र के बारे में पूछने का अधिकार है। ...*(व्यवधान)* अगर प्रिपेयर नहीं हैं तो बोल दीजिए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती पूनम महाजन।

SHRI KALYAN BANERJEE: Why are you so arrogant? ...*(Interruptions)*

SHRIMATI PRATIMA MONDAL: Sir, especially in the winter season, due to smog, visibility is almost nil, which creates problems for the drivers. This is the main reason for such accidents. In order to avoid such accidents, guards are supposed to be present for alerting the drivers to avoid accidents. So, I would like to know how many such cases have been reported. What action has been taken against them?

SHRI SURESH C. ANGADI: In this regard, I would like to state that the Ministry of Railways has been using fog safe devices. Apart from this, railway authorities have made arrangements for the environment staff to sit in the Railway Department. Whenever they come across any information of animals entering the track, automatically by way of the sound system, an alert is made. Fencing and other arrangements have also been made in this regard. Compared to earlier years, accidents involving elephants have come down.

SHRIMATI POONAM MAHAJAN: I will be very quick. As a wildlife enthusiast, I have been working with a lot of NGOs like WTI, Wildlife SOS, and WCT. We have also studied now that to safeguard human lives, we have to work on nature, forest and wildlife because we coexist. Without that, it is not going to work. मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, आपका बहुत अच्छा जवाब आया है। Can we work more with the Forest Department on prevention? When we talk about future planning, can the Forest Department and Railway Department sit together to create a budgetary allocation so that a wildlife corridor can be worked out? We

lost 32,000 animals in train accidents in the last three years. This is what I read in a newspaper report. So, I cannot even confirm it. It is 35,000. Thank you, Kanimozhi ji. But what I am trying to explain here is this. Can we have this kind of future planning where the Forest Department and the Railway Department can work together on the lines of Kana-Pench Corridor of the Ministry of Road Transport & Highways? I hope the Railway Department can do that. Prevention is better than cure. Can we work on prevention with proper budgetary allocations and take it forward?

SHRI SURESH C. ANGADI: The hon. Member has given a very good suggestion. The Ministry of Railways in consultation with the Ministry of Environment has issued an advisory to the Zonal Railways. The advisory prescribes guidelines to the Railways and Forest officials which would help in preventing incidents of animals hit by trains. Already, Railway Department is acting on these lines. Apart from this, as suggested by the hon. Member, with the coordination between the Railways and the members of the local villages, we can do more on this.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: I am happy to know that in the reply the Minister has said that they are planning to construct underpasses and ramps for the movement of wildlife at identified locations. It has worked very well in many countries. Can you give me a list of places where you have already constructed underpasses and ramps and also a list of places where you are planning to do?

SHRI SURESH C. ANGADI: The hon. Member is very much concerned as she also comes from South India. We will send the details to her.

(Q. 224)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह कई बार सदन में दिया जा चुका है कि हाई कोर्ट की बेंच राज्य सरकार की संस्तुति से और संबंधित हाई कोर्ट की संस्तुति से ही बनाई जा सकती है। वर्ष 1955 से उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्य मंत्री संपूर्णानन्द जी ने यह मांग रखी। वर्ष 1976 में हाई कोर्ट की बेंच की मांग की गई। इसके बाद वर्ष 1978, 1979, 1981 में भी हाई कोर्ट की बेंच की चार बार मांग की गई, किंतु हाई कोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार की मांग होना इसलिए मुश्किल है, क्योंकि हाई कोर्ट के वकीलों का अपना इंटरेस्ट है। वे दबाव बना देते हैं और हाई कोर्ट से संस्तुति नहीं आती है। यह बहुत गंभीर विषय है।

माननीय अध्यक्ष : सदन के सभी सदस्य अपने राज्य के लिए हाई कोर्ट की मांग करते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष जी, मेरी मांग है कि इस स्थिति में जब हाई कोर्ट की संस्तुति प्राप्त करना मुश्किल है, आम आदमी या वादी का जो हित है, उसकी रक्षा कैसे की जाए? उत्तर प्रदेश की आबादी उसमें तीन और हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की बात जसवंत सिंह आयोग ने की है। उसके बाद लॉ कमिशन की 230वीं रिपोर्ट में भी पूरे देश में इस प्रकार की बेंचेज की संस्तुति की है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रकार की परिस्थिति में गरीब वादियों के हित की रक्षा किस प्रकार से करेंगे?

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, माननीय सदस्य मेरठ के बहुत ही अनुभवी सांसद हैं और उन्होंने इस विषय को कई बार उठाया है। मैं उनकी भावनाओं और विषय के महत्व को भी समझता हूं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हाई कोर्ट की केवल एक बेंच है और महाराष्ट्र में चार बेंचेज हैं। यह एक पीड़ा की बात है और इसमें वजन है। मैंने पहले भी कहा था कि इसकी एक प्रक्रिया है और सदन को यह जानना जरूरी है कि हाई कोर्ट की एक नई बेंच बनाने के लिए बिलडिंग चाहिए,

जजेज के बंगले चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए। इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। इसके लिए राज्य सरकार का कमिटमेंट चाहिए और प्रिंसिपल हाई कोर्ट की फुल बेंच की रेकमेंडेशन चाहिए। ये दो चीजें अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन मैं सदन में बहुत विनम्रता से कहूंगा कि उनकी बात में वजन है। उत्तर प्रदेश की इस मांग पर चर्चा की आवश्यकता है, लेकिन नई बेंच के लिए इसकी औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा कि अन्य प्रदेशों से भी इसकी मांगें उठी हैं। हमारी नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने सिस्टम की जड़ता को समाप्त करके ऐसे अनेक निर्णय किए हैं, जिनसे आम आदमी को राहत मिली है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या इस विषय के अंदर भी उस जड़ता को समाप्त करते हुए पार्लियामेंट के माध्यम से, सरकार के स्तर पर, सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था की समीक्षा करते हुए, कोई रास्ता निकालने का प्रयास सरकार करेगी? हमारा निवेदन है कि हमें हाई कोर्ट की बेंच चाहिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है कि नई बेंच बनाने में संबंधित हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच की अनुशंसा आवश्यक है। यह एक कानून है। माननीय सदस्य की सलाह है, सुझाव है, इसे देखना पड़ेगा। मैं सदन को एक बात विनम्रता से, और संक्षेप में बताना चाहता हूं कि हर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना का आग्रह आता है। कई बार एक प्रदेश में तीन-तीन, चार-चार जगह आता है। मुझसे भी वकील मिलते हैं। हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हाई कोर्ट की बेंच कहां हो, कैसे हो, यह तो प्रदेश सरकार को तय करना पड़ेगा। यह जानना जरूरी है कि इसमें मेरा काम कानून के रूप में सहयोग करना है।

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, I find that today's hero Minister is Shri Ravi Shankar Prasad, all questions are related to him and he is very smilingly giving answers.

I have only one thing to say. In Calcutta High Court, there are two Circuit Benches, one is at Port Blair and another one is at Jalpaiguri which is newly constituted. Two judges are going to Port Blair and four judges are going to Jalpaiguri. So, six judges are gone. वर्ष 2014 से हम ने आपका कदम-कदम पर साथ दिया है। हम ने नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइन्टमेंट्स कमिशन बिल से आपका कदम-कदम पर साथ दिया है, लेकिन अभी मेरा यह प्रश्न है कि the Supreme Court collegium has also recommended so many names. Many names are pending before you. You are a very erudite person; you are a big-hearted man; and you are also in the practice. You understand the problem. Insofar as Calcutta High Court is concerned, so many names are pending for long. Kindly clear the vent. They should be cleared. Kindly clear it.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, hon. Member is my very esteemed friend and a learned lawyer. I have great regard for him and I really thank him for the kind words he has used. But, I think, he needs to understand that this particular question does not flow from this Question. This Question is related only to the creation of the benches.

As regards appointment process is concerned, he knows there is a collegium of the High Court, of the Supreme Court, and, Sir, I have said it very clearly – and I am repeating on the floor of the House – this Law Minister and this Government will not be a post office. We are also a stakeholder and we will our

convey views in the appointment process. That is what I have to say. But yes, I take your point. We are expediting it. We will look into it.

(Q. 225)

SUSHRI DIYA KUMARI: Hon. Speaker, Sir, through you, I would like to ask a question to the hon. Minister. Through his answer, I have been informed that in Rajasthan, one gauge conversion project of 152 kms. has been included in the previous three budgets. I assume it is the Mavli-Marwar railway line. This railway line passes through five districts of Rajasthan, namely, Pali, Jodhpur, Rajsamand, Chittorgarh, and Udaipur. It connects two regions of Rajasthan, Marwar and Mewar, which are huge tourist destinations. We have also the marble industry there.

It is my request to the hon. Minister if he could let me know when the work will start on this project. There is an issue with the Forest Department. The DPR and alignment are being made and they are going through the process. There has to be some kind of solution to this problem. So, I would like to ask the hon. Minister what is the progress of this project.

SHRI SURESH C. ANGADI : Hon. Speaker, Sir, here, the problem is huge land acquisition, including forest area, and around 10 tunnels and long viaducts will have to be constructed. After examining all the issues, the Railway Board has decided to retain the MG section as a heritage railway tourism center. The Railways has made it a heritage center at present. So, it may not happen at present.

SUSHRI DIYA KUMARI: Sir, that is not a very encouraging answer. I am sorry about that. But since it was sanctioned, and alignment, and DPR are also being made, the heritage line that is going can continue. My suggestion is that the conversion can happen on the same line which is there. They are making alignment and DPR. So, either they can make it there or they can convert the existing line. At present, we are neither here nor there. It is a sanctioned project. For the last three budgets, it is being sanctioned. The people are suffering because of this. It is no fault of theirs.

SHRI SURESH C. ANGADI: Sir, the hon. Member is very much interested for the development of her State. For the broad-gauge line, the alignment will have to be modified, which will be around 40 kms. long, which will be passing through the forest area. The forest clearance is also required. In my State also, there is a big problem of the forest areas. Many projects have not been cleared. Two wildlife sanctuaries named Todgarh Wildlife Sanctuary and Barkhan-Sathu Khera Wildlife Sanctuary are also there. A revised alignment would involve huge land acquisition and other expenditure. Hence, it has been kept as a heritage monument for the Railways. So, it cannot be taken up now.

SHRI GAURAV GOGOI: Hon. Speaker, Sir, we all want our railway projects to be successful. As told by the hon. Minister in his answer, all of these railway projects have a cost item. The CAG report for the year 2017-18 says that the Railways' operating ratio is 98.7% which is quite poor, and had the Ministry of Railways not

received advance payment, the cost would have overrun the revenue. That shows the financial performance of the Railways is quite worrisome. My question to the hon. Minister is: what is the projected operating ratio for this year and for the next three years? We want the financial health of our Railways to be safe and secure under this Government.

THE MINISTER OF RAILWAYS AND MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI PIYUSH GOYAL) : Thank you, hon. Member, for raising this important issue. A lot of people have been wanting to know and I could not respond outside because it is a CAG report and I have to first present its Action Taken Report in the Parliament. But this gives me an opportunity to share with the House that after the implementation of the 7th Pay Commission, the cost on the Railways, particularly for pensions and pay-outs for nearly 12.5 lakh employees of the Railways has shot up in the last three years. The 7th Pay Commission itself has had an impact of over Rs. 22,000 crore on the expenditure of the Railways which is more than 10 per cent of the total revenue that is collected in the Railways. The Railways being a public utility, we try to restrain ourselves from making any significant increases in the passenger fares which also results in huge gross subsidy where the passenger fares do not recover over 43 per cent of the cost that is incurred in providing passenger services. Suburban services in different parts of the country like Kolkata, Mumbai and Hyderabad are in a way daily means of transport for the people of these cities and their significant cost is

under-recovered. Then there are several routes in the North-East, in the State from where the hon. Member comes, which will never show economic viability. There is a social cost. There is social objective of the public utility. We are investing large amounts in the North-East, in the defence regions and in the hilly areas where cost recovery is never going to be possible.

Similarly, there are over 100 aspirational districts all across the country. We have sanctioned and we are implementing several projects which reach out to these aspirational districts. When we collectively look at all of this, ideally this cost should not come in the operating ratio. There is a social cost of running a Government utility as a service to the people of India. Therefore, we should take into consideration the fact that large amounts are being invested in all these social obligations besides the financial impact of the 7th Pay Commission. If one was to look back at the 6th Pay Commission which came probably in 2006, the operating ratio deteriorated by about 15 per cent in one year itself. So, it is a natural phenomenon that happens every time the Pay Commission comes in. Over a period of time, as you are able to increase your revenues, you start improving the operating ratio. But I think the time has also come for the nation to consider whether the social cost should be separately considered as a part of the Budget for which Government also gives budgetary support and the operating ratio should clearly reflect what is the cost of running the efficient portions of the

Railways or the commercial portions of the Railways. The time has come for all of us to reflect how long the Railways will be able to provide good services.

I am sure everybody has experienced the improvement in cleanliness, punctuality, quality of rolling stock, and quality of trains. ...(*Interruptions*) It is an on-going process. It is not going to happen overnight in every train. But the on-going process is clearly evident and visible. ...(*Interruptions*) With the kind of cleanliness that is there on stations, you will never find any dirt or mess. You will find that toilets are working and operational. All of these steps involve a cost which we have to ultimately look at in improving the revenue of the Railways.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: What is the present operating ratio? The present operating ratio also needs to be known.

SHRI PIYUSH GOYAL: Obviously, the operating ratio is calculated at the end of the year.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मैंने आपको माननीय सदस्य का जवाब देने के लिए नहीं कहा है।

...(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : Sir, 24 lakh electors of Sriperumbudur have elected me and sent to this House to find out whether the Avadi-Sriperumbudur-Guduvancheri railway line will ever be constructed. For the past six years the sanctioned project is just lying idle. It seems, in September the Railway Board has instructed the Southern Railway not to proceed with the work on this project. Any shrewd

businessman or professional would have seen its viability and IRR. The IRR of this project is 16 per cent. Generally, a project having 14 per cent IRR is taken up but this project has 16 per cent IRR. Moreover, for the first time the Tamil Nadu Government has agreed to bear 50 per cent of the cost of this project. To apprise my friend, a lot of religious temples fall in this route. Rajiv Gandhi Memorial is there. It is also the birth place of Bhagwan Ramanuja. Three clusters of industry; Oragadam, Sriperumbudur as well as Ambattur, are there. But the hon. Minister is not at all yielding....(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

...(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU: You should know that the people of Tamil Nadu are finding fault with the Modi Government only....(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब आप बैठेंगे, तभी मंत्री जी जवाब देंगे । Please sit down. Please calm down.

...(Interruptions)

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I am very happy to see that the hon. Member has suddenly found a lot of interest in the religious places of Tamil Nadu. It is a very good change that will augur well for the country. Particularly when some people and some Parties are losing their identity with religion, here we have a Party which is now talking about connectivity to religious places. It is a matter of great

satisfaction and happiness for a person like me who is committed to provide connectivity to religious places of all religious denominations.

As regards this particular project is concerned, the hon. Member has suddenly expressed his desire that the project should be implemented quickly. I am sure, the hon. Member recognises that in that particular project the land acquisition has gone through a judicial process because of which the project has got stalled. My Office will be very happy to share the specific details with the hon. Member.

The interesting part of his question was that he is able to work out the IRR of a railway project better than our Department or we are able to work out. Sir, I think, no railway line in the country is showing 16.5 per cent IRR. I would really like to be educated and I am open to learning from you, Sir, as to how that 16.5 per cent IRR has been calculated. If 16.5 per cent IRR is possible in a railway line, especially without carrying any freight because there is no freight traffic on that route, we will be able to make all the railway lines in the country profitable....(*Interruptions*) An hon. Member has alleged that it is an arrogant answer. I have humbly submitted that I would like to be educated how any railway project can give 16.5 per cent IRR. I would love to be educated by you, Sir.

SHRI DAYANIDHI MARAN: You can prove that it is wrong....(*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU : Sir, the hon. Minister has become very argumentative....(*Interruptions*) First of all, he should be polite....(*Interruptions*)

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): You are a very senior leader. We all have a great regard for you.

(Q.226)

SHRI ABDUL KHALEQUE: Hon. Speaker, Sir, the Government has taken various initiatives to attract investments over a period of time. These include, organising investment summits in the States and events to attract investments.

What is the percentage of investments in the North-Eastern region, out of the total FDI inflow in the country since 2000? If it is low in comparison to the national percentage, kindly give the reasons therefor.

Moreover, it is being seen that in certain sectors, the FDI inflow is more compared to others. For various reasons, FDI inflow is also poor in far-off areas like the North-Eastern region, where there is ample scope for growth and development. Has the Government come up with any plan to attract investment in far-off areas? If yes, please lay the plan before the House.

SHRI SOM PRAKASH: As has already been mentioned in the answer itself, the State-wise data on FDI invested is not centrally maintained. It is only at the Central level that the investment has increased. The State-wise data is not centrally maintained.

SHRI ABDUL KHALEQUE: Foreign Direct Investment is coming from various countries across the globe. But there are a few countries from where regular investment is coming into the country. Will the Government inform the House

which are the top five countries from where investment is coming in and their percentage, out of the total investment over the last ten years?

SHRI SOM PRAKASH: The first five countries from where Foreign Direct Investment is coming in are Mauritius, Singapore, Japan, Netherlands and United Kingdom.

SHRI T. N. PRATHAPAN: Hon. Speaker, Sir, the unemployment rate in India is at a 45-year high. Around 20 million Indians are jobless in our country. Five million Indians have lost their jobs in the last two years. If FDI is increasing and if the Make-in-India programme is benefitting everyone, as all of you are claiming, how has the unemployment rate reached this level? Can you provide the data showing employment being generated by FDI and the Make-in-India programme in our country?

THE MINISTER OF RAILWAYS AND MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI PIYUSH GOYAL): We have larger amounts of investment coming in with FDI. We have seen almost 50 per cent increase in FDI in the last five years compared to the previous five years. Obviously, that results in investments, more economic activity and also work opportunities for people, both directly and indirectly, many in the form of jobs and many in the form of the ecosystem that is created around FDI. So, there can be absolutely no hesitation on anybody's part in accepting that job or work is obviously created with FDI. But the country is moving more and more towards entrepreneurship and towards

different areas and avenues of work across the sectors. Take the example of Tourism. Tourism is a sector where you do not literally have job calculations. So many people have become tour operators and so many people have become guides, etc. But it is recognised world-wide that tourism provides a lot of work opportunities for every rupee being invested. The country has seen huge increase in tourism, both domestic and international, in the last few years, which obviously has resulted in employment generation in the country. Almost more than Rs. 6 crore MUDRA loans have been given. So, employment and work are an outcome of not only FDI but also several other factors. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 227 – श्री असादुद्दीन ओवैसी ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट रुकिए । माननीय सदस्य मैं आपको समझाता हूँ । प्रश्न में जो सैकेंड नंबर पर नाम होता है, वे एक ही प्रश्न पूछते हैं । पहले नंबर से दो प्रश्न पूछे जाते हैं ।

...(व्यवधान)

(Q. 227)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, I need your protection in this answer that has been given.

माननीय अध्यक्ष: संरक्षण है न, आपको बुला दिया, आपका नंबर ले आए साथ में।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: सर, और संरक्षण चाहिए। मंत्री जी को मत दीजिए, मुझे दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको ही संरक्षण है।

...(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : In the answer that has been given, the Government is accepting that 355 projects have shown cost overrun. The hon. Minister and the Government are not mentioning the year-wise data. Now, you are in the power for the last nearly six years. Clearly, he is accepting that overall cost overrun is Rs.3.88 lakh crore which comes to 20.07 per cent. Does this not debunk this Government's so called slogan and commitment of minimum government and maximum governance? It has fallen flat. That is why, you see that there is a huge cost overrun which comes to about Rs.3.88 lakh crore. Will the Minister be kind enough to tell us year-wise how many projects have been stalled?

राव इंद्रजीत सिंह: सर, 355 कॉस्ट ओवर रन के प्रोजेक्ट्स का ब्यौरा मैंने जवाब में दिया है। 552 प्रोजेक्ट्स का टाइम ओवर रन है और बोथ टाइम एंड कॉस्ट ओवर रन के 178 प्रोजेक्ट्स हैं। यह वर्ष 2018 का जिक्र है। जनाब ने पूछा है कि क्या आज के दिन हमारी सरकार इन प्रोजेक्ट्स को ठीक ढंग से मॉनीटर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही? मार्च, 2010 से लेकर सितम्बर, 2019 तक का ब्यौरा मैं दे रहा हूँ, जो कि कुल मिलाकर 10 साल का ब्यौरा है।

जब हमारी सरकार सत्तासीन हुई थी, उसके पहले वर्ष 2014 के अंदर कुल प्रोजेक्ट्स देश के अंदर 150 करोड़ रुपये से अक्वल थे, वे 710 थे। उनकी एन्टीसिपेटेड कॉस्ट 9,24,307 करोड़ रुपये थी। इनमें से केवल 454 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे, जो मुकम्मल हो चुके थे। जब से हमारी सरकार सत्तासीन हुई है, उसका जिक्र अगले पाँच साल का, मैं और साथ-साथ देना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 के बाद वर्ष 2015 में हमारी सरकार सत्तासीन हुई तो 751 प्रोजेक्ट्स वर्ष 2015 में लिए और जो मार्च, 2018 है, वह बढ़ते गए। मार्च, 2018 के अंदर 1315 प्रोजेक्ट्स, मार्च, 2019 के अंदर 1405 प्रोजेक्ट्स, यानी कि सितम्बर, 2019 तक कुल मिलाकर 1635 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे, जहाँ पर 150 करोड़ रुपये से अक्वल पैसा भारत सरकार खर्च करने लग रही है। यह 710 से बढ़ कर 1635 हुए, यह प्रो-एक्टिवनैस इस सरकार की दर्शाता है। इनमें से मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि जो मुकम्मल हो चुके हैं, जहाँ वर्ष 2014 तक केवल 454 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए थे, हमारी इस सरकार ने इन पाँच सालों के दौरान 604 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए, जिनकी कुल मिलाकर लागत 7,022,12 करोड़ रुपये है। मैं श्रीमान जी से यह कहना चाहता हूँ कि हमने पिछले वर्षों में प्रो-एक्टिवली काम किया है। यह सरकार प्रो-एक्टिवली काम करने लग रही है। कई वजहें हैं, जिनकी वजह से प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं, जिसके अंदर फोरेस्ट क्लियरेंसेज़, इनवायर्नमेंट क्लियरेंसेज़, विदेशी मुद्रा का भाव बढ़ना, ये सारी चीजें फेक्टर-इन किए जाने के बावजूद, आज के दिन पहली सरकार के बनिस्पत इस सरकार ने अक्वल और बेहतर काम किया है।

SHRI ASADUDDIN OWASI: Will the hon. Minister inform the House how this Government intends to augment its finances on account of increased expenditure on the projects mentioned in his reply? If the delay in projects is because of price inflation and environment clearance, is it not a failure of his Government?

12.00 hrs

RAO INDERJIT SINGH: I have mentioned the reasons for the time overruns. To monitor the projects, the Government has taken an initiative through a project called 'Pragati' which the hon. Prime Minister himself monitors. In this project, the Chief Secretaries of States are on call, the Secretaries of the various Departments are on call. They all sit down together in the presence of the hon. Prime Minister and all the issues of time and cost overruns and all such things are monitored. About 300 projects so far have been monitored which include railways, road transport, highways, power, steel, coal, etc. I think, on the whole, this Government is taking a more serious view of how these projects should be monitored than the previous Government.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर माननीय सदस्यों के स्थगन-प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने किसी भी स्थगन-प्रस्ताव की सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। ...(व्यवधान)

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नं. 2 - श्री श्रीपाद येसो नाईक जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD

YESSO NAIK): Sir, I, on behalf of Shri Rajnath Singh, beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Defence Institute of Advanced Technology, Pune, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (2) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Defence Institute of Advanced Technology, Pune, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1062/17/19]

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): महोदय, मैं भारत के विधि आयोग के प्रतिवेदन संख्या 277-सदोष अभियोजन (न्याय की हानि) विधिक उपचार – अगस्त, 2018 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 1063/17/19]

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND

MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Aluminium Company Limited and the Ministry of Mines for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 1064/17/19]

- (2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (a) (i) Review by the Government of the working of the National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar, for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of the National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1065/17/19]

- (b) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Copper Limited, Kolkata, for the year 2018-2019.

- (ii) Annual Report of the Hindustan Copper Limited, Kolkata, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1066/17/19]

- (c) (i) Review by the Government of the working of the Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur, for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of the Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1067/17/19]

- (d) (i) Review by the Government of the working of the Singareni Collieries Company Limited, Khamman, for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of the Singareni Collieries Company Limited, Khamman, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1068/17/19]

- (e) (i) Review by the Government of the working of the NLC India Limited, Neyveli, and its subsidiary companies NLC Tamilnadu Power Limited and Neyveli Uttar Pradesh Power Limited for the year 2018-2019.

- (ii) Annual Report of the NLC India Limited, Neyveli, and its subsidiary companies NLC Tamilnadu Power Limited and Neyveli Uttar Pradesh Power Limited for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1069/17/19]

- (f) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Gold Mines Limited, Kolar Gold Fields, for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of the Bharat Gold Mines Limited, Kolar Gold Fields, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1070/17/19]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Rock Mechanics, Bengaluru, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Rock Mechanics, Bengaluru, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1071/17/19]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Miners' Health, Kolar Gold Fields, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Miners' Health, Kolar Gold Fields, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1072/17/19]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre, Nagpur, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre, Nagpur, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1073/17/19]

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND
PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE
MINISTRY OF PLANNING (RAO INDERJIT SINGH):** Sir, I beg to lay on the
Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2018-2019.
- (2) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.
- (3) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1074/17/19]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (1) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Electronic Limited, Bengaluru, for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of the Bharat Electronic Limited, Bengaluru, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1075/17/19]

- (2) (i) Review by the Government of the working of the BEL Optronics Devices Limited, Pune, for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of the BEL Optronics Devices Limited, Pune, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1076/17/19]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

- (क) (एक) यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगोड़ा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगोड़ा का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1077/17/19]

- (ख) (एक) इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

- (दो) इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1078/17/19]

- (ग) (एक) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड), मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड), मुंबई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1079/17/19]

- (2) (एक) हरीश-चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) हरीश-चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1080/17/19]

- (3) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1081/17/19]

- (4) (एक) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1082/17/19]

- (6) (एक) सेमी - कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.एस.ए. नगर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) सेमी - कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.एस.ए. नगर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1083/17/19]

- (7) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन) संशोधन नियम, 2019 जो 23 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का.519(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1084/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, I, on behalf of Shri Hardeep Puri, beg to lay on the Table a copy of the Tea Waste (Control) Amendment Order, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.3954(E) in Gazette of India dated 31st October, 2019 under sub-section (3) of Section 49 of the Tea Act, 1953.

[Placed in Library, See No. LT 1085/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, I beg to lay on the Table: -

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Research and Information System for Developing Countries, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Research and Information System for Developing Countries, New Delhi, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1086/17/19]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND
INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH):** Sir, I beg to lay on the Table:

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the India International Convention and Exhibition Centre Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of India International Convention and Exhibition Centre Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1087/17/19]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council for Cement and Building Materials, Ballabgarh, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council for Cement and Building Materials, Ballabgarh, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1088/17/19]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

- (i) Review by the Government of the working of the Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

- (ii) Annual Report of the Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1089/17/19]

- (4) A copy of the Notification No. G.S.R.410(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 6th June, 2019, appointing the 6th June, 2019 as the date on which Section 2 of the Patents (Amendment) Act, 2002 in so far as it amends section 71 of the Patents Act, 1970 shall come into force, issued under Section 160 of the said Act.

- (5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 1090/17/19]

12.02 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

“In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 2nd December, 2019, agreed without any amendment to the Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th November, 2019.”

12.02 ½ hrs**AMENDMENTS TO DIRECTIONS BY THE SPEAKER, LOK SABHA
(DIRECTIONS 27 AND 42) UNDER THE RULES OF PROCEDURE AND
CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I am to lay on the Table a copy of the amendments to Directions (Hindi and English versions) issued by the Speaker under the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

[Placed in Library, See No. LT 1091A/17/19]

12.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

Action Taken Statements

DR. MANOJ RAJORIA (KARAULI-DHOLPUR): Sir, I beg to lay on the Table the following Final Action Taken Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers: -

1. Final Action Statement on the Fifty-second Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the observations/recommendations contained in the Forty-fourth Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Demand for Grants 2018-19' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals).
 2. Final Action Statement on the Fifty-third Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the observations/recommendations contained in the Forty-ninth Report (16th Lok Sabha) on the subject "Assam Gas Cracker project" of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals).
 3. Final Action Statement on the Fifty-fifth Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the observations/recommendations contained in the Forty-sixth Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Promotion and Coordination of Basic, Applied and Other Research in Areas Related to the Pharmaceuticals Sector' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Pharmaceuticals).
-

12.03 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL

1st and 2nd Reports

SHRI RAKESH SINGH (JABALPUR): Sir, I beg to present the following Reports

(Hindi and English versions) of the Standing Committee on Coal and Steel:-

1. First Report on action taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Forty-eighth Report (Sixteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Coal and Steel on the subject, 'CSR Activities in Steel PSUs' relating to Ministry of Steel.
 2. Second Report on the action taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Forty-ninth Report (Sixteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Coal and Steel on the subject, 'CSR Activities by PSUs under Ministry of Mines'.
-

12.04 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 143rd Report of the Standing Committee on Commerce on Action taken by the Government on the recommendations/observations contained in 137th Report of the Committee on 'Trade with Association of South East Asian Nations (ASEAN)' pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, I, on behalf of Shri Hardeep Puri, beg to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 143rd Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in 137th Report of the Committee on 'Trade with Association of South East Asian Nations (ASEAN)' pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry.

[Placed in Library, See No. LT 1091/17/19]

12.05 hrs

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Reported Chinese incursion into the territory of India

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमारे रक्षा मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। मुझे थोड़ा बोलने दीजिए।

सर, मैं एक गम्भीर मुद्दा आज सदन के सामने रखना चाहता हूँ। India is destined to be surrounded by two hostile neighbours, especially Pakistan and China; and they are always posing inimical attitude towards our country. We can change the history but cannot change the geography. We are simply wedged between the two nuclear power nations. इस सदन में सब देखते हैं कि हम बार-बार पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ दुश्मनी करता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है। उसके खिलाफ हम केवल आवाज़ ही नहीं उठाते, बल्कि हमारी फौज लड़ाई लड़ती हैं और कामयाबी हासिल करती हैं। लेकिन, इसके साथ-साथ एक और बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान का मददगार कौन है? आतंकवाद को पाकिस्तान पनाह देता है और पाकिस्तान को पनाह देता है चीन, लेकिन चीन के खिलाफ हमारा रुख संतुलित होता है जबकि पाकिस्तान के खिलाफ हमारा रुख आक्रामक होता है, हमें इसे देखना चाहिए। चीन अंडमान-निकोबार तक जहाज भेजने लगा है और हमारी नेवी उनके पीछे धावा बोलती है।

सर, इस सदन में 19 तारीख को अरुणाचल प्रदेश के एम.पी. तापिर गांव ने एक बड़ा गम्भीर मुद्दा उठाया, जिसे हम सबको देखना चाहिए। उन्होंने इस सदन के अन्दर कहा कि 'ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं हिन्दुस्तान की मीडिया हाउस को यह भी कहना चाहूंगा कि किसी भी इश्यू पर मीडिया का

फोकस नहीं होता। चाइना द्वारा कितनी टेरीटरी पर कब्जा हुआ, यह मैं सदन में रिकॉर्ड पर बताना चाहूंगा।'।

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, आप अपनी बात बोलिए। उन्होंने उठा दिया, सदन ने सुन लिया।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, उन्होंने यह भी कहा कि हम सबको इस विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए।...(व्यवधान)

उन्होंने कहा कि 'सदन में मैं रिकॉर्ड में यह बताना चाहूंगा कि जसवन्त सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो आर्मी में कैप्टेन भी थे, वे जिस जगह पर कैप्टेन थे, वह ऑलमोस्ट चाइना के कब्जे में आ गया। आतु-पुतू दिवांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है। वह भी आ गया।'।

सर, उनका यह दावा है कि 'आज पचास से साठ किलोमीटर से ज्यादा हमारी टेरीटरी पर चाइना ने कब्जा करके रखा है। अपनी सरकार को इस सदन में और मीडिया हाउस को आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।'।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगर आपका कोई विषय हो तो बताएं। तापिर गाव जी यहां बैठे हैं। क्या मैं उन्हें बोलने के लिए इजाजत दे दूँ?

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, इस पर चर्चा होनी चाहिए। विषय यह है। यहां रक्षा मंत्री जी भी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी आवाज़ में जितना आक्रामक रुख रहता है, चाइना के खिलाफ क्यों हमें नरमी बरतनी पड़ती है? यह हम सबको जानकारी मिलनी चाहिए। हम कोई कमजोर देश नहीं हैं। हमारी फौज कमजोर नहीं हैं, लेकिन आपके रवैये में यह फर्क हमें हताश करता है। आपके रवैये, रुख, तेवर में यह फर्क, यह अन्तर हम सबको पीड़ा देता है।...(व्यवधान)

सर, क्या हम चाइना से डरते हैं? अगर नहीं डरते हैं तो हमें खुल्लम-खुल्ला बोलना चाहिए। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय रक्षा मंत्री जी जवाब देंगे, अब आप जवाब सुन लीजिए। आपने पूरा बोल लिया। अब माननीय रक्षा मंत्री जी बोलेंगे।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मुझे बस दस सेकेन्ड का समय दीजिए।

सर, यह मुद्दा हमारे हिन्दुस्तान की आन, बान और शान का है। चाइना हमारे खिलाफ पाकिस्तान को पनाह देता है और चाइना के साथ जो आपका रवैया है, यह रवैया मुझे अच्छा नहीं लगता।...(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, सीमा सुरक्षा को लेकर अधीर रंजन चौधरी जी ने अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन चुनौती जिसे दी जानी चाहिए, उसे चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि सीधे मुझे ही चुनौती दे रहे हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : हम आपको आगाह करना चाहते हैं।

श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सीमा सुरक्षा को लेकर हमारी सेनाएं पूरी तरह से चौकस हैं और पूरी मुस्तैदी से हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। मैं यह भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी सेनाएं किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने में भी पूरी तरह से सक्षम हैं। किसी को इस पर सन्देह नहीं होना चाहिए।

महोदय, इस संबंध में मैं एक डिटेल्ड जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर परसेप्शनल डिफरेंसेज हैं। ये पहले से ही चले आ रहे हैं, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि हमारी सीमा यहां तक है। भारत का कहना है कि हमारी सीमा यहां नहीं है, बल्कि हमारी सीमा यहां पर है। एल.ए.सी को लेकर एक पर्सपेक्शनल डिफरेंसेस हैं, जो दोनों देशों के बीच बहुत पहले से चली आ रही हैं। इसका मूल कारण यह है कि भारत और चीन के मध्य साझा रूप से अंकित कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है, यानी कोई इस प्रकार की वास्तविक एल.ए.सी. नहीं है। भारत-चीन सीमा के साथ लगे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां दोनों पक्षों एवं एल.ए.सी. की अपनी अलग-अलग

अवधारणाएं भी हैं। दोनों पक्षों द्वारा एल.ए.सी. की अपनी-अपनी अवधारणा तक गश्त किए जाने के कारण अतिक्रमण की घटनाएं कभी-कभी हो जाती हैं। इसे मैं स्वीकार करता हूं।

कभी-कभी पी.एल.ए. कुछ भीतर आती है, लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कभी-कभी हमारे लोग भी उधर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : जब ... * ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य की कोई बात अंकित न हो।

... (व्यवधान) *

माननीय अध्यक्ष: माननीय रक्षा मंत्री जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज। इनकी कोई बात अंकित नहीं हुई है।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, अगर उनकी बात अंकित नहीं हुई है, तो उसका उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय रक्षा मंत्री जी, एक मिनट के लिए रुकिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जब कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं आएगी और आप यहां बोलेंगे, तो भी प्रेस में जाने वाली नहीं है। आज गंभीर विषय हो गया कि बिना रिकॉर्ड के कोई बात प्रेस में जाती है तो उसके लिए कई सारे विषय उठ गए हैं। मैंने आपको पूरा विषय बोलने के लिए मौका दिया है, इसलिए आप रक्षा मंत्री की पूरी बात सुन लीजिए।

... (व्यवधान)

* Not recorded.

श्री राजनाथ सिंह: वैसे तो मैं सीमा की सुरक्षा को लेकर अधीर रंजन जी को ही नहीं, बल्कि पूरे सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त कर चुका हूँ। मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उसको लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर एक पर्सनल डिफरेंसेज दोनों देशों के बीच है। कभी-कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है कि पी.एल.ए., यानी जो चाइना की आर्मी है और हमारे भारत की जो आर्मी है, इन दोनों के बीच कभी-कभी कान्फ्रन्टेशन की स्थिति हो जाती है।...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): आप ऑक्साई चीन के बारे में क्या बोलेंगे? ...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह: आप रुक जाइए। ...(व्यवधान) जब कभी कान्फ्रन्टेशन के हालात पैदा होते हैं तो बाद में सभी को इस बात की जानकारी होगी कि कितनी सुझबूझ से दोनों तरफ की सेनाएं अपना परिचय देती हैं और कान्फ्रन्टेशन को कभी एस्कलेट नहीं होने देती है। वहां जो संघर्ष होता है, उसको कभी बढ़ने नहीं देती है। कम से कम इतनी सावधानी बरती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, जब भी इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं तो उनसे निपटने के लिए भारत और चीन के बीच कई प्रकार के मैकनिजम्स हैं, जैसे दोनों सेनाओं के स्थानीय कमांडर्स के बीच पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, फ्लैग मीटिंग्स होती हैं। जो हॉट लाइन है, उससे incursions, transgressions and face-off जैसी स्थितियों को नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, कुछ लॉग टर्म जो इश्यूज हैं, उनको भी डिप्लोमैटिक लेवल पर रिजॉल्व करने का मैकनिजम हमारे पास है, जैसे स्पेशल रिप्रजेन्टेटिव्स टॉक्स होती हैं, उसमें एस.एस.ए. भाग लेते हैं। कभी-कभी वर्किंग मैकनिजम फॉर कन्सल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन होती है, जिसे हम डब्ल्यू.एम.सी.सी. के नाम से जानते हैं। इस स्तर पर भी बात होती है। कभी-कभी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर भी बातचीत होती है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक है। हम लोग समय-समय पर इसकी समीक्षा करते रहते हैं एवं उचित निर्णय भी लेते रहते हैं। भारत-चीन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, टनल, रेलवे लाइन और एयर फील्ड को डेवलप किया जा रहा है। जिससे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके, इसलिए ये सब काम वहां तेजी से हो रहे हैं। इस समय जो भी हालात हैं, मैंने उसकी जानकारी सदन को दी है। मैं पुनः सदन को आश्वासित करना चाहता हूँ कि सीमा सुरक्षा को लेकर किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर): अध्यक्ष महोदय, पंजाब अन्न भंडार और उद्योग क्षेत्र में सारे देश में बहुत बड़ा योगदान देता है। मेरे संसदीय क्षेत्र का उद्योग क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है क्योंकि स्पोर्ट्स, हैंड टुल्स, ऑटो पार्ट्स और लेदर के लिए सारी दुनिया में जालंधर को जाना जाता है। जालंधर का बना हुआ क्रिकेट बैट, हॉकी स्टीक और फुटबॉल आदि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी खेलते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि जीएसटी के कारण पंजाब की इंडस्ट्री को बहुत भारी नुकसान हुआ है। मेरे प्रांत के पच्चीस हजार इंडस्ट्री के यूनिट्स बंद हो चुके हैं। मेरे अपने क्षेत्र में भी बहुत सारे यूनिट्स बंद हो चुके हैं। एक तरफ जीएसटी की वजह से उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ केन्द्र सरकार नॉन-बीजेपी गवर्नमेंट्स के साथ भेदभाव कर रही है क्योंकि अगस्त-सितम्बर से पंजाब सरकार का जीएसटी कम्पनैशंसन चार हजार एक सौ करोड़ रुपये पेन्डिंग है, जो रिलीज नहीं हो रहा है। इससे पंजाब का डे-टु-डे फाइनेन्शियल काम भी रुकता जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरे स्टेट का पेन्डिंग कम्पेनसेशन फौरी तौर पर रिलीज किया जाए।

मेरे क्षेत्र में इंडस्ट्री को बहुत भारी नुकसान हुआ है इसलिए एक हैवी इंडस्ट्री पैकेज जालंधर क्षेत्र को दिया जाए।

श्री निशीथ प्रामाणिक (कूचबिहार): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में लंबे समय से विलंबित एक मुद्दे को उठाना चाहता हूं। यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, यह जरूरत है। इससे कई वर्षों तक राजवंशी लोगों को वंचित रखा गया है।

28 अगस्त, 1949 लेफ्टिनेन्ट कर्नल हिज हाइनेस महाराजा सर जगत दीपेन्द्र नारायण भूप बहादुर एवं तत्कालीन राज्य मंत्रालय के मंत्री वी.पी.मेनन के बीच कूच बिहार का भारत में मिलन के बारे में राजीनामा हुआ था। मिलन के समय कूच बिहार के गौरव के प्रतीक महाराजा की नारायणी सेना

को भारतीय सेना में शामिल करने की बात की गई थी। कूच बिहार के पास तत्कालीन सेना के मूल स्वरूप को न बदलते हुए भारतीय सेना में शामिल किए जाने की बात हुई थी, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद भी संधि के समय किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया। मेरी मांग में कुछ नया नहीं है, जो उस समय वादा किया गया था, मैं उसको अमल में लाने की मांग कर रहा हूँ।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार के रक्षा मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द नारायणी सेना रेजीमेंट की प्रक्रिया शुरू के जाए और बंगाल के सभी युवा को धर्म और जात-पात को भूलकर शामिल होने का मौका दिया जाए।

बंगाल में काफी युवा बेरोजगार है। अगर नारायणी सेना को चालू किया जाए तो युवा को रोजगार के साथ-साथ भारतीय सेना को भी एक मजबूत रेजीमेंट मिलेगी और बंगाल को भी एक नया रेजीमेंट मिलेगा।

इसको सिर्फ एक रोजगार के मुद्दे से मत देखिए, इसके माध्यम से एक बंग इतिहास और कूच बिहार तथा समग्र राजवंशी सम्प्रदाय को आपस में जोड़ने का काम करेगी। आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द नारायणी सेना रेजीमेंट को लेकर उचित और आशा के अनुरूप कदम उठाया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री कृपानाथ मल्लाह, डॉ. राजदीप राय, श्री तापिर गाव, और श्री पल्लब लोचन दास को श्री निशीथ प्रामाणिक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में रोजगार हेतु मल्टी इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक जोन के निर्माण के विषय पर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। आप भारत के किसी भी बड़े शहर में जाएं, वहां आईटी या आईटीएस कंपनी में देखेंगे तो दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और नार्थ ईस्ट के बहुत सारे लोग काम करते हुए मिलेंगे, चाहे गुड़गांव, नोएडा, बंगलुरु, हैदराबाद या पुणे

हो। दार्जिलिंग एक तरह से एजुकेशन हब है। यहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यह क्षेत्र टैलेंटेड युवाओं से भरपूर है, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी की मार काफी समय से चल रही है। पढ़े-लिखे युवा रोजगार की तलाश में परिवार और बूढ़े मां-बाप से दूर शहर की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर हैं। अगर मेरे संसदीय क्षेत्र में सिलीगुड़ी के पास एसईजेड जोन विकसित होता है तो इससे जॉब और एम्पलायमेंट का क्रिएशन होगा और ब्रेन ड्रेन रोका जा सकेगा। यहां भरपूर मात्रा में टैलेंट मौजूद है, यह देश के हित में काम आएगा और वैस्ट बंगाल की खराब आर्थिक स्थिति को सुधारने का मौका मिलेगा। दार्जिलिंग लोक सभा क्षेत्र रेल मार्ग, एयर कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत अच्छा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि एसईजेड जोन सिलीगुड़ी के आसपास विकसित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजू बिष्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): माननीय अध्यक्ष जी, मुम्बई जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहर में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे साई बाबा मंदिर से लेकर गोडबंदर थाणे तक जाता है। यह 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है और 15 लाख की आबादी में मूलन पूर्व, भांडु पूर्व, बिकरौली पूर्व एरिया हैं, जहां पेट्रोल पम्पों की कमी है। इस क्षेत्र में पेट्रोल पम्प की नितांत आवश्यकता है और बड़ी मात्रा में लैण्ड सॉल्ट कमिश्नर के पास है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार अपनी तरफ से प्रयत्न करे कि साल्ट कमिश्नर से लैण्ड का एक्विजिशन करके सरकारी पेट्रोल पम्प का तुरंत निर्माण कराया जाए ताकि इस बड़ी आबादी वाले क्षेत्र में लोगों को राहत मिल सके।

श्री राजबहादुर सिंह (सागर): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा करने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सागर में रेल सेवा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। सागर से नागपुर जाने के लिए ट्रेन की आवश्यकता है। वर्तमान में सागर से सीधे नागपुर की ओर जाने के लिए अभी कोई ट्रेन नहीं है।

नागपुर मेडिकल सुविधाओं के लिए हब के रूप में जाना जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि सागर से सीधी नागपुर के लिए कोई ट्रेन चलाई जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री उदय प्रताप सिंह को श्री राजबहादुर सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुनील बाबूराव मेंढे (भन्डारा-गोंदिया): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान महाराष्ट्र में भन्डारा, जहां वेनगंगा नदी बहती है, के कारण बढ़ते हुए प्रदूषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

हाल ही में मार्च 2019 में ही सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने सर्वेक्षण किया, इसमें 53 नदियां महाराष्ट्र में दूषित पाई गईं। इसमें वेनगंगा नदी भी शामिल है। इस नदी में नागपुर की ओर से सीवेज वाटर, एनटीपीसी और अन्य उद्योगों से इंडस्ट्रियल वाटर मिलता है। इस कारण नदी का काफी पानी प्रदूषित होता है। दूषित पानी में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है। नदी किनारे भन्डारा और अन्य शहरों में बसने वाले गांवों में यही पानी पीने के लिए यूज होता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि नदी को दूषित करने वाले स्रोतों को कम किया जाए। यहां भारी मात्रा में आयरन का उत्खनन होता है, उसमें भी कमी लाई जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री सुनील बाबूराव मेंढे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल (लद्दाख): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लद्दाख में टेली कॉम्युनिकेशन की स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। लद्दाख का बार्डर चीन और पाकिस्तान के साथ लगता है। यहां विलेजेज और हैमलेट्स 350 हैं, जहां मोबाइल और टेली कॉम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है। अब विंटर सीज़न आ रहा है, इस मौसम में यहां 12-15 फीट तक बर्फ होती है। इसमें लोगों के माल-मवेशी दब जाते हैं, पूरा चारागाह खत्म हो जाता है और वहां एक पेशेंट को इवैक्युएट करने के लिए कम्युनिकेशन तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। पिछले साल तक जो 344 डीएसपीटीज चलते थे, वे सारे बंद हो गए हैं। इस बार के विंटर में हम कैसे जीवित रहेंगे इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मैं आपका बताना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र दरास में आज का तापमान -24.8 है। ऐसी दुर्गम स्थिति में लोगों के लिए कम्युनिकेशन का साधन होना बहुत जरूरी है। वहां कमर्शियल वायबिलिटी नहीं होने के कारण प्राइवेट सेक्टर तथा बीएसएनएल का सेटअप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां ऑपरेशनल कॉस्ट हाई है और रिटर्न लेस है। इसलिए मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि युनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंडिंग के तहत पूरे लद्दाख को टेलीकम्युनिकेशन के साथ जोड़ दिया जाए। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ क्योंकि मैंने पिछले पांच महीनों में जितने पत्र भेजे, मुझे सबके जवाब मिले, लेकिन एक्शन बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि पिछले पांच सालों में यूएसओएफ ने लद्दाख को कितना पैसा दिया है- वर्ष 2014 से 2015 और वर्ष 2015-2016 में शून्य, वर्ष 2016 से 2017 में 914000, वर्ष 2017 से 2018 में 134000 तथा वर्ष 2018 से 2019 में 154000। अगर डिपार्टमेंट मुझे बोल देता तो मैं किसी सरपंच से इससे ज्यादा पैसा दिलवा देता। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। सरकार पूरा ध्यान रख रही है, पूरे देश को डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ रही है। लेकिन, डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो इस काम को ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं।

यह शेम की बात नहीं है। अगर मैं यूपीए की स्थिति को बता दूँ तो ये लोग पूरे देश के सामने आ जाएंगे कि इन्होंने क्या किया है। अभी आलोचना करने का समय नहीं है।

डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण जितनी भी सरकार की स्कीम्स हैं, चाहे वह मनरेगा, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, उज्ज्वला योजना, ऑनलाइन टेंडर आदि हैं, वहां ये सारी स्कीम्स ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए, मेरा सरकार से निवेदन है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसको प्रायोरिटी देकर पूरे लद्दाख क्षेत्र को डिजिटल लद्दाख बनाने की कृपा करें। यह मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: फिर हर शून्य काल का माननीय मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा।

श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बस्ती समेत संपूर्ण उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशुओं से होने वाली समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। छुट्टा पशुओं की वजह से विशेषकर किसान भाइयों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे पशु मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाइयों की खरीफ फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों की गाढ़ी कमाई और खून-पसीने की मेहनत बर्बाद हो जाती है। छुट्टा पशु गली-मोहल्ले से लेकर व्यस्त सड़कों तक, विशेषकर हाइवे आदि पर यातयात जाम का कारण बन रहे हैं। इससे राहगीरों को यातायात में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूँ कि छुट्टा पशुओं की समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से निकालने की कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री हरीश द्विवेदी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BALLI DURGA PRASAD RAO (TIRUPATI): Thank you very much for giving me this opportunity to speak on a very important issue in respect of a project in the backward region of Rayalaseema in Andhra Pradesh.

Sir, the NTPC-BHEL Power Projects Limited (NBPPL) project was sanctioned during UPA Government and foundation stone was laid in 2010 by the then Prime Minister, Shri Manmohan Singhji with a promise to provide Rs. 6000 crore and an assurance for creating 6000 direct and about 25,000 indirect employment for the local people.

To my surprise, as of now, the Government could sanction only Rs.100 crore for the project. A piece of land of 753 acres has been allotted to the promoter companies, i.e., NTPC and BHEL by the State Government of Andhra Pradesh. But after the sad demise of my beloved leader and the former Chief Minister of Andhra Pradesh, Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy, this project has been put on the back burner.

The construction of compound wall is already completed. People of my constituency are eagerly looking upon the new Government in Andhra Pradesh. Completion of this project would generate employment for local youth in big way in Venkatagiri, Srikalahasti and Tirupati of Tirupati Parliament Constituency.

The hon. Chief Minister of Andhra Pradesh has also requested several times to the Central Government to provide a new alternative project at the same place, if this project is not going up. Thank you, Sir.

DR. (PROF.) KIRIT PREMJBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Hon. Speaker, Sir, thank you very much for allowing me to raise an important issue regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The issue is regarding the vacancy in the faculty position under reserved category in Central Universities and other universities of national importance, like the IIMs, IITs, and NITs.

At the outset, I would like to thank our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji's Government for having passed the order to fill up the reserved seats in the faculty position across all the IIMs in the country. The Government has rightly identified the poor representation of faculty members belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories in these institutions and has directed them to comply with the reservation rules.

It is very appalling that there are no Scheduled Caste/Scheduled Tribe faculty members in twelve of the top IIMs in the country. Similar situation of very low representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes is prevailing in other universities, like the IITs, NITs and other institutes of national importance. At present, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs make up just six per cent of the total faculty members in the IIMs and nine per cent in IITs.

I would request the Government to continue monitoring this situation and fill up the Scheduled Caste/Scheduled Tribe faculty positions in all these Central Universities and institutes of national importance. The Government should

encourage and provide incentives to youth from Scheduled Caste/Scheduled Tribe community to join doctoral programmes so that they can become professors.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा एवं श्री उदय प्रताप सिंह को डॉ. किरिट पी. सोलंकी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मुंबई शहर की घनी बस्ती है, उसमें रोजाना रेल से सफर करने वाले 75 लाख लोग हैं। ऐसी स्थिति में मुंबई को पूर्व और पश्चिम से जोड़ने वाले सारे ब्रिजेज और पुलों की मरम्मत की बात आती रही है, जो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं। उनमें से बहुत से ब्रिजेज के बारे में रिपोर्ट आई है कि उनकी मरम्मत करनी पड़ेगी या नया ब्रिज बनाना पड़ेगा। इस तरह से वहां यातायात की व्यवस्था बहुत गंभीर हो रही है। रेलवे ने पहले सेंट्रल रेलवे पर एक हैंकॉक ब्रिज था, उसे तुड़वाया, उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अगस्त, 2018 में लोअर परेल का ब्रिज तुड़वाया गया, डिस्मिशन ले लिया, उसके चार-पांच महीने बाद उसे डिस्मैंटल किया गया और अब दिसम्बर, 2019 आ गया है, वहां पर अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है। इसलिए मैं इस शून्य प्रहर में, आपके माध्यम से रेल मंत्री और सरकार से प्रार्थना करता हूं। आगे चलकर दादर के तिलक ब्रिज के बारे में भी गंभीर बातें सामने आ रही हैं, अगर वह ब्रिज टूटा तो बहुत ही गंभीर समस्या निर्मित होगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पहले पर्याप्त व्यवस्था का निर्माण करें, बाद में पुल तोड़ें, जिससे लोगों को तकलीफ न हो।

इसलिए मैं आपके माध्यम से शून्य प्रहर में सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि इस पर ज्यादा गंभीरता से ध्यान दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री राहुल रमेश शेवाले एवं श्री विनायक भाउराव राऊत को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र - सोनीपत और जींद में एक्सीलरेटर्स पास हुए नौ महीने हो गए हैं। उस समय शिलान्यास भी किया गया था, लेकिन आज तक वे नहीं लग सके हैं। उनके लिए फण्ड भी रिलीज हो चुका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी लगवाया जाए ताकि लोगों को, खासकर महिलाओं और हैण्डिकैप्ड लोगों को आसानी हो सके। सोनीपत से लगभग 80 हजार लोग डेली दिल्ली आते हैं। यही मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रमेश चन्द्र कौशिक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती कवीन ओझा (गौहाटी): अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से शून्य काल के अंतर्गत अपने संसदीय क्षेत्र गुवाहाटी (पश्चिम) विधान सभा क्षेत्र से मेघालय बार्डर की लम्बित पड़ी पीएमजीएसवाई सड़क योजना की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। जिमिरगांव से बाखलापारा रोड पैकेज संख्या – एस-॥ 347/419/665, मुदुकी पीडब्ल्यूडी रोड पैकेज संख्या – एस-॥ 242, मातीखार पीडब्ल्यूडी रोड से रानीबारी पैकेज संख्या एस-॥ 249 का कार्य लगभग 80 से 90 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है, परन्तु एक व्यक्ति विशेष द्वारा पीआईएल डालकर भूभाग को विवादित करने के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय से कार्य को रुकवाने का आदेश लाकर पूरे क्षेत्र के नागरिकों के आने जाने को कठिन बना दिया है। इसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र गुवाहाटी पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में लिया गया कार्य दोनों प्रदेशों - असम और मेघालय में विवादित होने के कारण पीएमजीएसवाई का कार्य अब तक रुका हुआ है।

अतः आपके माध्यम से मेरा ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार से आग्रह है कि एक केंद्रीय उच्च स्तरीय समिति का गठन कर माननीय उच्च न्यायालय से रुके कार्य के आदेश को निरस्त कराया

जाए, जिससे रुकी हुई भारत सरकार की असम से मेघालय तक पीएमजीएसवाई सड़क योजना को चालू कराया जा सके।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय देख लें और एक-एक मिनट में अपनी बात पूरी करें।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): अध्यक्ष जी, बुंदेलखंड क्षेत्र एक विशेष संस्कृति वाला क्षेत्र है और वहां की अपनी एक बुंदेली भाषा है। देश में करीब 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलने वाले हैं और इन लोगों में से करीब 12 प्रतिशत लोग बुंदेली भाषा बोलते हैं। भाषा से ही क्रियाओं और विभिन्न संज्ञाओं का ज्ञान होता है और भाषा के द्वारा ही मनुष्य की संवेदनाओं और विचारों को व्यक्त किया जाता है। इस कारण से भारतीय संस्कृति में भाषा पर हर संभव प्रकार से विचार किया गया है। यह उसी का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति के पास साहित्य और भाषा का विपुल भंडार है। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं सहित विश्व की सभी भाषाओं की जननी है। इसके परिणामस्वरूप भारतवर्ष में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं और सैकड़ों भाषाएं तथा बोलियां हैं। इन बोलियों द्वारा ही भारत के पास असीम वैचारिक शक्ति है। संस्कृत की तरह इन भाषाओं के पास भारत के उत्थान और विकास के लिए मार्गदर्शक शक्ति है जिसको और ज्यादा सहजने तथा संवारने की जरूरत है। यदि इनमें कुछ भाषाओं को विशेष संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा, तो नए भारत का निर्माण और तेजी से होगा।

महोदय, मेरी मांग है कि बुंदेलखंड में 'आल्हा' गायन बुंदेली भाषा में होता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा खंड काव्य है जो हजारों वर्षों से आज तक जीवित है। दुनिया के विकसित देशों के हजारों छात्र वहां गाई जा रही वीरता की गाथाओं पर शोध कर रहे हैं। महारानी लक्ष्मी बाई हमारे यहां से आईं। आपने हमेशा सुना होगा – 'बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।' मेरा निवेदन है कि आठवीं अनुसूची में भारत सरकार बुंदेली भाषा को जोड़े, ताकि वहां अपनी भाषा समझने वाले छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च स्तर पर पहुंच सकें और उच्च पदों पर सुशोभित हो सकें।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री अनुराग शर्मा और श्री विनोद सोनकर को कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विजय कुमार (गया): महोदय, हाल ही में समाचार पत्रों में खबर आई कि जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, उन्हें भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। देश के नामी गिरामी सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज करने तथा उन्हें समुचित जानकारी देने की व्यवस्था के अभाव में उन्हें दर-दर भटकना पड़ता है। सरकार ने आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से गरीबों के कल्याण के लिए तथा गंभीर रोगों के इलाज के लिए उन्हें समुचित सुविधा उपलब्ध कराने का प्रभावी कदम उठाया है। इस योजना से लोगों को लाभ भी मिला, लेकिन जानकारी के अभाव में अभी भी लोग इस कार्ड के समुचित लाभ से वंचित हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करें, जिससे इसके लाभार्थी आपात परिस्थिति में सम्पर्क करके उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। इस योजना से एससी, एसटी वर्ग के छोटे हुए व्यक्तियों को जोड़ा जाए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, चूंकि गया संसदीय क्षेत्र के लोग दलित और शोषित समाज से आते हैं। आपने जीरो ऑवर में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान सीएजी की रिपोर्ट, जो दिल्ली सरकार के ऊपर आई है, की ओर दिलाना चाहता हूँ। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दिल्ली सरकार के अधीन जो 18 स्टेट पीएसयूज हैं, उनमें से 13 पीएसयूज में 18,119 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। एक तरफ, जहां उनका रेवेन्यू चार हजार करोड़ रुपये बढ़ा है, जिसमें से भारत सरकार ने उनको 2,184 करोड़ रुपये दिये हैं। जहां उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, वहां पीएसयूज की खराब नीतियों के कारण दिल्ली की जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई मेकैनिज्म बनना चाहिए कि कोई भी सरकार जो अपने वायदे करे, वह उनको कितना पूरा करे, यह कम से कम जनता के बीच में जाना चाहिए। उन्होंने अपनी घोषणाओं में 70 वायदे किए थे। उन्होंने कहा था कि जन लोकपाल बिल बनेगा, नहीं बना। उन्होंने कहा था कि स्वराज बिल बनेगा, नहीं बना। उन्होंने कहा था कि दिल्ली सोलर सिटी बन जाएगी, नहीं बनी। उन्होंने कहा था कि यमुना की सफाई होगी, नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि दो लाख टॉयलेट्स बनेंगे, नहीं बनें। उन्होंने कहा था कि पांच सौ स्कूल्स बनेंगें, एक भी स्कूल नहीं बना, बीस नए कॉलेजेज बनेंगे, एक भी नया कॉलेज नहीं बना, महिला सुरक्षा के लिए फोर्स बनाएंगे, नहीं बनी। यहां तक कि उन्होंने अनऑथराइज्ड कालोनी को पास करने के लिए कहा था, वह भी भारत सरकार ने पास किया है। अगर हम भारत सरकार की बात करें तो हमने अपनी घोषणाओं में कहा था कि धारा 370 हटाएंगे तो धारा 370 हटाई। हम ने कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे तो हमारी सरकार के कार्यकाल में राम मंदिर बना। ऐसा कोई मेकैनिज्म होना चाहिए, जिससे सरकार की ...* घोषणाओं पर रोक लगे।

मैं कहना चाहता हूँ कि आज दिल्ली के मुख्य मंत्री पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। यहां पर 20 सालों में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, चार दिन पहले उन्होंने एक नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी और कल उन्होंने स्किल यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी। केवल घोषणाओं से दिल्ली नहीं चलती, उनको कुछ करके दिखाना चाहिए।

डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं): अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे मिड डे मील के बारे में अनुरोध करना चाहता हूँ कि मिड डे मील सरकारी स्कूलों में शायद इसलिए लाया गया, ताकि गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ कुपोषण से भी बच सकें, लेकिन आज जो मिड डे मील एनजीओ या संस्थाओं के माध्यम से सप्लाई किया जाता है, वे इस पर पानी फेरने का काम कर रही हैं। आए दिन मिड डे मील

* Not recorded.

से संबंधित शिकायतें आती हैं। कहीं पर मिड डे मील के खाने में छिपकली निकलती है, कहीं पर चूहा निकलता है, कहीं पर खाने में कांच निकलता है तो कहीं पर पानी जैसी दाल होती है। कहीं पर एक लीटर दूध में 84 बच्चों को पिलाने की बात होती है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार लगातार कुपोषण जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए 'पोषण पखवाड़े' के माध्यम से लोगों को जागरूक करके कुपोषण से दूर करने का प्रयास कर रही है, वहीं ये संस्थाएं और एनजीओज हमारे इस कार्य पर पानी फेरने का काम कर रही हैं।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी की ऐसे मिड डे मील की संस्थाओं और एनजीओ, जिनको हम टेंडर देते हैं, उनकी पूरी तरह से जांच-पड़ताल करके ही उनको टेंडर दिया जाए, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का सपना साकार हो सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. संघमित्रा मौर्या द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI ABU HASEM KHAN CHOWDHURY (MALDAH A DAKSHIN): Hon. Speaker, through you, I would like to bring to the notice of the Central Government the tragic situation caused due to flood and erosion caused by Ganga River in my Parliamentary Constituency Maldaha this year, particularly, in Maldaha and parts of Murshidabad, particularly Farakka, Shamsheganj and Dhulian.

The erosion caused due to the shift in the course of the river has been causing havoc in the region for past many years on both sides of the Ganga River. However, this year, the situation is extremely problematic, especially, in

Dhulian. Continuous shifting of river course and erosion has introduced vulnerable conditions on physical as well as social environment. The Government of West Bengal does whatever it can but it is not adequate. In the past, the UPA Government decided to take the responsibility of erosion control for 80 km. downstream and 40 km. upstream but that has been given up by this Government.

Through you, Sir, I would like to request the Central Government that work in this regard should be carried out. Otherwise, in the entire area of Dhulian, there would be a terrible catastrophe and it would be very difficult to manage the catastrophe. Repair work has been done in the past by the Farakka Barrage. That is why, I am asking the Central Government to direct the officials of the Farakka Barrage to undertake these activities again.

DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): I would like to bring to the notice of the Government, through you, Sir, that the present economic slowdown has affected the automobile industry heavily in our country particularly Tamil Nadu industries and led to loss of thousands of jobs and also loss of crores of revenue to the Government.

Tamil Nadu is the 'Detroit of India' since 30 per cent of the automobile industries and 35 per cent of the auto components manufacturing industries are having the manufacturing facility in Tamil Nadu. The total automobile and auto components industries are employing more than 30 lakhs people and giving

almost 25 per cent of the State revenue.

In Tamil Nadu, more than 25 automobile OEM's manufacturing plants and more than one lakh MSMEs involved in auto components manufacturing units are facing severe threat of financial losses that force the closure of units and it will lead to social unrest.

Hence, I would like to request the Union Government, through you, Sir, to save MSMEs by taking suitable measures like by reducing the GST for auto components to 18 per cent from 28 per cent; GST rates in engineering job works should be reduced to five per cent from 12 per cent; MSMEs to be declared as a priority sector like agriculture and the interest rates to be fixed between five per cent and six per cent; for the imports of the latest technology machineries, all taxes should be exempted to improve the technology and productivity; and NPA norms for the MSME sector should be increased to 180 days from 90 days.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. ए. चैल्लाकुमार द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

यह सर्वविदित है कि हिमालय में स्थित कैलाश मानसरोवर हिन्दुओं का सर्वोच्च धार्मिक स्थल है, जहाँ कम से कम एक बार यात्रा करने का हर हिन्दू का सपना होता है। परन्तु, दुर्भाग्य से धन की कमी और वहाँ की यात्रा करने के बारे में उचित जानकारी उपलब्ध न होना एक दुःस्वप्न जैसा है। अभी

तक मानसरोवर यात्रा का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसके लिए एक गहन प्रक्रिया और स्वास्थ्य जाँच के बाद एक वर्ष में सिर्फ 960 यात्रियों का चयन किया जाता है। यह यात्रा पुरातन काल से चले आ रहे मार्ग से ही की जाती है, जिसमें कठिन और खतरनाक मार्गों से पैदल ही जाना पड़ता है। इसमें 15 हजार फीट पर स्थित खतरनाक और कठिन लिपु दर्रे से होकर कठिन एवं सीधी चढ़ाई करनी होती है, जिसमें तिब्बत तथा चीन से होकर जाना होता है। इस पर लगभग एक लाख रुपये का खर्च आता है। अन्य मार्ग नेपाल होकर सड़क मार्ग से है, जिस पर वाहन द्वारा यात्रा करने पर एक लाख पचास हजार रुपये से भी ज्यादा खर्च आता है। आम आदमी के लिए इस महान यात्रा पर इतना भारी खर्च उठाना अत्यन्त ही कठिन है। वर्षों से मानसरोवर यात्रा के लिए सरकारी सहायता के लिए समय-समय पर माँग होती रही है, पर केन्द्रीय सरकार ने कभी भी इस माँग पर कोई ध्यान नहीं दिया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ राज्य सरकारें- दिल्ली, गुजरात और राजस्थान सरकार सीमित संख्या में यात्रियों को 25 हजार रुपये की सहायता के अलावा गर्म कपड़े और ट्रेकिंग जूते प्रदान करती हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पर्यटन मंत्रालय इस कार्य में पहल करके सभी मेट्रोपोलिटन शहरों में राज्य सरकारों के सूचना केन्द्र में अलग से कैलाश मानसरोवर विभाग बनाने के निर्देश जारी किए जाएँ, जो यात्रियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए उचित एवं व्यापक जानकारी प्रदान कर सके।

सरकार से मेरी माँग है कि इस दिशा में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाए, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रबंधन और सरकारी सहायता के बारे में विचार करके हिन्दुओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर इस यात्रा को आसान और किफायती बनाने की दिशा में उचित निर्देश जारी करे, जिससे ज्यादा-से-ज्यादा हिन्दू धर्मार्थियों को इस यात्रा का लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष: सर्वश्री अरविंद सावंत, विनायक भाऊराव राऊत, संजय हरिभाऊ जाधव, डॉ. श्रीकांत शिंदे, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और राहुल कस्वां को श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Sir, I rise to speak on a very important issue pertaining to my constituency of Jajpur in the State of Odisha. The issue is regarding the creation of a separate railway division in Jajpur, Odisha.

Sir, Odisha has the maximum resources of almost all minerals from coal to iron and from bauxite to manganese. Odisha is also the highest producer of steel and aluminium in the country. Ninety-eight per cent of chromite in India comes from Jajpur. The Central Government has also declared Kalinga Nagar of Jajpur District, which is one of the largest industrial hubs in Asia, as a National Investment Zone. Thanks to the economic development of the State and the thrust for industrialization by our able State Government. We have significant footprints of noted industries and foreign companies. Besides, the District has also a vast potential for tourism.

Jajpur District has four railway junctions, six goods train sheds and twenty-one stations. The centrality of the District can be understood from the fact that, on the one hand, it is around 100km from the capital city of Bhubaneshwar and, on the other hand, the distance from Paradip and Dhamra port is also more or less same.

Considering the importance, our hon. Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji, has also requested for the same. Sir, Odisha Government has always been supportive of the railway projects and development of railway infrastructure in terms of providing land and other logistics. The commitment of our Government to railway projects stands in excess of Rs. 5000 crore which speaks of our priority to this sector.

Sir, I have elaborated in detail why we need and why we deserve a separate railway division in Jajpur. Through you, Sir, I request the hon. Minister to positively consider our case on priority basis.

SHRI P. K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, recently, the Union Health Ministry has directed the Central Institute Body of all AIIMS to begin the process of review of their tuition fee. The tuition fee of all AIIMS is going to increase. Even the aid given to the important medical colleges by the Central Government is either not given in time or not given at all. If the Government withdraws the aid like this in all types of welfare activities or privatise everything, the medical treatment will become expensive. The medical aid is a primary necessity of the people. Everything would become difficult for the people. The people who depend on AIIMS should get cheap medical treatment. Otherwise, how are they going to get such a good medical treatment. Ninety per cent of our people depend on the Government hospitals. If the Government increases the medical fee of the AIIMS like this, it is going to affect the poor people.

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, the Government of India from 1996 to 2009-10 approved eight irrigation projects under the Accelerated Irrigation Benefit Programme in Odisha, out of which three projects in Ret, Telengiri and Rukura were completed just before these elections. The rest, Subarnarekha, Lower Suktel, Lower Indra, Kanunpur and Anandpur Barrage are just languishing in the dust. The combined original cost of these projects was Rs. 2,698.89 crore. The project cost has increased to Rs. 12,864.18 crore which is of 4.76 per cent escalation. By March 2014, Rs. 6,250 crore had already been spent. However, these irrigation projects are nowhere near completion. The C&AG report has pointed out several times about the unnecessary delay and cost escalation.

Earlier, I had raised the issue of the Lower Suktel Irrigation Project in my constituency. Over the last 15 months, no work has happened there. I had requested Government of India to set up a monitoring Committee to look into the centrally sponsored projects so that the work could be expedited and completed. These projects once completed would go a long way towards mitigation of drought, poverty alleviation, and would also relieve farmers' distress.

There is a problem in many projects where the persons occupying the land have been ousted and the compensation has not been given to the oustees. With your intervention, Sir, I would appeal to the hon. Minister of Jal Shakti to intervene

and hold a review with the officers of the State Government and find a solution to this problem.

Thank you very much, Sir.

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): Sir, would like to express my strong objection against the recent Gazette notification dated 6th November, 2019, which amends the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.

The serial number 23, under schedule K of Drugs and Cosmetics Rules, 1945, contradicts section 42 of the Pharmacy Act 1948 which says, “No person other than a registered pharmacist shall compound, prepare, mix or dispense any medicine on the prescription of medical practitioner”.

The present amendment allows community health officers from nurses to ASHA and Anganwadi workers to prescribe drugs besides pharmacists. This is an important point in this amendment. By allowing people with no professional knowledge about medicines to dispense them, this Government is putting public health at risk.

Pharmacists have earned this privilege by studying intensively about medicines through various pharmacy courses which extend up to six years, which is equivalent to MBBS. At present, there are about 1 million registered pharmacists in our country. Their duty is to dispense medicines so that right medicines reaches the right person. During dispensation, pharmacists do patient counselling through which they come to know about the prescription, dosage,

drugs, etc. Only a person having essential knowledge in preparing and dispensing medicines is capable of doing this. ...(*Interruptions*) Sir, this is a very important matter.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक्स्ट्रा वालो को पढ़कर नहीं बोला जाता है।

...(व्यवधान)

SHRI K. SUDHAKARAN : Sir, I request the Government to withdraw the amendment with immediate effect and take necessary steps to save the patients in our country.

श्री मोहन मण्डावी (कांकेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बस्तर जिले में रेल का अभाव है। धमतरी से कांकेर और कांकेर से कोंडागांव और जगदलपुर को जोड़ने का प्रयास किया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ को बस्तर जिला सबसे ज्यादा आय देता है। आज भी बस्तर के 95 प्रतिशत लोगों ने रेल को नहीं देखा है। वे हमसे यह पूछते हैं कि रेल और ट्रेन में क्या अंतर है? आज लोगों में बहुत विश्वास है कि मेरे आने से और माननीय मोदी जी नेतृत्व में निश्चित रूप से रेल लाइन का विकास होगा।...(व्यवधान)

“देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई,

विपति काल कर सतगुन नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुन एहा।”

माननीय मोदी जी, देने-लेने में कहीं संकोच नहीं करते हैं। लेकिन हमारा बस्तर जिला अभी भी अछूता है।

“दैहिक दैविक भौतिक तापा, मोदी राज, नहिं काहुहि ब्यापा।”

माननीय मोदी जी, के राज में किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस्तर जिले को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। हमारे बस्तर में संसार का सबसे अधिक लोहा होता है।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I am deeply obliged that you have given me the opportunity to speak. Everyone in our country today is very much concerned about the factum of committing rapes all over the country.

Sir, through you, I will request the hon. Minister and our hon. Prime Minister to bring in a legislation prohibiting rape scenes, molestation scenes, and use of vulgar languages in the movies.

13.00 hrs

Similarly, the Government should bring a legislation prohibiting the use of any vulgar words in novels, etc. I would request the hon. Ministers headed by the hon. Prime Minister to think about it.

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती लॉकेट चटर्जी।

आज आपका जन्मदिन है। लेकिन आज आप राज्य के विषय पर मत बोलना। मैंने आपके राज्य विषय को हटा दिया है।

...(व्यवधान)

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): सर, आपको भी जन्मदिन की बधाई। ...(व्यवधान) दादा, आज अध्यक्ष जी का भी जन्म दिन है। ...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: अध्यक्ष जी, आपको जन्मदिन की बधाई । हैप्पी बर्थडे । ...(व्यवधान) आप जीयो हजारों साल । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मेरा तो रोज जन्मदिन रहता है ।

...(व्यवधान)

***SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE:** Respected Speaker Sir, today everybody is highly concerned about the condition of the women in the country, particularly in Hyderabad, and Kalyanji has very rightly raised the issue. He has talked about removing the vulgar dialogues and obscene shots from the movies. Very true. But what pains me more is the fact that when the entire country is fuming against the Hyderabad incident, in our state West Bengal, just near the house of our Chief Minister, two women footpath dwellers were gang raped and nobody talked about that. Why? Because they were from the footpath. They don't get justice, no intellectual stages a protest march for them. Sir, today, in Cooch Behar, Alipurduar mostly the tribal people are being attacked; the Hindu organizations are being attacked. The RSS office-bearer Bir Bahadur Singh has been shot at in Garden Reach, which is known as mini-Pakistan. Infact the Mayor of Kolkata himself had called it mini-Pakistan. The RSS person was shot at in broad daylight just outside a mosque and he is now struggling for his life in hospital. The RSS

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

workers are being intimidated. They are under serious threats. We have grown up under such fear psychosis. We have witnessed the fearful situation during the Left regime; now the same is true with the Trinamool Government. We are used to violence and we are no longer afraid of it. But Sir, I have visited Balurghat myself, I have gone to Birbhum too. Particularly the tribal women are being targeted everywhere. They are raped, killed and their bodies are hushed up in the forests. No justice is meted out to these hapless people. The incident of Park Street is still relevant and there was no justice for that. The rape victim has already died but she did not get any justice. And today the party in power in the state is talking of death penalty for the rapists. How contradictory!

...(Interruptions)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाने का मौका दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद।

सर, सारा सदन जानता है कि 2 अप्रैल, 2018 की जो घटना पूरे देश में घटी, जो एससी एवं एसटी एट्रोसिटीज़ एक्ट को डायलूट किया गया था, उसके विरोध में जो प्रदर्शन हुए थे, उन प्रदर्शनों में कई जानें भी गई थीं। लेकिन उस वक्त केन्द्र सरकार ने और विभिन्न प्रदेशों की सरकारों ने भी यह आश्वासन दिए थे कि जो झूठे मुकदमें दर्ज हुए हैं, वे वापस लिए जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कई राज्यों में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: फिर राज्यों का विषय आ गया।

...(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली: विशेषकर दलितों के जो नौजवान हैं, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। दलितों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। ... (व्यवधान)

کنور دانش علی (امروہ): محترم اسپیکر صاحب آپ نے مجھے ایک بہت ہی اہم مدعہ اُٹھانے کا موقع دیا، اس کے لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

جناب، پورا ایوان جانتا ہے کہ 2 اپریل، 2018 کا جو واقعہ پورے ملک میں پیش آیا، جو ایس۔سی۔، ایس۔ٹی، ایٹروسٹیز ایکٹ کو ڈیلیوٹ کیا گیا تھا، اس کے خلاف جو مظاہرے ہوئے تھے، ان مظاہروں میں کئی جانیں بھی گئیں تھیں۔ لیکن اس وقت مرکزی سرکار نے اور مختلف ریاستوں کی سرکاروں نے بھی یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ جو جھوٹے مقدمات درج ہوئے ہیں، وہ واپس لئے جائیں گے، لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی ریاستوں میں اور خاص طور سے اُتر پردیش میں (مداخلت)۔، خاص کر دلتوں کے جو نو جوان ہیں، ان کو جھوٹے مقدموں میں پھنسایا جا رہا ہے۔ دلتوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔

माननीय अध्यक्ष: राज्यों के विषय नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित होती है।

13.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.03 hrs

The Lok Sabha reassembled at Three Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377

माननीय अध्यक्ष : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

श्री राहुल गांधी।

**(i) Need to start construction work on Nanjangud-Wayanad
-Nilambur rail line**

SHRI RAHUL GANDHI (WAYANAD): The Nanjangud-Wayanad-Nilambur rail line was been a long-held dream of the people of my constituency. Unfortunately, the project has been in the pipeline for several years now. As the you are aware, poor railway connectivity coupled with the night traffic ban on sections of NH-766 has severely reduced mobility and restricted interstate trade and commerce.

Unlocking Wayanad's potential is contingent on improving both intra and inter State connectivity. This project will considerably reduce the travel time between Bangalore and Thiruvananthapuram, and create new opportunities for the people of Wayanad parliamentary constituency. Given the socio-economic

significance of the project, I urge the Government of India to lend all possible support to the Government of Kerala to take up this crucial infrastructure project.

(ii) Need to make Maternity Benefit Scheme more beneficiary friendly

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): The financial assistance to pregnant women was initially provided nationally under the National Food Security Act and now under PM's Maternity Benefit Scheme. The maternity benefit entitlement under NFSA, 2013 is Rs. 6000 per child. But under PM's scheme PMMVY, it was reduced to Rs. 5000 per woman and restricted only to the first living child. A budget provision of Rs. 2,700 crore was made in 2017-18, and Rs. 1200 crore in 2018-19, against the requirement of Rs. 15,000 crore for full implementation of the scheme.

Based on the RTI replies and JABS survey conducted in six states of Northern India revealed that entitlement under PMMVY scheme reaches only one-third of the beneficiaries. Implementation challenges for the scheme are a 23-page application, mother-child protection card, Aadhaar card, husband's Aadhaar card, bank passbook, updated marital home address and the linking of bank account with Aadhar card. Frequent technical glitches in the application and payment process and the lack of effective grievance redressal mechanism discourages the beneficiaries as well.

I urge the Government to make it beneficiary-friendly by adopting best practices in some of already successful maternity benefit schemes like the Tamil Nadu's Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme brought by Dr.

Kalaingar during DMK Government which provides Rs. 18,000 per child for the first two births.

(iii) Need to make Gorakhpur a centre for UPSC examinations

श्री रवि किशन (गोरखपुर): महोदय, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा और सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा वर्ष में दो बार तथा अन्य परीक्षाएँ वर्ष में एक बार आयोजित की जाती हैं। वर्तमान में गोरखपुर को मात्र सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा का ही केन्द्र बनाया जाता है। अभ्यर्थियों को अन्य परीक्षाओं के लिए लखनऊ अथवा प्रयागराज जाना पड़ता है। जैसा कि सरकार अवगत है कि गोरखपुर पूर्वांचल के विद्यार्थियों के लिए प्रमुख शिक्षा का केन्द्र है, जहाँ पर आसपास के करीब 20 जिलों के अतिरिक्त पड़ोसी राज्य बिहार के भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के अतिरिक्त महामना मदनमोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय में भी विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा में ज्ञान अर्जन करते हैं। गोरखपुर, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना का बड़ा केन्द्र होने के कारण बड़ी संख्या में यहाँ सेवारत एवं पूर्व सैनिकों के परिवार भी निवास करते हैं, जो पूर्वांचल के लोगों के लिए सेना में जाने की प्रेरणा प्रदान करता है। वर्तमान में माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार द्वारा महिलाओं को सेना में शामिल होने के अच्छे अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में इस क्षेत्र की महिलाएं सेना में जाने का जज्बा भी दिखा रही हैं।

महोदय, पूर्वांचल की एक बड़ी संख्या अपने जीविकोपार्जन हेतु घर से दूर अन्य प्रदेशों में काम करती है, जिनके लड़के एवं लड़कियां गोरखपुर या पास के नगरों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षा केन्द्र दूर होने के कारण एवं अभिभावक की अनुपस्थिति तथा आर्थिक स्थिति अनुकूल न रहने की वजह से ढेर सारे बच्चे मुख्यतः लड़कियाँ इन परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं।

अतः सदन के माध्यम माननीय मंत्री, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से निवेदन है कि गोरखपुर को संघ लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं का केन्द्र बनाने की कृपा करें। धन्यवाद।

(iv) Need to take steps to revive jute industry in West Bengal

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): West Bengal has always been famous for its jute production. Our State accounts for eighty per cent of the jute produced in India and employs one-fourth of its population in jute mills. Hooghly, the place I belong to, has the maximum concentration of jute mills and is known as the jute belt of West Bengal. I want to bring before this House, the hardships faced by the jute mill workers of not only Gondapara but of West Bengal. The management and the owners of the jute mills are to be held responsible for these hardships. They exploited the workers by giving them dismal wages and increased their working hours long time back before closing the mills down completely and forcing them into unemployment. Neither the owners run the mill nor do they sell it to others. The mills that are running, pay no gratuity or provident funds and the skilled labour are paid less than unskilled labour. Agitation and strikes are common but none of their demands are met. Lack of modernisation and the industry's failure to evolve is also a major reason for closing down of mills. An awareness campaign is also required to promote the eco-friendly jute. I want the Government to take necessary steps to revive the jute industry of West Bengal.

(v) Need to provide employment to locals by public sector undertakings

SHRI DEVUSINH CHAUHAN (KHEDA): I want to bring to your kind notice that in Government PSUs particularly under the Ministry of Petroleum and Natural Gas, no or negligible employment is given to local people. The Government PSUs like ONGC which is doing work in my constituency, Kkedda, Gujarat, came out with a tender, but the contractor is not giving employment to the local people of my constituency or district, whereas it is mandatory to give employment to local people in works. Sometimes the contractor provides petty employment to the local people but after a few days with some excuses the contractor throws out the local people from the work site. The Ministry should look into this grave issue and ONGC may be asked to provide the details of employment it gave to local people in my constituency, grade wise in the last two years and till November, 2019.

**(vi) Regarding establishing two new Indian Reserve Batallions (IRBs)
at Davangere in Karnataka**

SHRI G.M. SIDDESHWAR (DAVANAGERE): I would like to draw the attention of the Union Government towards the need to establish two new Indian Reserve Batallions (IRBs) at Davangere in Karnataka.

माननीय अध्यक्ष: श्री हरीश द्विवेदी - उपस्थित नहीं।

**(vii) Need to revive the closed cotton mill in Etawah Parliamentary
Constituency, Uttar Pradesh**

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र इटावा, उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार के सहयोग से एक सूत मिल इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में केन्द्र सरकार का आर्थिक सहयोग न मिलने के कारण बंद हो गई है।

आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि उक्त बंद पड़ी सूत मिल को पुनः चालू किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर- उपस्थित नहीं।

**(viii) Need to take steps to start construction of
Pune-Ahmednagar-Jalgaon Railway Line**

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पुणे-अहमदनगर-जलगाँव रेलवे लाइन को शीघ्र शुरू करने की दिशा में कदम उठाए जाएं।

(ix) Need to formulate an action plan to weed out '*Vilayati Babul*' in the country, particularly in Rajasthan.

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में एक हानिकारक वनस्पति जिसे विलायती बबूल के नाम से जानते हैं, जिसका लैटिन नाम जूलिस फलूरा है, इस वनस्पति ने धीरे-धीरे पूरे देश को, विशेषकर राजस्थान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिसके कारण पर्यावरण, वन्य जीव जन्तुओं, पेड़-पौधों, उपजाऊ भूमि आदि पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस वनस्पति के संबंध में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि यह वनस्पति हमारी उपजाऊ भूमि को बंजर कर रही है, जिसके कारण इसके आसपास कोई भी पेड़-पौधे नहीं पनपते हैं। इसकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन में 175 फीट तक चली जाती हैं। जिसके कारण धरती का भू-गर्भीय जल काफी नीचे चला जाता है। साथ ही इस वनस्पति की लकड़ी किसी भी उपयोग में नहीं आती है और इस लकड़ी के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। एक तरफ तो माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 30 करोड़ गैस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं, दूसरी तरफ विलायती बबूल, विशेषकर राजस्थान में तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसे दूर-दराज के क्षेत्रों में लोग काटकर जलाने के काम में लेते हैं और यह पेड़ मलेरिया एवं मच्छर जनित अन्य बीमारियों को पनपने में योगदान करता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में मौजूद तत्व मच्छरों के पोषण का कार्य करते हैं।

महोदय, अतः आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस वनस्पति को खत्म करने एवं रोकथाम के लिए यथाशीघ्र एक प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए, ताकि पर्यावरण एवं जल संरक्षण हो सके तथा उपजाऊ भूमि को बंजर होने से बचाया जा सके।

14.19 hrs*(Shri A. Raja in the Chair)*

**(x) Regarding refund of people's money who invested in PACL Limited,
a Pearl Group company**

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, पल्स ग्रुप की पीएसीएल लिमिटेड, जो कि पूरे देश में भूखंड के नाम पर एकमुश्त जमा योजना एवं किस्त भुगतान के माध्यम से कार्य कर रही थी, इस योजना के माध्यम से कंपनी ने देश भर के गरीब, मजदूर, किसानों एवं मध्यम वर्गीय लगभग 6 करोड़ निवेशकों का लगभग 49,100 करोड़ रुपये जमा करवाया था । 21 अगस्त, 2014 को सेबी ने इस कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया था । AISO ने निवेशकों को पैसे वापस दिलाने हेतु उच्चतम न्यायालय में पक्ष रखा । माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 फरवरी, 2016 को कंपनी की संपत्ति को नीलाम करके पैसे देने का आदेश दिया । मेरे संसदीय क्षेत्र के लगभग 2 लाख निवेशकों का पैसा भी इसमें लगा हुआ है । पैसे न मिलने के कारण निवेशक परेशान हैं । अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि PACL कंपनी की चल-अचल संपत्ति को नीलाम करके निवेशकों के जमा धन को वापस दिलाने का कष्ट करें ।

(xi) Regarding building multi-specialty Hospital in Siliguri

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): The districts of Darjeeling, Kalimpong, and North Dinajpur are among the most deprived regions in India. Majority of the people here are dependent on tea garden, farming or collection of Forest Products for their livelihood, and the average family income is only around Rs.6000/month.

Due to low income, people from our region cannot afford treatment in expensive private hospitals, and government run facilities are inadequately equipped and critically understaffed. During my recent visit to the North Bengal Medical College, I was shocked by the general condition of filth and criminal lack of amenities for the patients.

Because of this, our region urgently needs an upgrade in its healthcare system and facilities so that our people won't be forced to travel to Vellore, Delhi and Mumbai for treatment.

Therefore, I request the Union Health Ministry to build at least a 1000-bedded multi-specialty hospital on the lines of AIIMS in Siliguri

(xii) Regarding eviction of families residing near railway property

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The railway authorities issued notice for the eviction of families residing at Thenmala, Aryankavu, Kazhuthuruthy, Punalur etc. The notice was issued to the families residing near by the railway property. The families occupied the land for long period during several generations. The State Government and Revenue authorities are examining their claim for ownership in the aforesaid land. Without considering their legal claims for ownership, the railway is initiating action for eviction that too by not complying with the legal formalities for eviction. The eviction without complying with the legal formalities is against the principle of natural justice. The matter was not considered in its true spirit.

Hence, I urge upon to stop the further proceedings of eviction.

**(xiii) Regarding vaccination for Foot and Mouth Disease (FMD)
in West Bengal**

DR. SUBHAS SARKAR (BANKURA): Foot and Mouth Disease (FMD) is a highly contagious viral disease of cloven—footed animals. In terms of economic impact, it is the most important livestock disease in the world.

As per estimates given by the ICAR (Indian Council of Agricultural Research) the direct financial loss due to disease is estimated at Rs. 20,000 crore per annum.

Therefore, in order to control FMD in the country FMD-CP was taken up by the Government of India.

In West Bengal, in the year 2018-19, only one round of mass vaccination has been done in the month of Sept to Nov, 2018. The second round of vaccination which was scheduled in March, 2019 was not undertaken. For this programme Rs. 2634.94 lakh was released by the Government of India. So, the discontinuity has its impact on the Vaccination done in 2018.

**(xiv) Regarding pending projects of Godda Parliamentary
Constituency, Jharkhand**

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, यह अंग्रेजी में है लेकिन मैंने हिन्दी में बोलने की परमिशन ली है। मेरा लोक सभा क्षेत्र में देवघर है। पर्यटन मंत्रालय ने इसे एक महत्वपूर्ण शहर के तौर पर अपनी लिस्ट में इनक्लूड किया है। धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से यह इतना महत्वपूर्ण है कि 51 शक्तिपीठ और द्वादश ज्योतिर्लिंग देवघर में है इसलिए उसे मनोकामना लिंग भी कहते हैं। प्रत्येक साल वहां पांच करोड़ लोग दर्शन के लिए आते हैं। इस कारण पूरे ईस्टर्न इंडिया की इसे सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और सदन से और खासकर रक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वहां एक स्ट्रेटेजिक डीआरडीओ का सेंटर है, उस सेंटर को बचाने के लिए एक मिलिट्री स्टेशन की बड़ी आवश्यकता है।

मेरी पहली डिमांड है कि देवघर में एक मिलिट्री स्टेशन हो। दूसरा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के कारण डीआरडीओ की एक लैब देवघर में हो। तीसरा, वहां के लोगों को रोजगार नहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक आर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित करे। चौथा, वहां गोड्डा में एक सैनिक स्कूल सैंक्शन है जो अभी तक चालू नहीं हुआ है, वह चालू हो जाए। पांचवां, जब मनोहर पर्रिकर साहब रक्षा मंत्री थे तो वहां डिफेंस रिक्रुटमेंट सेंटर स्थापित करने की बात हुई थी। मेरा इलाका नक्सलवाद और आतंकवाद से ग्रसित है। उस नक्सलवाद और आतंकवाद के कारण वहां के लोगों के विस्थापन और पलायन के चलते वे देश के खिलाफ सोचने को मजबूर हो रहे हैं। मेरा इलाका संथाल परगना एक क्रूरतापूर्ण स्थिति में खड़ा है, जहां के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। They have not only been systematically marginalized, but also cruelly exploited and dispossessed.

Jharkhand Government is more than willing to extend a helping hand for the above mentioned projects. इसलिए आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सभी प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा करे।

**(xv) Need to develop jaigaon in Alipurdwars Parliamentary Constituency,
West Bengal as a Smart City**

श्री जॉन बर्ला (अलीपुरद्वारस): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र अलीपुरद्वारस पश्चिम बंगाल में स्थित जयगांव शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की मांग रखना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित जयगांव शहर हमारे पड़ोसी देश भूटान से लगता हुआ एक छोटा सा शहर है जिसका नाम जयगांव है। व्यवसाय और टूरिज्म दोनों के लिए जयगांव बहुत महत्वपूर्ण है। भूटान के निवासी विभिन्न प्रकार की चीजों की खरीदारी के लिए जयगांव आते हैं। भारतीय पर्यटक भी इसी सीमा से होकर भूटान जाते हैं।

किंतु आज एक तरफ सीमा से उस पार सुंदर और स्वच्छ फूनलोचिंग शहर है, वहीं इस तरफ गदंगी से भरा हमारा जयगांव शहर है। ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है जिससे बरसात के मौसम में पानी हर तरफ भर जाता है और बाढ़ की स्थिति बन जाती है। रास्तों की हालत भी जयगांव में बेहद खराब है। गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है और कूड़ा रास्तों में हर तरफ बिखरा हुआ मिलता है। अस्पताल की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। भूटान संसार का एकमात्र कार्बन निगेटिव देश है। वहां के लोग शहर आते हैं तो हमारे देश के बारे में न जाने क्या सोचते होंगे। जयगांव को स्मार्ट सिटी बनाना देश के सम्मान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

जयगांव में स्मार्ट सिटी बनने से मेरे यहां के चाय बागानों के पिछड़े और गरीब बेरोजगार लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी और वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। वे भी अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे और मेरे क्षेत्र का विकास हो पाएगा।

(xvi) Need to undertake repair of New Delhi-Lucknow National Highway-24 and also construct flyovers at various places in the National Highway

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): माननीय सभापति जी, आपका ध्यान नई दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। इस मार्ग पर जनपद सीतापुर के अंतर्गत महोली रेलवे क्रॉसिंग, कमलापुर, फ्लाईओवर, सिंघौली फ्लाईओवर, अठरिया फ्लाईओवर का निर्माण कार्य नहीं हुआ है जिससे आये दिन सीतापुर में जाम की स्थिति बनी रहती है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग अत्यंत क्षतिग्रस्त भी है।

मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्राथमिकता पर उक्त फ्लाईओवर एवं क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण जनहित में अविलम्ब करने का कष्ट करें।

**(xvii) Need to provide salary, allowances and other facilities
to wardens of 'Nagrik Suraksha Corps' in Uttar Pradesh**

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय सभापति जी, नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों का देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है, परन्तु इसके एवज़ में उत्तर प्रदेश के नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों को सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का ड्यूटी भत्ता, वेतन, मानदेय एवं प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है। भारत के अनेक राज्यों में नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों को यह सुविधाएं प्राप्त होती हैं परन्तु उत्तर प्रदेश में यह अभी तक लागू नहीं हुई है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों का मनोबल बढ़ाने तथा देश सेवा के कार्य के लिए और प्रेरित करने के उद्देश्य से इन्हें ड्यूटी भत्ता, वेतन व मानदेय प्रदान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं तथा उनके लिए स्थानीय स्तर पर होम गार्ड्स जैसी वर्दी भी उपलब्ध करवाएं।

(xviii) Regarding NRC in Assam

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Mr. Chairman, Sir firstly, I wish a very Happy Birthday to hon. Speaker Saheb on his birthday today.

On the 2nd September, 2019, the Ministry of External Affairs stated that ‘The updating of NRC is a statutory, transparent and legal process mandated by the hon. Supreme Court of India.’ The status governing NRC updation are The Citizenship Act, 1955 and The Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, as amended by 1.G.S.R.803 E, dated 9th November, 2009 (with effect from 9/11/2009). The entire exercise was monitored by the hon. Supreme Court.

NRC was executed on the ground by the Centre and State Government. A number of 55,000 State Government employees worked for four years for the updation of NRC.

Sir, Rs. 1,600 crore have been released to the NRC Secretariat so far by the Central Government. This does not include salaries of employees.

The Ministry of External Affairs further stated that, “NRC is a fair process based on scientific methods. Inclusion in the NRC is unique process as it is based on “application” rather than “house to house enumeration”. It can be seen from the application form for data entry in NRC, there was no column in the application asking for religion of the applicant.”

I, therefore, urge the Government that no new exercise should be done in the name of NRC again in Assam. I also urge to issue Gazette notification on the Final List of NRC, which was published on 31.08.2019 and make necessary arrangement to include the names of genuine Indian citizens irrespective of caste, creed and religion whose names were dropped from the final list. Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, I would request you to kindly read the text, which has already been approved. Only this portion will go on record.

(xix) Regarding waste management solutions for Hyderabad

SHRI ANUMULA REVANTH REDDY (MALKAJGIRI): Almost all Indian States are facing the problem of waste management, air and water pollution. It is high time that waste management and pollution control measures are taken on priority basis by the Centre and all the State Governments.

I want to raise my concern over long-term waste management solutions for Hyderabad, which is one of the leading IT cities of the country. Professionals from India and all over the world come and settle in the city. It is important that we have clean water to drink and fresh air to breath.

(xx) Need to boost Indian textile industry

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): The Indian textile industry is the second largest employment generating sector that is giving employment for both skilled and unskilled labourers. India's overall textile exports during financial year 2017-18 is US \$ 39.2 billion and is expected to increase to US \$ 82 billion by 2021. This industry contributed 2 per cent of country's GDP and employs more than 45 million people. The sector contributed 15 per cent to the export earnings of India. The Indian textile industry is expected to become a \$ 300 billion industry by 2030 and it can create additional job opportunities to 35 million people in the country. This can be achieved if the industry enhances its focus on exporting higher value-added products by modernizing with sustainable business practices. The Indian textile industry has the capacity to produce a wide variety of products suitable to different market segments, both within India and across the world.

I would urge upon the Union Ministry of Textiles, through you, Sir, to establish mega apparel cities in port cities of our country, particularly, in Tamil Nadu to increase the production of textiles to compete with the countries like China in textile exports and thereby millions of job opportunities will be created and giving boost to exports. In this respect the Union Ministry of Finance has to cooperate by reducing the GST on synthetic fibers from 18 per cent to 12 per cent, which may increase Indian textile sales in the US market.

(xxi) Need to redress grievances of Fair Price Shop Dealers

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The Fair Price Shop Dealers Federation announced a nation-wide agitation to redress their grievances. They demand Rs. 250 per quintal as margins for rice, wheat & sugar with a minimum guaranteed income of Rs. 30,000- per month for their livelihood.

There is a need to restore kerosene quota and appoint erstwhile kerosene dealers as LPG dealers who have since lost their business on account of some States being declared as Kerosene Free by Government of India in order to ensure their livelihood since they had so far been living solely on Kerosene retail business. Frequent increase of retail kerosene price is forcing the general public to buy the same from open market. This reduces the income of Fair Price Shop dealers. Government has to ensure sufficient supply of pulses and edible oil at Rs. 20 per kg and iodized salt at Rs. 5 per kg, less than market prices to arrest the exorbitant hike in its open market prices. Government's move to privatize PDS may cause exploitation, unemployment and further disaster to the FPS dealers including their loss of business and hunger to them and their respective families. The proposed concept of 'One Nation One Card' will create serious operational complications for many States like West Bengal, Jharkhand and Tamil Nadu, which are making subsidized distribution from their State exchequer. The failure of Direct Benefit Transfer, especially in some States is also causing a lot of

problems to the smooth functioning of Public Distribution System. The Government must intervene in the matter and take corrective steps to redress the grievances of Fair Price Shop dealers.

(xxii) Regarding withdrawing MEIS benefits for spices.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Hon. Chairperson, in August the DGFT issued orders to suspend the duty credits up to 7 per cent under the Merchandise Export from India scheme. The removal of this incentive has come as a rude shock to those dependent on the spice trade for their livelihood.

This will hurt the industry which contributes up to 15 per cent of Andhra Pradesh's GDP and Lakhs of farmers in the State which is the largest producer of spices in the country. Sir, in my own state of AP, weak monsoon rains have led to lower Chili production despite an increase in sowing area.

Sir, Sudden changes cause loss of customers and contracts. Moreover, the produce is exported usually around the month of December which is after the effective date of the order. The Government must also pay heed to international factors.

Therefore, I would like to appeal to the Government to review its decision to withdraw MEIS benefits for spices.

(xxiii) Need to provide compensation to farmers who suffered loss of sugarcane due to flood and unseasonal rains in Maharashtra.

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले): सभापति महोदय, मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि बाढ़ और बेमौसम वर्षा से महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में पर्याप्त आर्थिक सहायता मुआवजे के रूप में प्रदान की जाए।

**(xxiv) Regarding vacancies in Maulana Azad National
Urdu University at Gachibowli, Telangana**

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): The academic and research activities of any institution – it becomes more important when it is an institution of national importance - solely depend on the strength of faculty. And, no institution or university can flourish or its students bring laurels if they do not get proper guidance. This is exactly what is happening in Maulana Azad National Urdu University at Gachibowli in Ranga Reddy district of Telangana which falls within my Parliamentary Constituency.

Sir, you will be shocked if you see the number of faculty vacancies in this university. Out of total 47 sanctioned posts of Professors, 23 posts are lying vacant; out of 95 posts of Associate Professors and 266 Assistant Professors, nearly 90 posts are lying vacant. It means, there are more than 100 vacancies. It is not acceptable to have such huge number of vacancies on academic side because it will cripple the academics and bring disrepute to the institution. I am told that these vacancies are lying since long. Apart from vacancies on the academic side, there are also vacancies in non-teaching staff.

In view of huge vacancies, I request the Minister of HRD to take personal interest and undertake a special recruitment drive and fill in all vacancies within a time-bound manner.

(xxv) Regarding setting up an airport at Rameswaram

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Rameswaram stands for national integration. Daily, a huge number of people all over the country as also from different parts of the world are visiting Rameswaram and Rameswaram comes under my Constituency. Ramanathapuram itself is a famous place from where so many multi-millionaires are doing variety of business all over the world, particularly, in places like Dubai, Saudi Arabia, Hong Kong, Taiwan, Sri Lanka. They play a very important role in the economy of our country. People are doing cotton production business, spices and sea-based product business. The nearest airport to Rameshwaram is Madurai which is 200 kilometres far away. I would urge upon the Government to provide an airport under Regional Air Connectivity Scheme also known as UDAN scheme at my Constituency, which is the need of the hour.

**(xxvi) Need to include 11 communities of Sikkim in the list
of Scheduled Tribes**

SHRI INDRA HANG SUBBA (SIKKIM): Sikkim is geographically small but a beautiful state with population just around 7 lakhs. Sikkim is amongst one of the eight North Eastern States, it is rich in traditions, culture, customs and cuisines like other NE states, which adds a unique feature to the diversity of our nation and we are proud of it.

But nonetheless, there are a number of socio-economic and political issues unresolved and pending since the very inception of its statehood in year 1975. Among other demands, inclusion of 11 left out communities namely Khas (Chhetri, Bahun), Rai, Magar, Gurung, Sanyasi/Giri, Thami, Dewan/Yakkha, Newar, Sunwar/Mukhia, Jogi and Bhujel in the list of Scheduled Tribes have been pending for many years now. Only about 40 percent of people of Sikkim are included in the list of Schedule Tribes. Remaining 60 per cent of them are either categorised as OBC or in General category.

The importance and urgency of including 11 left out communities in the list of Scheduled Tribes lies in the fact that these communities are also socio-educationally backward and economically weak at par with other Scheduled Tribes of Sikkim. All 11 communities belong to Sikkimese of Nepali origin as defined in the Tripartite Agreement signed on 8th May, 1973 and are protected by

371F. It was a historic mistake when all these communities were not included in the list of Scheduled Tribes at par with other tribes of Sikkim.

Therefore, for greater justice and equality, the 11 left out communities be included in the list of Scheduled Tribes under article 342 of the Indian Constitution at the earliest.

(xxvii) Regarding producing artificial meat

SHRIMATI POONAM MAHAJAN (MUMBAI-NORTH-CENTRAL): Producing artificial meat is a great alternative to traditional meat producing and processing methods, which have proven to contribute more towards environmental degradation than most other large-scale industries due to their large amounts of carbon dioxide emissions. Plant and fungal ingredients (in the case of plant-based meat) or meat harvested from cells (in the case of cultivated meat) are used to produce artificial meat. Artificial meat like plant-based meat and cultivated meat has successfully been produced in countries like the USA and Singapore, and companies working in this industry have managed to garner up to \$9 billion dollars in market capital and 20 million euros in funding. Artificial meat, in theory, is a great alternative for a country like India with an abundance of protein-based millets and pulses.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): We would like to understand this subject further because this is a very interesting subject. I think the idea is something very interesting and we can discuss this in the House also.

(xxviii) Need to develop Sant Ravi Das Van Vihar in Basti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती): सभापति महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती, उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय से लगभग 1 कि.मी. दूरी पर स्थित संत रविदास वन विहार पार्क वर्ष 1988 में स्थापित हुआ था। स्थापना काल से ही यह पार्क बस्ती सहित इसके आस-पास के जनपद के लोगों के लिए एक आकर्षण का केन्द्र रहा है। पूर्व में यहां आकर्षक बाल उद्यान, झीलें, फव्वारा, झूला, नौकायन आदि व्यवस्था थी। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों व नदी के घाट पर बसे होने के कारण यहां आने वाले लोगों को स्वच्छ एवं सुन्दर वातावरण प्राप्त होता था। किन्तु महोदय पिछले कुछ वर्षों से यह पार्क अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। पूरा पार्क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में आ चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस पार्क के महत्व को देखते हुए इसे आधुनिक रूप से विकसित कर इसे इसके पुराने स्वरूप में लाने हेतु आवश्यक कार्यवाई करने की कृपा करें।

**(xxix) Need to set up an industrial unit in Nanded Parliamentary
Constituency, Maharashtra**

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़): सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र नांदेड़ जो कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहां श्री गुरु गोविन्द सिंह जी की गुरुता गद्दी, एवं प्रसिद्ध गुरुद्वारा है तथा यहां देश-विदेश से श्रद्धालुओं, व्यापारियों, एवं आमजनों का आवागमन वर्ष भर लगा रहता है।

महोदय, नांदेड़ में तथा आसपास क्षेत्र में कई शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण केन्द्र कॉलेज आदि चल रहे हैं तथा काफी संख्या में यहां विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण करते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि नांदेड़ में एक बड़ी उद्योग ईकाई खोली जाए, ताकि स्थानीय बेरोजगार शिक्षित, उच्च शिक्षित लोगों की स्थानीय रोजगार प्राप्त हो तथा स्थानीय श्रमिकों को भी रोजगार प्राप्त हो। सरकार इसके मद्देनजर एक बड़ा उद्योग नांदेड़ में खोलने हेतु इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाही करने का कष्ट करे।

14.53 hrs

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – 2019-2020

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up the discussion on Voting on Supplementary Demands for Grants for the year 2019-20.

Prof. Saugata Ray has tabled seven cut motions to the Supplementary Demands for Grants. If the hon. Member wants to move his cut motions, he may send a slip at the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions he would like to move.

A list showing the serial number of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case the Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

Motion moved:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2020, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 4, 7, 8, 10, 11, 14 to 17, 19, 20, 22 to 27, 29, 32 to 34, 38, 40 to 44, 46 to 49, 51, 53, 56 to 58, 60 to 62, 64, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 79, 82 to 84, 86, 89 to 91, 93, 94 and 96 to 100 ”

Demands For Supplementary Grants-2019-2020 submitted to the vote of Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of the Supplementary Demand for Grants submitted to the vote of the House			
1	2	3			
	No. and Title of Demand	Revenue	Capital	Total	Page
	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE				
१	1. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare	Voted	0.05	...	0.05 1-2
२	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.01	...	0.01 3
	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY				
३	3. Atomic Energy	Voted	0.01	0.03	0.04 4
४	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)				
५	4. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.02	...	0.02 5-6
	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS				
६	7. Department of Pharmaceuticals	Voted	...	160.00	160.00 7
	MINISTRY OF CIVIL AVIATION				
७	8. Ministry of Civil Aviation	Voted	0.01	...	0.01 8
	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY				
८	10. Department of Commerce	Charged	0.02	...	0.02 9-10
९		Voted	218.03	65.00	283.03
१०	11. Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Voted	400.50	165.00	565.50 11
	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION				
११	14. Department of Consumer Affairs	Voted	0.01	...	0.01 12
१२	15. Department of Food and Public Distribution	Charged	0.01	...	0.01 13
		Voted	0.01	0.02	0.03
	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS				
१३	16. Ministry of Corporate Affairs	Voted	12.85	...	12.85 14
	MINISTRY OF CULTURE				
१४	17. Ministry of Culture	Voted	0.01	0.01	0.02 15
	MINISTRY OF DEFENCE				
१५	19. Defence Services (Revenues)	Voted	2000.00	...	2000.00 16
१६	20. Capital Outlay on Defence Services	Voted	...	0.01	0.01 17
	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION				
१७	22. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	24.08	0.01	24.09 18
	MINISTRY OF EARTH SCIENCES				
१८	23. Ministry of Earth Sciences	Voted	...	0.01	0.01 19

सं. मांगे, 2019-2020-SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

No. and Title of Demand		(रिक्करीड in ₹ crore)			
		राजस्व Revenue	* पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY					
24. Ministry of Electronics and Information Technology	Voted	0.02	...	0.02	20
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
25. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Charged	...	0.29	0.29	21-22
	Voted	0.03	0.02	0.05	
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
26. Ministry of External Affairs	Voted	0.01	0.01	0.02	23
MINISTRY OF FINANCE					
27. Department of Economic Affairs	Voted	13.69	33.97	47.66	24
29. Department of Financial Services	Voted	...	2500.00	2500.00	25
32. Direct Taxes	Voted	...	0.02	0.02	26
33. Indirect Taxes	Voted	...	0.02	0.02	27
34. Indian Audit and Accounts Department	Voted	27.39	...	27.39	28
38. Transfers to States	Charged	1000.00	...	1000.00	29
	Voted	0.01	...	0.01	
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING					
40. Department of Animal Husbandry and Dairying	Voted	0.02	...	0.02	30
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES					
41. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01	...	0.01	31
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
42. Department of Health and Family Welfare	Voted	0.07	0.02	0.09	32-34
43. Department of Health Research	Voted	0.01	...	0.01	35
MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
44. Department of Heavy Industry	Voted	...	0.01	0.01	36
MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
46. Ministry of Home Affairs	Voted	8820.64	...	8820.64	37
47. Cabinet	Voted	0.01	...	0.01	38
48. Police	Voted	3387.48	0.01	3387.49	39
49. Andaman and Nicobar Islands	Voted	0.03	0.01	0.04	40
50. Chandigarh	Charged	...	60.00	60.00	41
51. Dadra and Nagar Haveli	Voted	0.02	5.00	5.02	42
53. Lakshadweep	Voted	0.01	...	0.01	43
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS					
56. Ministry of Housing and Urban Affairs	Charged	9.10	...	9.10	44-45
	Voted	0.02	0.03	0.05	

629

क्र.सं. 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(xxxiii)

No. and Title of Demand		सजस्व Revenue	(ह-करोड़ in ₹ crore)			Page
			पूँजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
MINISTRY OF HUMAN						
RESOURCE DEVELOPMENT						
57. Department of School Education and Literacy	Voted	0.04	...	0.04	46	
58. Department of Higher Education	Voted	0.03	...	0.03	47-48	
MINISTRY OF JAL SHAKTI						
60. Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	0.01	...	0.01	49	
61. Department of Drinking Water and Sanitation	Voted	0.02	...	0.02	50	
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT						
62. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.03	5.10	5.13	51	
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE						
64. Election Commission	Voted	...	6.22	6.22	52	
65. Appropriation - Supreme Court of India	Charged	20.58	...	20.58	53	
MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS						
68. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.01	...	0.01	54	
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY						
69. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.01	60.00	60.01	55	
MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS						
71. Ministry of Parliamentary Affairs	Voted	0.01	...	0.01	56	
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS						
72. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	...	0.02	0.02	57	
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS						
74. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	1000.00	...	1000.00	58	
MINISTRY OF PLANNING						
75. Ministry of Planning	Voted	22.18	...	22.18	59	
THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT						
79. Rajya Sabha	Voted	20.00	...	20.00	60	
MINISTRY OF RAILWAYS						
82. Ministry of Railways	Voted	...	0.01	0.01	61	
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS						
83. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	...	0.02	0.02	62	
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT						
84. Department of Rural Development	Voted	0.06	...	0.06	63	

भारत 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

No. and Title of Demand		(रु. करोड़ in ₹ crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
86. Department of Science and Technology	Voted	54.00	0.01	54.01	64
MINISTRY OF SHIPPING					
89. Ministry of Shipping	Voted	0.05	22.87	22.92	65
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP					
90. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Voted	0.02	50.01	50.03	66
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
91. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	0.03	0.01	0.04	67-68
DEPARTMENT OF SPACE					
93. Department of Space	Voted	0.01	666.00	666.01	69
MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
94. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.01	...	0.01	70
MINISTRY OF TEXTILES					
96. Ministry of Textiles	Voted	0.03	0.01	0.04	71-72
MINISTRY OF TOURISM					
97. Ministry of Tourism	Voted	0.01	...	0.01	73
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
98. Ministry of Tribal Affairs	Charged	185.00	...	185.00	74
	Voted	0.01	0.01	0.02	
MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
99. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.02	5.00	5.02	75
MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
100. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	225.01	...	225.01	76
GRAND TOTAL					
		17441.37	3804.79	21246.16	
	Charged	1214.71	60.29	1275.00	
	Voted	16226.66	3744.50	19971.16	

HON. CHAIRPERSON: Now, the hon. Minister.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I thought you are going to call the hon. Members to speak. Or, are you asking me to speak?

HON. CHAIRPERSON: Dr. Shashi Tharoor.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, this request by the Government is seemingly routine but unfortunately, it masks a dismaying record of economic mismanagement and budgetary failure. The 2019-20 Budget ushered in by this Finance Minister had proposed an expenditure of Rs.27,86,349 crore and in the Supplementary Demands for Grants, she is now seeking approval for a gross expenditure of Rs.21,246 crore more which will be 0.7 per cent increase from the approved Budget. It is not unreasonable. But if we were to look at all of this, the incremental cash outgo in the Supplementary Demands will have to be met through an increase in either borrowings or an increase in revenue.

Now, during the actual debate on the Budget in this House, I had pointed out that that the Government's projections for revenue were unduly optimistic. I am sorry to say and no one likes to do that 'I told you so' but that is exactly what we are seeing today. During the seven months of this new Government, the Government has collected a revenue of Rs.9.3 lakh crore out of the budget estimate of Rs.20.8 lakh crore for the current fiscal year, not counting borrowings.

In seven months, the figure should have been well above 50 per cent of their projections, close to 60 per cent, instead the figure is only at 45 per cent. As I said, I told you so, I am sorry, we were shown a budget which was always based on unrealistic revenue projections.

Now, let me come to the collections under the various components of revenue during this period. Let us look at the Central Government net tax revenue. It is at 41 per cent, that is, Rs.6.8 lakh crore. Corporate tax is at 36 per cent in seven months, income tax is at 43 per cent in seven months, and disinvestment, which is the other possible source of money coming into the Government, is Rs.17,365 crore on 17 per cent of the budgeted target for this fiscal year of Rs.1.05 lakh crore. So, the numbers speak for themselves.

During the presentation of the Budget last time, the Government had mentioned that they would stick to a target of 3.3 per cent for the fiscal deficit. Now, this was always a long shot at best. I must say that every year the Finance Minister's hon. predecessor had also regularly made commitments and failed to meet them. As I pointed out during the Budget debate, late Shri Arun Jaitley, a good friend kept having to adjust the fiscal deficit target every single year that he was the Finance Minister. For another, there was always an assumption of a growth in tax revenue to offset increased Government spending on schemes like PM-Kisan which was conceived in time for the elections.

In the present scenario, even the Finance Minister has admitted to the media that there is a possibility of fiscal slippage in the current fiscal year.

....(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : I have never said it.(*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR: I have been told as a quote from you in the media.

....(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Please give me the source where you are quoting from.(*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR : Okay, I will ask my staff where it has come from.

....(*Interruptions*). But there will be a slippage, Madam.(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: No, I am sorry.(*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR: Okay, we will get the exact quote.(*Interruptions*) I believe your exact quote is 'difficult to maintain fiscal discipline'.(*Interruptions*)

But let me put it in my words, you will have a slippage in your fiscal deficit this year.(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: It is alright.(*Interruptions*) Don't put your words into my mouth.(*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR : That is my argument.(*Interruptions*) But I think you will have to readjust your figure as your predecessor has had to do. That is, unfortunately, the reality we are facing today.

Now, on the economic conditions under which the supplementary demands are coming in – we all know that the traditional economic wisdom dictates that the GDP of the country will grow only if the key contributors to it such as investment, manufacturing, consumption and exports expand. But here we have a peculiar situation where all of these are going down and have in fact hit rock bottom, but the Government still believes that it can sell the idea of a five trillion-dollar economy without offering us a roadmap of exactly how this will happen. At least, the Prime Minister keeps talking about five trillion-dollar GDP, but the hon. Nishikant Dubey believes that GDP is not important and I am not sure who is the more reputed economist amongst the two of them. But the fact is that the GDP growth rate in the most recent quarter has been considerably lower than such fevered fantasies at a tepid 4.5 per cent, the sixth consecutive quarter of slowing growth. The new figures represent a stunning decline. The country's GDP was growing by more than 9 per cent at the start of 2016, a legacy of the Manmohan Singh years, and today 4.5 per cent has become the new normal.

With GDP growth at a 16-year low, unemployment at a 46-year high, household consumption at a 4-decade low, with bad loans and rising number of non-performing assets, we are also witnessing an all time high in terms of a drop in private investment. If we look at unemployment today, it is 7.48 per cent in November. The labour participation rate is the lowest it has been in recent memory and, in fact, the unemployment rate has touched a 3-year high in October

of 8.45 per cent. In rural areas, it has doubled from the 2013-14 fiscal year to 2017-18 fiscal year. There has been an over 50 per cent increase in unemployment in many sectors in the urban areas and urban males in particular have suffered.

15.00 hrs

As per a working paper published by the Azim Premji University, we have seen nine million people losing jobs between 2012 and 2018. That is an average of about a couple of millions a year between this crucial period that the BJP was largely in power. This clearly calls for remedial measures under the Supplementary Demands for Grants to do something about employment generation, but these are not forthcoming.

Instead, what do we have? We have salaries for police and Armed Forces under which the Government proposes to spend Rs. 3,387 crore to pay salaries and the cost of rations for the police and Rs. 2,000 crore for payment of salaries and allowances for the Armed Forces, but Supplementary Demands for Grants are meant for expenditures that could not have been anticipated in the regular Budget, but these are standard exercises. These salaries and ration costs have not gone up since the Budget was approved. Why was this not anticipated, instead of coming back to us four months after the Budget was approved?

If you look at the situation that we are seeing in the country, the National Statistical Office tells us that rural poverty has risen nearly four percentage points to 30 per cent and that given the size of the rural population, the overall estimated poverty rate has gone up nearly a percentage point to 23 per cent which means, it is simple mathematics, that about 30 million people have fallen behind or below the India's official poverty line in the last six years that the BJP has been in power. They have presided over increasing poverty where 30 million people, who were above the poverty line, have fallen below it.

With growing unemployment and increasing poverty, surely, the one thing the Minister could have thought about in her Supplementary Demands for Grants would have been more allocations for the MGNREGS because there, we are facing a situation in which many people – I think, MPs have already complained during Question Hour – working in the Scheme have not been given their salaries. I have met workers in my constituency who have not been paid their MGNREGS wages for seven months.

15.02 hrs

(Shri P.V. Midhun Reddy *in the Chair*)

In this situation, the Union Budget as well as the Supplementary Demands for Grants have ignored issues of social security and employment. They have shown no intention of boosting rural India's needs. It was a disappointment, of course, for 13 crore rural households that are dependent on MGNREGS. The 2019-20 Budget has a lower figure than the revised estimate for the previous

fiscal. In 2018-19, Rs. 61,084 crore were allocated and this year, only Rs. 60,000 crore have been allocated. After reducing the budget from one year to the next, nothing has been added in the Supplementary Demands for Grants.

Sir, this is incomprehensible because in fact all experts have said that for this Scheme to work and benefit the intended targets, you cannot do it for less than Rs. 88,000 crore. The Centre had to allocate Supplementary Budgets for three straight years after original allocations were exhausted in the first few months of the respective financial years because the workers need the jobs, but those allocations in the past were delayed, people did not get their wages on time, work slowed down and nobody got the guaranteed 100 days of employment under MGNREGS under BJP rule. On top of that, I see that in the fiscal year 2018, below 50 days of employment was provided on average at the all India level. In these circumstances, surely, what we need is more Supplementary Demand for MGNREGS so that people can get their wages on time.

By the way, 78 per cent of all MGNREGS wages have been paid late. What is more is that they have not been paying compensation for delayed payments. These are the people who need this money from their employment to be able to live, but they are not being given their money by this Government. Unfortunately, the last figure I have is of 2017 fiscal where Rs. 11,000 crore in wages were unpaid by the Central Government. In the first two quarters of 2017-18, 32 per cent of the payments were all that was made. An activist filed an RTI that

revealed that in the fiscal year 2018, there were 13.17 crore people registered under MGNREGS, but only 5.73 crore workers sought work and 5.1 were given work, with the result that obviously the Government was not spending the money it should have been spending. I would have said that this was a missed opportunity to increase the allotments to the MGNREGS in order to benefit people who are getting increasingly poor with the passage of time.

Coming back to the question of the Government's challenges, where will the revenue come from? It is not going to come from manufacturing because the manufacturing growth rate has now been so subdued. We all know that for our economic growth to reach the kinds of levels we once used to routinely take for granted, our manufacturing sector would need to grow in double digits. Instead it has seen a very subdued rate of growth around three per cent for the last five years, from 2.8 per cent in fact to 4.6 per cent averaging just about three per cent. The Indian automobile sector is in a disastrous shape. It has seen worst-ever half-yearly performance. Two-wheeler sector is plummeting, registering a major dip. Auto components, which, I think, the Finance Minister's own State was leading the country in manufacturing, has seen a dip of 22 per cent. So, the result is we are looking at the worst figures in the automobile sector in the last two decades. This is the crisis we are facing.

At the same time, revenue is not going to come from consumer spending because consumer spending fell for the first time in more than four decades.

Every year, for each of the last forty years our consumers have been spending more. Especially after MNREGA came and rural demand went up, people had more purchasing power in the rural areas. All that has gone. We have seen a decline for the first time in forty years, according to the latest Consumption Expenditure Survey by the National Statistical Office. What we are seeing is that the average amount of money spent by an Indian in a month has fallen by 3.7 per cent. What is shocking is that there appears to be a dip in food consumption, including on essential food items. The most disconcerting fact to economists has been that this is the first time this has happened in decades. The former Planning Commission Member, Shri Abhijit Sen said that the fall in food spending especially in villages shows that malnutrition has increased. It would be fair to say that poverty has increased significantly. But there are, as I said, no new welfare schemes envisaged in the Supplementary Demands for Grants by the hon. Finance Minister.

What does the Government wish to spend the money on? We are told that allocations for the new Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are going to get Rs. 8,821 crore. We all know that it has been nearly four months since on the 5th of August the Home Minister introduced the Jammu and Kashmir (Reorganisation) Bill in the Upper House of Parliament. Since that time our own citizens, our own political leaders, one of our own Members has been living under a clamp down, living in detention. In the absence of any return to normalcy in

Kashmir, these allocations to the areas would mean very little. We know that 30 political leaders were kept under detention, some of them in solitary, including a former Minister of State in the Government of Shri Vajpayee, a former Chief Minister in the coalition Government with the BJP and a currently serving MP. What are we seeing? These people as well as other leaders are being shunted from one location to another. There have been allegations of manhandling by the police. Meanwhile, terrorism keeps going up. According to the Government's own data provided here by the MoS, Ministry of Home Affairs, cross border infiltration along the Line of Control has gone up by almost 50 per cent since the provisions of Article 370 were abrogated and Kashmir was put under lockdown. So, with all the attempts of infiltrations that have been reported in this House, with tourism going down – our own Prime Minister said to the youth of Kashmir, 'Go for tourism and not terrorism' – with communications lockdown and loss of income for telephone companies, with on-line merchants not able to sell their Kashmiri handicrafts and goods to the world because there is no internet, we are looking at a situation in which Jammu and Kashmir is in dire straits and routine supplementary expenditures are not going to help.

I will make a mention about the missing allocations and then I will conclude. I have already mentioned about MNREGA. Fisheries is an important issue. There has been a repeated demand from the Members of the coastal areas for additional funding for our coastal areas. There is a rampant coastal erosion.

There have been severe climatic attacks on our country. We have heard about cyclone Ockhi, and we have heard about cyclone Gaja in Odisha. There have been floods in many parts of our country. Kerala suffered terrible floods in August 2018 and 2019.

We are shocked that the Government broke its campaign promise of creating a dedicated fisheries Ministry for this area. But the very least they can do is to have a focus on the needs of our coastal communities, particularly our fishing communities to provide a comprehensive economic package to offset the losses they are suffering from cyclones, floods, coastal erosion and strengthen their coastal sea walls. This could have been easily allocated on the supplementary Demand for Grants, but it has not.

For instance, in my own constituency, we have a premier hospital which used to give free service to the poor.

HON. CHAIRPERSON: Tharoorji, please conclude now.

DR. SHASHI THAROOR : The name of the hospital is Sree Chitra Tirunal Institute and the Government is apparently giving so little money now that they have to charge poor people for services in their hospital which used to be free until 1st of December.

So, this Government is trying to pinch pennies at the expense of the Aam Admi, poor persons of this country but it is not actually doing anything to help the larger picture.

Let me stress whether we grow at 9 per cent, as we once did in the UPA regime, or at 4.5 per cent as we are now growing today, the fact is that our fundamental commitment must be to the bottom 25 per cent of our society. This Government has sadly been pushing more and more people below the poverty line without addressing it.

They have talked about new India ...(*Interruptions*) I am going to conclude. I just want to stress that you must have new India that both promotes high economic growth whether some Members believe that GDP matters or not. Clearly, you need higher economic growth. But please ensure that the benefits of this growth are enjoyed by the poor and disadvantaged sections of our society.

The truth is, as our former Prime Minister said, you need trust in society to create a healthy economy. That also needs to be restored.

HON. CHAIRPERSON: Tharoorji, please conclude now. There are eight speakers from your party.

DR. SHASHI THAROOR : All this requires a vision which is sadly missing from the original Budget and is still absent in the supplementary Demand for Grants.

I just want to conclude by saying that it is time for the Government to correct course and steer this country in the right direction which, it has not been doing in the economy all this time. Thank you.

690

337

TEXT OF CUT MOTIONS

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I beg to move

(TOKEN)

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF
ATOMIC ENERGY (PAGE 4) BE REDUCED BY RS. 100.

1. Need to start power generation from Bhartiya Nabhikiya Vidut Nigam Limited (BHAVINI) immediately. (1)

(TOKEN)

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF
COMMERCE (PAGE 9) BE REDUCED BY RS. 100.

2. Need to keep intact the present infrastructure and staff strength at Tea Board, Kolkata. (2)
3. Need to increase intake of students in the Indian Institute of Foreign Trade. (3)

(TOKEN)

THAT THE DEMAND UNDER THE MINISTRY OF CORPORATE
AFFAIRS (PAGE 14) BE REDUCED BY RS. 100.

4. Need to jettison National Financial Reporting Authority. (4)

(TOKEN)

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEFENCE SERVICES
(REVENUE) (PAGE 16) BE REDUCED BY RS. 100.

5. Need to implement one rank one pension scheme for the Army fully. (5)

(TOKEN)

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT
OF FINANCIAL SERVICES (PAGE 25) BE REDUCED
BY RS. 100.

6. Need to tackle non performing assets in IDBI bank. (6)

(TOKEN)

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD MINISTRY OF HOME
AFFAIRS (PAGE 37) BE REDUCED BY RS. 100.

7. Need to end shut down of internet in the Union Territory of Jammu and Kashmir. (7)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मेरा नाम उन्होंने अपने भाषण में लिया है और यह मेरा राइट है कि मैं रिप्लाय करूँ। ... (व्यवधान) सर, उस दिन मैंने अपने भाषण के दौरान दो लोगों को कोट किया था। एक सन् 1934 में साइमन कटले, जिन्होंने कि जीडीपी बनाया था। दूसरा यह रिपोर्ट कोट की थी। उन्होंने कहा कि कौन इकोनॉमिस्ट है, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ कि प्रधान मंत्री इकोनॉमिस्ट हैं या मिस्टर थरूर इकोनॉमिस्ट हैं, यह पूरा देश तय करेगा। यह रिपोर्ट है - रिपोर्ट बाय द कमीशन ऑन द मेज़रमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। फ्रांस के राष्ट्रपति सरकारजी ने सन् 2008 में एक कमेटी बनाई थी। सर, यह नया, लेटेस्ट है। उसमें प्रो. जोसेफ एफ. स्टिगी, जिनको इकोनॉमिक्स का नोबल प्राइज़ मिला था, प्रो. अर्मित्य सेन, जो कि कांग्रेस के बड़े नज़दीकी माने जाते हैं, उनको इकोनॉमिक्स का नोबल प्राइज़ मिला और प्रो. जीन पॉल। उसमें जो सदस्य थे, यह पूरी दुनिया को जानने वाला विषय है - बीना अग्रवाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, केनेग जे. एरो, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, एंथनी एटकिंसन, वॉर्डन ऑफ नफील्ड कॉलेज के, बेंग्सन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, ... (व्यवधान) सुनिए, उन्होंने मेरा नाम लिया है। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Let him conclude.

डॉ. निशिकांत दुबे: यह मेरा राइट है। ... (व्यवधान) इसके बाद रॉजर थे, कॉलेज दे फ्रांस के, शिकागो यूनिवर्सिटी ... (व्यवधान) अण्डर द रूल - 352 व 353 यह मेरा राइट है। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nishikantji, please be very brief.

डॉ. निशिकांत दुबे: मैं कह रहा हूँ कि ये सारे इकोनॉमिस्ट्स हैं - हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, प्रिन्स्टन के, कोलंबिया के, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इन्होंने यह रिपोर्ट दी है। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Okay, make your point and conclude.

डॉ. निशिकांत दुबे: दूसरा, सन् 2018 में ओएसीडी कंट्रीज़ ने । ... (व्यवधान) Under Rules 252 and 253, I have every right to defer.

HON. CHAIRPERSON: Nishikantji, please conclude note.

डॉ. निशिकांत दुबे: उसके बाद ओएसीडी ने ठीक इसी तरह का जॉसेफ स्टील, जिसकी यह कमेटी की रिपोर्ट है, उसने यह कहा । ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Your point is taken.

डॉ. निशिकांत दुबे: उसका जो रिक्मेंडेशन नंबर 6 और 7 है । ... (व्यवधान) मैं पॉइंट यह कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जीडीपी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, चाहे वह यूएन जहां कि मिस्टर थरूर काम करते थे, 2011 में 192 में देशों की बैठक हुई और उन देशों ने एक प्लेज लिया कि जीडीपी के पूरे मापदंड को बदलने के बारे में हमको सोचना चाहिए । ... (व्यवधान) गांव, गरीब, किसान तक यह जा रहा है कि नहीं जा रहा है । ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, this debate is going nowhere.

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): निशिकांत जी को अपनी बात रखने का अधिकार है । ये क्यों पीड़ित हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं । ... (व्यवधान) आपने बोला, उन्होंने जवाब दिया । अब आप बैठिए । आप मेरी बात सुनिए । पढ़े-लिखे आदमी के बारे में आप इस तरह की टिप्पणी कीजिएगा । ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Tharoor, please take your seat.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You have made your point, and he has made his point. Please let the debate go on.

... (Interruptions)

श्री राजीव प्रताप रूडी: सर, यह जो रिसर्च टीम का संकट है... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Rudy, please do not divert into all these things. Please go ahead with your speech.

... (*Interruptions*)

श्री राजीव प्रताप रूडी: सर, मेरे 47 सैकेंड कम कर दिए जाएं, टाइम वेस्ट हो गया। उसको ज़ीरो कर दिया जाए।

HON. CHAIRPERSON: I can extend it. Please go ahead.

... (*Interruptions*)

श्री राजीव प्रताप रूडी: ऐसे थोड़े ना होगा। एक मिनट तो ये लेकर चले गए। हमारे मित्र ने इतने तर्क दिए, इतने आंकड़े दिए कि मैं अपने भाषण के पहले थोड़ा कंप्यूज्ड हो गया। मैं आपके माध्यम से सामान्य रूप से देश की जनता को भी सम्बोधित करूँगा और इस सदन में जो सरकार की वित्तीय व्यवस्था है, उसके बारे में चर्चा करूँगा। भारत में इस बार का जो बजट पेश हुआ, वह लगभग 28 लाख करोड़ रुपये का हुआ, जिसमें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है- डिफेंस। उसमें हम लोगों ने सवा चार लाख करोड़ रुपये दिए हैं। अपने फौजियों के लिए हम इतना पैसा रखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सरकार आगे भी देने के लिए हमेशा तैयार है। प्रमुख रूप से कई सारे बजट थे, जिस पर हम लोगों ने कंज्यूमर अफेयर्स में लगभग दो लाख करोड़ रुपये, एग्रीकल्चर में 1.38 लाख करोड़ रुपये दिए, जिसमें 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रूरल डेवलपमेंट में 1.19 लाख करोड़ रुपये, होम में 1.19 लाख करोड़ रुपये, एचआरडी में 94 हजार करोड़ रुपये, रोड सेक्टर में 83 हजार करोड़ रुपये, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में 80 हजार करोड़ रुपये, रेलवेज में 68 हजार करोड़ रुपये, जिसमें लगभग 23 फीसदी की वृद्धि हुई थी। यह सिलसिला बड़ा लम्बा है। सरकार ने सोच कर इतना बड़ा बजट बनाया।

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में 48 हजार करोड़ रुपये, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में 42 हजार करोड़ रुपये, जिसमें 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अदर्स में 13 लाख करोड़ रुपये है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 8.7 लाख करोड़ रुपये और सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स में 3.31 लाख करोड़ रुपये है। इसमें मूल रूप से देखा गया है कि भारत की सरकार और प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, जिन विषयों पर हम लोगों ने प्रायोरिटी की है, उसमें पीएम किसान योजना एक बड़ी योजना है, जिसके लिए 75 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। उस विषय पर मैं आगे आऊँगा, किस तरह से किसानों के पास पैसा जा रहा है। शायद यह विश्लेषण का अभाव इनको दिख रहा है। मनरेगा में 7 हजार करोड़ रुपये, ये बार-बार कह रहे हैं कि मनरेगा में पैसा नहीं पहुँच रहा है, कम हो रहा है, पता नहीं किस देहात में रहते हैं, कहां रहते हैं। हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है।...(व्यवधान) पता नहीं कहां से ये है, लेकिन मैं चर्चा राजनीतिक रूप से नहीं कर रहा हूँ। नेशनल एजुकेशन में वृद्धि 38 हजार करोड़ रुपये, हेल्थ मिशन में 33 हजार करोड़ रुपये, आईसीडीएस के बारे में कल स्मृति ईरानी जी बोल रही थी, हमारी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बच्चों के कुपोषण की एक बड़ी लड़ाई भारत में लड़ी जा रही है। इसके लिए कितना पैसा जा रहा है। शायद यह सब प्रतिपक्ष के मित्रों की परिभाषा है। पानी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सदन में पानी के लिए, मुझे लगता है कि इस पूरे सत्र में और पिछले सत्र में अगर बार-बार किसी विषय पर सांसदों ने चर्चा की तो मैंने गिनती कराई। 543 में से 283 सांसदों ने किसी न किसी मुद्दे पर पीने के पानी के संकट के बारे में कहा और सरकार ने उसमें लगभग 10 हजार करोड़ रुपये अलग से डाल दिए हैं, जिसमें 81 प्रतिशत की वृद्धि है। ये आंकड़े इसलिए जानना जरूरी है कि सरकार किस तरह से देश में काम कर रही है।

महोदय, अब वर्ष 2019-20 की जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं, जिसको स्वीकृत करने के लिए हम यहां आए हैं, इसमें लगभग 21 हजार करोड़ रुपये, सरकार ने कुछ पैसे बचा लिए और अपना काम कर लिया। इस बार के बजट में हम जो स्वीकृति करेंगे, वह लगभग 18 हजार करोड़ रुपये के आस-पास

है। उसमें जो मुख्य मुद्दे हैं- वह रीकेपिटलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कम्पनीज 2500 करोड़ रुपये, इसमें पैसा एक बड़ा महत्वपूर्ण है। लगभग साढ़े 8 हजार करोड़ रुपये एमएचए के लिए है, मैं उस पर लौट कर आऊंगा। पुलिस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सिंग, उसका राशन, उसकी तनख्वाह में वृद्धि, ये बड़ी फौज है, पूरे भारतवर्ष में पैरामिलिट्री फोर्सिंग की अलग भूमिका है। देश की सरकार ने उन पर ध्यान दिया है और उनके लिए लगभग 37 हजार करोड़ रुपये हैं।

अंतरिक्ष की बात- दुनिया में अगर अंतरिक्ष की बात करते हैं, सदन में स्पीकर साहब ने अंतरिक्ष की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। देश के प्रधान मंत्री जी ने कई बार चर्चा की। पूरे भारत को गर्व है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया में अमरीका, चीन, रूस के बाद अपना स्थान रखते हैं। उसमें लगभग 650 करोड़ रुपये है। ट्राइबल मिनिस्ट्री के लिए छोटा सा है, लेकिन पैसे की जरूरत हुई, हमने 185 करोड़ रुपये और बढ़ा दिये। अब तो ओलंपिक्स में भी जाने वाले हैं, हमारे मंत्री जी को पैसे की जरूरत थी, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हजार करोड़ रुपये, तो लगभग ऐसे क्षेत्रों में इस बार के बजट में हमने परिवर्तन किया है। यह जो 8 हजार करोड़ रुपया गया है, उसमें मुख्य रूप से एक राज्य के बारे में हम लोगों ने पैसा दिया है, हम सब लोगों का उसका कमिटेमेंट है। 14वें वित्त आयोग के माध्यम से केंद्र का कितना पैसा राज्यों में जाना चाहिए, केन्द्र-शासित प्रदेशों को कितने पैसे जाने चाहिए और इसमें जम्मू-कश्मीर के हिस्से में लगभग 8 हजार करोड़ रुपया आया। यह 8 हजार करोड़ रुपया सिर्फ अभी है।

महोदय, कश्मीर के बारे में यह जो निर्णय हम लोगों ने, इस सदन ने लिया, क्योंकि शशि थरूर साहब कुछ कह रहे थे, वे बाहर ही चले गए, लेकिन सरकार ने तो योजना बनाई है, चाहे यह धारा 370 हटाते या नहीं हटाते, लेकिन उसके पहले भी सरकार ने लगभग 80 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं की स्वीकृति का मन जम्मू-कश्मीर में बनाया था। जिसमें से लगभग 63 प्रोजेक्ट चलने हैं या चलने के क्रम में हैं। मूल रूप से उसमें ट्रांसपोर्ट है, पीएम्स पैकेज फॉर लद्दाख, कारगिल एंड जम्मू और कश्मीर, हम सब लोग जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, कारगिल से शुरू करते हैं। मैं हर शब्द में जोड़ूंगा कि लद्दाख

पहले, कारगिल पहले और जम्मू-कश्मीर हमारा अंग है, हमारे साथ है। उसमें जल जीवन मिशन है, रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसके लिए बड़ी योजना है। उड़ान की भी योजना है, जो देश में फोर्थ फेज में जाएगा, वह कश्मीर में जाएगा। हम स्नो लेपेड की बात करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं, शायद दुनिया का अद्भुत जानवर वह होगा, हम लेह, लद्दाख, कारगिल में उतरकर स्नो लेपेड को देख लें। उस इलाके की जो भव्यता है, हमें भी वहाँ जाने का मौका मिला, कोश्यारी जी, जो यहाँ नहीं हैं, पहले हमारे साथ सांसद थे, वे हमारे साथ कमेटी में वहाँ गए थे, हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान, जो उस लद्दाख के क्षेत्र में है, उसकी खूबसूरती का अंदाजा पूरे भारत को नहीं है। हम तो जा भी नहीं पाते हैं, हम तो जा भी नहीं सकते थे, वहाँ तो परमिट की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। लेह, लद्दाख और कारगिल के क्षेत्र की बहुत बड़ी ताकत है। एक युद्ध में उसकी ख्याति बढ़ी। वहाँ पर भी हवाई सेवा प्रारम्भ करने के लिए प्रधान मंत्री जी ने वित्त मंत्री जी को सलाह दी और जो फोकस एरियाज हैं, उस पर सरकार कान्सन्ट्रेंट कर रही है। इस विषय पर हम आगे चलकर बताएंगे।

महोदय, 15वें वित्त आयोग की कार्य अवधि बढ़ा दी गई है। उसे अक्टूबर, सितम्बर में अपनी रिपोर्ट देनी थी।...(व्यवधान) 5-6 महीने के लिए उसकी कार्य अवधि बढ़ा दी गई है। देखिए, सरकार हमेशा सोचकर कुछ काम करती है और जब धारा 370 हटी है, तो उसके लाभ क्या हैं, वह तो पूरे देश ने देखा है। अब हमारे लिए बहुत जरूरी है कि 8 हजार करोड़ रुपये तो दें, लेकिन जम्मू-कश्मीर को हमें और भी बहुत कुछ देना है। इसलिए उसकी कार्य अवधि बढ़ा दी गई है। एन.के. सिंह साहब उसके अध्यक्ष हैं। मुझे विश्वास है कि यह 15वां वित्त आयोग यह तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक राज्यों को, कहाँ-कहाँ कितने-कितने पैसे जाने हैं, कितना किसे मिलना है। कश्मीर की प्राथमिकता के कारण उसकी कार्य अवधि को बढ़ाया गया है।...(व्यवधान) एक साल बढ़ाया है। जब भी हो, लेकिन मूल रूप से कश्मीर के कारण उसे बढ़ाया गया है। So that funds flow to the States and the UTs. Ladakh, Kargil, and Jammu & Kashmir remain very special to us. It is. वह स्पेशल

स्टेट्स हटा दें। It is special to the nation; it is special to the House, and special to all of us. More special, after Article 370 has been removed. वह हमारे लिए, भारत के लिए सबसे बड़ा महत्व है। It will be on par with other States rather it would be much better than other States. This is the commitment; this is the commitment of the Prime Minister; and this is the commitment of the House. मैं फिर से दोहराना चाहूँगा और सदन में सब लोगों ने बोला है, मैं भी फिर से बताऊँगा कि हम लोगों ने जम्मू-कश्मीर को उस वोट की राजनीति से बाहर किया है। उस राज्य में भ्रष्टाचार का एक बड़ा स्वरूप था, उससे उसे बचाया और बाहर किया। उस राज्य की राजनीति या धर्म का जो सिंबल था, उससे उसे बचाकर बाहर किया। कास्ट, क्रीब, कलर और ओरिजिन पर जो डिस्क्रिमिनेशन था, हम लोगों ने सदन में निर्णय लेकर उससे उसको बचाया और बाहर किया। यह एक अस्थायी प्रोविजन था, जिसे समाप्त किया गया। 70 साल बाद यह निर्णय हमारे सदन ने किया। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह बताने में गर्व होगा। हमारे बच्चे हमारे बारे में यह कहेंगे कि उस सरकार में वह सदस्य आप थे, जिन्होंने इस बड़े निर्णय में भाग लिया। हमारे जाने के बाद भी इतिहास इसे याद रखेगा और हम सब उसके भाग हैं।

महोदय, जैसे जमीन की बात है। मैं सोच रहा था कि कैसे सरकार का कोई निर्णय जमीन की कीमतों को बढ़ाता है। वर्ष 2001 में मैं इसी सदन में बैठता था। माननीय राजनाथ सिंह जी यहां पर सड़क एवं परिवहन मंत्री थे। मैंने उनसे कहा कि मेरे क्षेत्र में छपरा से मुजफ्फरपुर तक एक सड़क है, उस सड़क की स्थिति बहुत खराब है, उसे राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित कर दीजिए और मैं जम्मू-कश्मीर के संदर्भ से इसे जोड़ना चाहता हूँ। माननीय राजनाथ सिंह ने उसे घोषित कर दिया। वर्ष 2001 की घोषणा के बाद वर्ष 2015 में उस राष्ट्रीय उच्च पथ का निर्माण हुआ, जो लगभग 100 किलोमीटर का है। जिस सड़क के किनारे की जमीन की कीमत जहां पहले 5,000 रुपये प्रति कट्ठा थी, आज उस जमीन की कीमत पाँच लाख से लेकर दस लाख रुपये प्रति कट्ठा तक होगी। सरकार के एक निवेश से

वहां के अगल-बगल के क्षेत्रों के लोगों का जीवन कितना ऊपर जाता है, उनकी आय कितनी बढ़ती है, वहां के जमीन की कीमत कितनी बढ़ती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने अपनी आँखों से देखा है और इससे उन सभी इलाकों का विस्तार होते हुए हमने देखा है। इसी प्रकार से, अगर वहां पर सड़कों का निर्माण होगा, अगर वहां इन्वेस्टमेंट आएगी तो स्वाभाविक तौर से वहां की आय बढ़ेगी, उस राज्य के लोगों की आय बढ़ेगी। अगर सरकार के निवेश से जमीन का भाव बढ़ता है तो इससे किसानों को और बाकी लोगों को लाभ होता है।

महोदय, आज कश्मीर में सरकारी दफ्तर समय से खुल रहे हैं। पहले वहां सी.बी.आई. और करप्शन लॉज लागू नहीं थे। अब वहां पहली बार सी.बी.आई. के केसेज दर्ज हुए। वहां करप्शन के मामले में बैंक के कई अधिकारी पकड़े गए। ये सब जनता के पैसे थे, यह किसी व्यक्ति का पैसा नहीं था। वहां कई सारे कानून पास किए गए।

महोदय, यह सुनने वाली बात है, वहां जम्मू-कश्मीर में 42,000 नए पद सृजित किए गए हैं। आप सोचिए कि उस राज्य में वहां के नौजवानों के लिए कितना बड़ा रास्ता खुला है।

महोदय, हमारी सरकार के प्रयासों से वह राज्य 100 फीसदी ओडीएफ हो गया। वहां हर घर तक बिजली सरकार ने पहुंचाई और कश्मीर के एक-एक घर में बिजली है। वहां के शिक्षकों को, जिन्हें पहले वेतन नहीं मिलते थे, उन्हें अब सी.जी.एच.एस. की फैसिलिटी मिलेगी, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। जम्मू-कश्मीर में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों का वेतन लगभग दोगुना हो गया है। यह तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है और हम सभी लोग इस पर गर्व करेंगे कि हमारे एक निर्णय से इन सब लोगों को इतना बड़ा लाभ हुआ।

महोदय, लद्दाख के बारे में तो कभी कोई चर्चा ही नहीं करता। अब वहां डिवीजनल कमिश्नर बैठेंगे। लद्दाख का डिवीजन इतना बड़ा है कि अगर उसे नापा जाए तो शायद पश्चिम बंगाल के एक कोने से भी बड़ा लद्दाख का एक क्षेत्र होगा। लद्दाख में यूनिवर्सिटी के बारे में कभी किसी ने लद्दाखियों के

लिए ऐसी कल्पना नहीं की होगी। मुझे याद है कि अभी हाल-फिलहाल में एक हवाई जहाज में मेरे साथ एक कप्तान थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कहां के रहने वाले हैं? उसने कहा कि मैं लद्दाख का हूं। पिछले 70 सालों में वह पहला लद्दाखी था, जिसे हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस मिला। हम लोगों ने इतना बड़ा निर्णय लिया है कि वहां के बच्चों के लिए हम एक यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। इसे समझना तभी संभव होगा जब हम वहां पहुंच जाएं और इसे समझ सकें।

महोदय, यह तो विश्लेषण है, बैकग्राउण्डर है। अब हम शशि थरूर की बातों के संदर्भ में चले आते हैं। ओ.ई.सी.डी. की एक रिपोर्ट सितम्बर में आई थी। उसमें कहा गया कि *weakest growth in the economy has been registered in the last ten years*. दुनिया भर की जो ग्रोथ है, वह लगभग 2.9 प्रतिशत से नीचे चली गई है। यह हमारी रिपोर्ट नहीं है। उसके कारण पूरे विश्व में, चाहे वह अमेरिका का फेडरल रिजर्व हो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो या पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हो, सभी ने धड़ाधड़ अपने लेंडिंग नॉर्म्स चेंज किए और सब लोगों ने इसे पूरी दुनिया में शुरू किया है। अगर निर्मला जी वह काम यहां करती हैं तो आप लोगों को इसके लिए बेचैनी होती है और पूरी दुनिया ही इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठा रही है। अगर हम मिड-कोर्स करेक्शन कर रहे हैं तो हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। हम दुनिया के साथ और दुनिया से आगे निकलने की तैयारी कर रहे हैं।

महोदय, मैं कभी भी आर्थिक विषयों पर नहीं बोलता हूं। सब लोग समझते हैं कि मैं पायलट हूं। मैं इकोनॉमिक्स का यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहा, लेकिन मैं कभी इसकी चर्चा ही नहीं करता हूं। मेरे जितने कन्टेम्पररीज़ हैं, वे मगध यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। यहां मेरा यह चौथा टर्म है, लेकिन मैं मूल रूप से राजनीतिज्ञ हूं। दूसरी चीजों की चर्चा करने से राजनीतिक महत्व कम होता है, इसलिए मैं राजनीतिक महत्व को ही आगे बढ़ाकर ही बात करूंगा।

महोदय, इन सभी चीजों से चीन और अमेरिका के बीच झगड़े हो रहे हैं। उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। वहां के राष्ट्रपति का कोई निर्णय, वहां के ट्रेड के किसी निर्णय से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। आज चीन से सभी लोग निकल कर बाहर जाना चाह रहे हैं। कहीं पर कई रिस्ट्रिक्शंस हैं। वे भारत आएंगे। हमने अपने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया, ताकि वे भारत आएंगे। वे ताइवान नहीं जाए, वे साउथ एशिया नहीं जाएंगे, वे सिंगापुर में नहीं जाए, बल्कि हमारे यहां आएंगे। जब हम लोग निर्णय लेते हैं तो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। हम इसलिए निर्णय नहीं लेते हैं कि यह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए है। पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में यह एक बड़ा निर्णय हुआ है, जिसके हम लोग साथी हैं। कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर उनको यहां लाया गया। शुक्र मनाइए कि अभी यूरोप में ब्रेक्जिट नहीं हो पाया है। अगर वह हो जाता तो शायद वर्ल्ड इकोनॉमी और नीचे जाती।

महोदय, आज ग्लोबल स्लोडाउन तो है ही। उसको हमें स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि आज किसी एक देश की आइसोलेशन की बात नहीं होती है। India has to play a much bigger role. We have done enough to bring down the corporate taxes. सरकार ने क्या कदम उठाया? इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए अगर हम कई सारे निर्णयों को भूलना चाहे तो भूल सकते हैं और कहना चाहे तो कह सकते हैं। सी.एस.आर. का कानून आया, उसमें यह था कि वह क्रिमिनल ऑफेन्स होगा। हम लोगों ने कहा कि उसको चेंज कीजिए और उसे सिविल ऑफेन्स बनाइए। अब वह सिविल ऑफेन्स हो गया।

महोदय, हम बार-बार कहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का व्यवहार अच्छा नहीं है। उनके लिए सेन्ट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया गया। उनके लिए स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस इश्यू हुए। आई.टी. ऑर्डर कैसे निकालना है, नोटिस तथा सम्मन कैसे देना है, इन सभी को सेन्ट्रलाइज्ड कर दिया गया है, ताकि उनकी मॉनिटरिंग हो सके। Surcharge on capital gains was reduced. Angel tax on start-ups was withdrawn. Bank lending rates, by RBI or through Government's

initiative, came down. जब बैंकों का पूरा लोन लौटा दिया जाता है, तो बैंक्स उनके कागजात लेकर बैठे रहते थे। सरकार का निर्देश हुआ कि अगर मेरा बैंक का क्लोजर हो गया, हमने पैसा लौटा दिया है, तो 15 दिन के अंदर कागज लौटाइए। देश के जितने लोग अपनी पूंजी लगाते थे, अगर उनका काम हो गया, उन्होंने पैसे लौटा दिए हैं, तो जो कागजात छुपा कर रख लिए जाते थे, उनसे कागजात लेने के लिए 15 दिन का मैनडेट दिया गया। ये जो छोटी-छोटी बातें हैं, उनके लिए सरकार ने निर्णय लिया है। मुझे नहीं लगता है कि किसी सरकार में इस प्रकार के निर्णय हुए हैं।

इसके अलावा, हम लोगों ने जीएसटी के बारे में बहुत चर्चा की। 17 टैक्सों को एक टैक्स बना दिया गया। जब राज्यों ने कहा कि मेरा क्या होगा, तो सरकार ने एक संवैधानिक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि इन सब को जोड़ कर पांच वर्षों तक, वर्ष 2015-16 के बेस लेवल से अगर आपका रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हुआ है तो हम 14 परसेंट की वृद्धि के हिसाब से देंगे। यह भारत सरकार की इतनी बड़ी ताकत थी। इतना बड़ा कमिटमेंट करके राज्य सरकारों को अपने पक्ष में लाया गया। देश में जो रोड बैरियर्स लगे रहते थे, ट्रकों का लंबा जाम होता था, आज वह खत्म हुआ है। इससे आम आदमी का जीवन अच्छा हुआ है और देश का भी हित हुआ है। अगर इसे देखने वाले को यह स्वीकार्य था कि बॉर्डर पर छह-छह किलोमीटर तक लाइन में खड़े रहे और उनका जीवन वैसा ही था। हमारे जीवन को देश के प्रधान मंत्री जी ने कम से कम उससे सरल बना दिया है। पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश जाने में अब हमें किसी भी बॉर्डर पर एक घंटा खड़ा रहना पड़े, उसको हमने खत्म कर दिया है और आप सभी को भी इसमें सहूलियत है। जो बॉर्डर टैक्सेस होते थे, ट्रक्स लगे रहते थे, वे सारी समस्याएं खत्म हो गईं। We have simplified the tax system, removed check posts at borders, reduced tax burden. इससे किसको लाभ हुआ है? It is an estimate. I do not know what is the source but it has been said that this has benefited normal people.

महोदय, हमारी सरकार ने बैंकप्टसी कोड लाया। उसके कारण जो रिकवरी हुई, वह तो हुई ही है। इसके कारण 70,000 करोड़ रुपये सीधे वापस लौटे और लगभग 20,2000 करोड़ रुपये का हम लोगों ने सेटलमेंट कर लिया है। NPAs have started being cleaned up. The NPAs in just one year reduced from 11.2 per cent to 9.3 per cent. इसका परसेंटेज लाखों में जाता होगा। Bank consolidation, which was much required, has been done in a very beautiful way. FDI liberalisation was done. FIPB has been abolished. We can see the growth of FDI. In 2014 when the FDI in this country was around Rs.25 billion, in 2019 it has reached Rs.44 billion. दादा, यह अपने आप तो नहीं हुआ है। कुछ न कुछ तो सरकार का योगदान है। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मोदी जी है तो मुमकिन है। ... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: यह सही है न, आप इसे स्वीकार कर रहे हैं न? ... (व्यवधान)

महोदय, कम से कम एक बार मैं अधीर रंजन जी को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि मोदी जी है तो मुमकिन है। ... (व्यवधान) अधीर रंजन साहब, आपको बधाई है। आप ऐसे ही अच्छी-अच्छी बातें करते रहें। ... (व्यवधान) मोदी जी है तो मुमकिन है, आपने कह दिया, हम लोगों ने भी इसे स्वीकार किया। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह मोदी जी के सुनहरे सपने हैं। ... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : अधीर रंजन जी, अब हो गया। आप दिल की बात कह चुके हैं। ... (व्यवधान) अभी हम कालेधन की बात छोड़ देते हैं।

महोदय, लगभग 100 करोड़ लोगों का आधार सीडिंग हुआ है। अब उनके खातों में सीधे पैसा जाता है। हम लोगों ने प्रायरीटी सेक्टर लेंडिंग में निर्णय लिया है। हमने कृषि, हाउसिंग, एक्सपोर्ट क्रेडिट तथा एजुकेशन के बारे में निर्णय लिया है। इसके कारण ही आज सरकार की गति दिख रही है।

एनबीएफसी डिस्ट्रेस में था, हाउसिंग सैक्टर डिस्ट्रेस में था। मंत्री जी ने कहा और पैसे निकाल कर दिए गए और काफी पैसे दिए गए। नेशनल हाउसिंग बोर्ड को लगभग 20 हजार करोड़ रुपये दिए। पीएसयू बैंक्स, एनबीएफसीज़ को ढाई लाख करोड़ रुपये दिए। ...(व्यवधान) ओरिजनल बजट नहीं, सप्लीमेंट्री बजट पर ही बता रहे हैं। आपने सुना नहीं। आप बात कर रहे थे। आप सुनते नहीं हैं। मैं देश की उपलब्धियों के बारे में बता रहा हूँ। 20 हजार करोड़ रुपये तो हाल-फिलहाल का है। दादा, आप अखबार भी नहीं पढ़ रहे हैं।

HON. CHAIRPERSON: Rudy Ji, please do not get distracted. Please address the Chair.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: We have to come to the political point. This is the technical point.

HON. CHAIRPERSON: Please go ahead.

श्री राजीव प्रताप रूडी : आप लोगों ने मेरा समय ले लिया। ऐसा न करिए। लगभग 9 लाख करोड़ रुपये का एनपीए था। हम लोग बार-बार सदन में बोलते हैं और देश को सुनाते हैं। हम बार-बार फिर जोर-जोर से कहेंगे कि आप लोग जब सरकार में थे, तो 9-10 लाख करोड़ रुपये आपने दे दिए। यह संकट हमारे लिए है, हमें वसूलना पड़ता है और कानून बदलना पड़ता है। अगर आप ईमानदारी से काम करते होते, जो पैसा आपने निकालकर देश के लोगों को दे दिया, पता नहीं किसको दिया, कहां दिया, संकट हमारा बना हुआ है। हम तीन-सवा तीन लाख करोड़ रुपये वापस लाए हैं। बाकी कहां हैं, हम ढूंढ़ निकालेंगे। हम सब लोग उस काम में लगे हुए हैं। ...(व्यवधान) पता नहीं कहां गया?

महोदय, माननीय मंत्री जी बैठी हुई हैं। मुद्रा एक ऐसी योजना है, जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे पास एक बड़ी इंटरस्टिंग चीज है, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में हर चीज को कहीं न कहीं लागू करता हूँ। ...(व्यवधान) मैं सब बताऊंगा। मिथुन साहब, मेरा समय पता नहीं क्यों कम कर रहे हैं?

माननीय सभापति: हम कम नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: माननीय चेयरपर्सन साहब, पिछले चार साल में 6 लाख करोड़ रुपये का हमने एक आंकड़ा निकाला है। मंत्री जी, मैं आपके पास इस विषय को लेकर नहीं पहुंच सका। मुद्रा योजना एक अद्भुत योजना है। कल एक क्वैश्चन का जवाब था, हमारे पड़ोस की एक सांसद हैं, उन्होंने कहा कि उनके जिले में 600 करोड़ रुपये मुद्रा योजना में गए हैं। मैंने अपने क्षेत्र में इस काम को चुनाव के पहले शुरू किया। मैंने प्रधान मंत्री जी को भी इसके बारे में बताया है। मैं बैंकों के साथ संघर्ष करता रहता हूँ। जहां मैं कामयाब हो गया, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, हम कोई लाख, दो लाख या पांच लाख करोड़ रुपये की बात नहीं कर रहे हैं। आप कृपया सुनिश्चिए। ये सब ऐसे व्यक्ति हैं, जो भारत के लोग हैं, गरीब हैं, किसान हैं।

भारती देवी, ग्राम खरिका, उसको 40 हजार रुपये श्रृंगार की दुकान के लिए, चूड़ी के लिए, कान वाले सामान के लिए मिले। हमको नहीं पता है, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, जिन्हें छोटी-छोटी बच्चियां जाकर काउंटर पर खरीदती हैं। आप लोगों ने कभी देखा नहीं है। अगर मेले में जाएंगे, तो देखेंगे कि किस तरह से यह बिकता है। भारती देवी को श्रृंगार के लिए दिया। शमसीर अंसारी को मैं खुद ही कागज देने गया था। शमसीर अंसारी से मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं? वह बोला कि मेरी मोबाइल रिपेयर की दुकान है। हमने पूछा कि कभी पहले बैंक से पैसा लिए हो? उसने कहा, बैंक से नहीं लिए। यह 100-110 लोगों की सूची है। ये लोग ऐसे हैं, कोई दुकान लगाता है, कोई ठेला लगाता है और अपना व्यापार पहले से कर रहा है। देश के प्रधान मंत्री ने इनको पैसा भिजवाया है कि जो बनी हुई दुकान है, इसमें मोबाइल रिपेयर भी है। ...(व्यवधान)

यह सोनपुर में एक छोटे से गांव की ब्रांच का है। राजकुमार गुप्ता, जो मिठाई का काम करता है, हलवाई है, उसे 50 हजार रुपये मिले। विजय शंकर भगत, गांव खरिक्समर को किस चीज के लिए

दिए? पान के दुकानदार को 50 हजार रुपये दिए। आप थोड़ा और आगे बढ़ने दीजिए। अरुण कुमार भोला ठाकुर को नाई के काम के लिए 25 हजार रुपये दिए। ऐसा नहीं है कि 50 हजार रुपये या 1 लाख रुपये ही हैं, किसी को 25 हजार रुपये भी दिए हैं। मैडम, आपने 10 रुपये सैकड़ा सुना है, देहात में 10 रुपये सैकड़ा लोग पैसे देते हैं। आहलूवालिया साहब जानते ही होंगे। 10 रुपया सैकड़ा, मतलब 100 रुपये लीजिए तो 10 रुपये ब्याज, उसका इंटरेस्ट रेट 10 रुपये प्रति महीना है।...(व्यवधान) देश के प्रधान मंत्री जी ने इसको समझा। 100 रुपये पर 300 रुपये उसको लौटने पड़ते थे। यह देश के गरीबों की योजना है। मालती देवी को श्रृंगार के लिए, मुकेश कुमार चौरसिया को ग्रिल मेकिंग के लिए दिए। हमारे गांव में एक मुसलमान, छोटा सा नौजवान मुर्गी की दुकान चलाता है, काट-काटकर आवाम को खिलाता है। बैंक में लिखा है कि चिकन शॉप के लिए, जाहिर अहमद अजहर को 48 हजार रुपये दिए। सुबोध महतो को चाट का ठेला लगाने के लिए 39,000 रुपये मिले, कहीं दुनिया में देखा नहीं था। कभी किसी ने सोचा था? मैं अब इस सूची को छोड़ देता हूं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सूची है।

अब विकास की बात करनी है। जब मैं बहुत छोटा था, मैं एक उदाहरण देता हूं कि विकास की कड़ी क्या होती है। कभी आपने सुना था कि रेलवे गंगा में स्टीमर चलाता है। किसी सदस्य ने नहीं सुना होगा। रेलवे कभी स्टीमर चलाता था, तब मैं गांव जाने के लिए स्टीमर से गंगा नदी पार करता था। उस पार सोनपुर जंक्शन को एशिया सबसे लम्बा जंक्शन कहा जाता था। उस समय गांव जाने में पूरे एक दिन लगता था। फिर विकास की गाड़ी आगे बढ़ी। गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु बना, उस पर जाने लगे, उस समय मेरी माँ हार्डिंग रोड से एक बस चलती थी, मेरा गांव वहां से 65 किलोमीटर दूर है। पटना से एक बस चलती थी जिसका नाम वन डे सर्विस था। वह सुबह छह बजे निकलती थी और 68 किलोमीटर दूरी तय करके शाम छह बजे तक पहुंचती थी और माँ उसमें सामान रख कर जाती थी। उसके बाद हमारी सरकार आई, फिर एक और पुल बना, फिर सड़कों का निर्माण हुआ। मैं पटना शहर में नहीं रहता हूं, हमारी सरकार का आगमन हुआ और इसमें बिहार सरकार की भी बड़ी

भूमिका रही है। आज मैं 55 मिनट में पटना से अपने गांव पहुंच जाता हूं, इनको विकास नहीं दिखता है, परिवर्तन नहीं दिखता है।

महोदय, आप भी पटना आइए। 70 सालों से पटना राजधानी की तरकारी सबलपुर, राहर दियरा, अकीलपुर और पतलापुर दियरा क्षेत्र से आता था। पीयूष गोयल साहब ने चार सौ करोड़ रुपये इसके लिए दिए, जहां पूरे बिहार की तरकारी निकलती है, एक-एक टोले तक खम्भा और ट्रांसफार्मर लग गया, आप चल कर पूछ लीजिए, वेरिफाई कर लीजिए कि किस तरह से सरकार ने वहां पहुंच कर काम किया है, जो किसी सरकार ने नहीं किया।

हमारे बहुत सारे मित्र यहां बैठे हैं। मैं पांच सालों से देहात में घूम रहा हूं, जब से हमारी सरकार है, मैं दिन भर देहात में रहता हूं, लोगों के बीच रहता है। पिछले पांच सालों में एक भी आदमी नहीं मिला, जिसने कहा है कि मेरी नौकरी छीनी गई है। देहात के लोगों का हैपीनेस इंडेक्स पिछले 70 वर्षों में सबसे अच्छा है। आज देहात के लोग खुश हैं।

दिल्ली के फाइव स्टार होटल आजकल घाटे में चल रहे हैं। वे घाटे में इसलिए नहीं चल रहे हैं कि वहां लोगों की कमी हो गई है। वे घाटे में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि दिल्ली के गलियारे और कनॉट प्लेस में ताजमहल बेचते थे और खरीदने वाले ताजमहल घूमते थे, उनकी संख्या पिछले पांच सालों में पांच सितारा होटलों में खत्म हो गई है। उसी का दुख हमारे दाहिनी तरफ के मित्रों को बहुत बेचैनी हो रहा है। यह बड़ा संकट है।

महोदय, आपको अंदाजा नहीं होगा कि दिल्ली में हम लोगों ने देखा है, गांव में हमने कहीं नहीं देखा है। कई बार हमारे मित्र कह देते हैं कि रूडी जी आप क्या-क्या बोल देते हैं। मैं जो बोलता हूं वह अगले सौ साल के लिए बोलता हूं। कई बार गड़बड़ भी बोल जाता हूं लेकिन उसे सुधार लेता हूं। सरकार ने पिछले पांच वर्षों में क्या-क्या निर्णय लिए हैं?

हम प्रवक्ता थे, निर्मला जी भी प्रवक्ता थीं। 1996 से पार्टी के प्रवक्ता हैं। ट्रिपल तालाक पर मैंने कितने घंटे ... * आर्टिकल 370 पर कितने ... * अयोध्या पर कितने घंटे ... * चर्चा में खर्च किए होंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा देश बनेगा, जो देश के बच्चों को इन संकटों से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है।

इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। अगला निर्णय भी आज या कल में आ जाएगा। हम माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देते हैं कि आने वाली पीढ़ी को संकट नहीं देखना पड़ेगा। पीढ़ियों के लिए निर्णय किया है, हम लोगों ने उनके साथ बैठकर किया है।

महोदय, हम लोगों की नीति बहुत सिम्पल है। यह देखने का नज़रिया है कि गिलास आधा भरा हुआ है या खाली है? कितना भी गिलास भरा हो, इनको खाली वाला हिस्सा ज्यादा दिखता है, जबकि हम लोगों को भरा हुआ दिखता है। यही इनके और हमारे सोचने में फर्क है। मछली खिलाने वाली सरकार चाहिए या मछली पकड़कर अपना जीवन चलाने वाली सरकार चाहिए? यहां से तय कीजिए। हम सबको मछली मारने का तरीका सिखाते हैं, जीवन तो वह अपने आप चला लेगा।

एक छोटी सी कहानी है। राजा का एक दोस्त बंदर था। बंदर राजा के कमरे में जाता था जबकि दरबारियों को परमिटेंड नहीं था। राजा बंदर को अंदर आना अलाऊ करता था और राजा बंदर के पास जाता था। एक बार राजा सोए हुए थे, राजा के बगल में बंदर सोया हुआ था। राजा की नाक पर मक्खी बैठी तो बंदर परेशान हो गया कि राजा की नींद खराब हो रही है। उसने एक बार तौलिए से हटाया, तो कुछ नहीं हुआ, तब उसने सोचा कि मक्खी को सबक सिखाना है। बगल में राजा की तलवार रखी हुई थी, उस बंदर ने तलवार से मक्खी उड़ाई तो राजा की नाक कट गई। आप जो कर रहे हैं आप इस बात को थोड़ा सा समझिए। हम बीजेपी वाले लोग तो बहुत अच्छे हैं, हमने आपको टोक-टाक कर छोड़ दिया, लेकिन आपने निर्मला जी से माफी नहीं मांगी है। आप माफी नहीं मांगेंगे तो

* Not recorded.

आने वाले जीवन में इस बात के लिए प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। सदन आपको कभी माफ नहीं करेगा, हम यहां चुपचाप बैठेंगे।

मैं एक बात को सदन में रखता हूं, इसका संज्ञान लिया जाता है। देश में जितनी जोर से सिविल एविएशन का विस्तार हुआ है, उस हिसाब से प्रत्येक वर्ष 1,000 पायलटों की जरूरत है। मैंने नीति आयोग से भी आग्रह किया है और मित्रों से भी किया है। भारत में मात्र 250-300 पायलट बनाने की क्षमता है। पिछले 20 वर्षों में और आगे आने वाले 20 वर्षों तक 700-800 पायलट विदेशों से ट्रेड होंगे यानी भारत की हार्ड करेंसी, 700-800 करोड़ रुपये जो देश में खर्च हो सकते थे, विदेश में जा रहे हैं।

मैं सरकार से मांग करूंगा कि देश में ही जवान प्रशिक्षित हों। उन्हें फ्लोरिडा, यूएसए, कनाडा, फिलीपीन्स न जाना पड़े। भारत में पायलटों के प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। हर सांसद के क्षेत्र के निकट केंद्र बने, यह हर जगह तो नहीं बन सकता है। पायलट प्रशिक्षण केन्द्र के लिए बड़े पैसे की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इस पर भी पालिसी लैवल पर विचार किया जाए। इसकी चर्चा कहीं नहीं हुई है। खेलकूद में ओलम्पिक्स का मामला है।

मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और आगे भी समय देते रहेंगे, यह मुझे विश्वास है। जिस ताकत के साथ वित्त मंत्रालय की छवि बनाई है, मैं इसके लिए निर्मला जी और हमारे छोटे मित्र अनुराग जी को बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद।

SHRI DNV. SENTHIL KUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam, Chairperson, Sir.

Thank you for giving me the opportunity to speak. The Appropriation Bill, 2019, also known as the supply Bill or spending Bill, authorises the expenditure of certain further Government funds from the Consolidated Fund of India for the current financial year.

There are so many Central Government schemes which are being given to the States, rural and poor, out of the tax payers' money. The hon. Finance Minister spoke about it. It is good and they feel proud that they have eradicated corruption through certain schemes and by transferring money directly in the bank accounts of the MGNREGA workers. There is corruption at the ground level. I hope the hon. Finance Minister will take note of it and see to it that the benefits of the schemes, launched by the Central Government from the taxpayers' money, go and reach the downtrodden, the poorest of the poor and the women.

All the Government schemes should be useful. Let me give you one example of the Open Defecation Free scheme. Lakhs of toilets have been constructed throughout the country. Thousands of toilets have been constructed in my constituency. Let me say that not even 10 per cent of the toilets are in use. They have spent around Rs. 12,000 on the scheme for construction of toilet. The Central Government gives a share of Rs. 3500. Just imagine the amount of money that has been spent. They say that with the given amount, it is impossible

to construct a toilet. They have just taken the money and it is just a room which is not in use. If the hon. Minister can send some representatives, I will take them to my constituency. I would challenge them to prove that more than 10 per cent of the toilets are in use. So, what is happening to the money that is being spent? It is not that the lakhs and crores of rupees, which is being spent by the Government, have gone down the drain, rather in this scheme, it has gone down the sewage.

When the Central Government has got a scheme, they should know within one year whether the said scheme is feasible or not, and whether they should think of revisiting the plan to try to make the things work out. That is the one suggestion which I would like to give.

We want to be transparent; we want to be corruption-free and we want to serve the people. I think, let me take this opportunity to request the hon. Finance Minister to raise the salary of the MPs and also enhance the funds given under MPLADS. I think the hon. Members from both the Benches would agree with me. The MPLADS funds, which is given, is too meagre. I have six MLA constituencies and an MLA gets Rs. 3 crore for a constituency. I think it is high time that there should be an enhancement of the same. In the adjoining Kerala, they are getting Rs. 6 crore. If we want to do something constructive for them, it is impossible to do it within MPLADS fund, which is given to us. So, I would like the hon. Minister of Finance to consider it. I think both the Benches will agree and will take this

matter forward. ...(*Interruptions*) In Tamil Nadu, it is Rs. 12000, whereas the Central Government gives ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You just go ahead with your speech.

SHRI DNV. SENTHIL KUMAR S.: So, while allocating funds, it is important that the efficiency criteria; like more tax revenues, the financial management and infrastructure needs for faster growth, should be considered for distributing funds to the States especially.

The States like Tamil Nadu should be rewarded because we have been affected not only by the vertical devolution, that is shaft between the States and the Union Territories, but also by the horizontal distribution in terms of the revenue of the States. There is a big difference between what we give and what we get. Like for example, the States' share in the Central taxes amount to more than Rs. 30,000 crore. The Tamil Nadu Government's total GST revenue estimation is around Rs. 64,023 crore. Tamil Nadu's contribution to the Union Tax is large, but the State gets just one-tenth in return. As I have already said, the States are losing the legitimate share due to the vertical devolution. Tamil Nadu has recorded a faster growth rate of Indian economy than the national rate. The States which are contributing more, are getting less. It is also the second largest State in terms of Gross State Domestic Product.

In this Appropriation Bill, it is heartening to see that the transfer to the States has been increased. I would like to know if the States' share of Rs. 7,825

crore of the Inter-State GST, would be released to the State of Tamil Nadu through this Appropriation Bill. The States like Maharashtra, Gujarat, Haryana and Tamil Nadu receive less than Rs.30 out of Rs.100 whereas some States get more than Rs.100 and even more than Rs.200.

A developing nation's growth is always judged on what the Government spends of its GDP on education and on health care. It is very sad to see the amount spent on these two things. I hope the Finance Minister takes a note of that and increases the share of GDP on education from what it is now. It is 1.2 per cent to 1.4 per cent on health care. So the expenditure on health care should be increased. The developed countries spend around 18 per cent of their GDP on health whereas we are at around 1.5 per cent.

I would also like to know about the AIIMS for Madurai which was announced in the Union Budget of 2014-15. The foundation stone was laid by the Prime Minister in January 2019. It is just that the foundation stone still exists. Not even one brick or stone has been added to it. I hope that the required amount would be released soon for the Madurai Medical College to take off.

A railway line was promised by the Railway Minister just before the elections. I do not want to see it as an election stunt. It is a good thing and we would benefit from it. It was Morappur-Dharmapuri railway line. An amount of Rs.358.95 crore was sanctioned but just a few lakh of rupees have been

released. I take this opportunity to kindly suggest to the Finance Minister to release the remaining amount to the Railways so that this work gets done.

We have high regards and respect for you, Madam. We want to see this as an Appropriation Bill and it should not be judged as a 'Misappropriation Bill', especially for Tamil Nadu. Please do consider.

Sir, I thank you for giving me this opportunity.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Mr. Chairman, Sir, I rise to speak on Supplementary Demands for Grants, 2019-20. I have already moved seven Cut Motions to the Supplementary Demands on which I will seek voting later.

The Supplementary Demands, as Dr. Shashi Tharoor mentioned are for a small amount which is a total of Rs.21246 crore and it is only 0.7 per cent of our Budget of nearly Rs.27 lakh crore.

15.58 hrs

(Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

The net cash outgo is Rs.18,995 crore and recovery is Rs. 2,249 crore. Madam Chairperson, I will divide my short speech into two parts. Firstly, let me speak about the proposals in the Supplementary Demands. The maximum amount has been given for Jammu and Kashmir and Ladakh. A total of Rs.8,820 crore has been given. I say that the Government has treated Jammu and Kashmir badly. So many leaders have been arrested including Dr. Farooq Abdullah, Shri Omar Abdullah and Ms. Mehbooba Mufti who have all been Members of this House. I demand their release immediately. I also demand re-introduction of internet services in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir cannot be kept as a jail permanently. This is not the way to bring peace, tranquillity and normalcy to any place ...(Interruptions). सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स में 8820 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर को दिए गए हैं। ...(व्यवधान)

Sir, the IDBI Bank has been given Rs.2,500 crore for re-capitalisation. It is a Government Bank with the maximum amount of NPA. Now the Government is trying to revive it by merging it with LIC.

16.00 hrs

But so far there has been no turn around. I would like to bring this fact to the notice of the hon. Finance Minister. The Department of Space has been given an extra amount of Rs. 666 crore. I do not know if the Department of Space has to be pulled up. The way our Chandrayan II failed, our rover failed to land on the moon. The Department of Space has been allocated an amount of Rs. 66 crore, including the expenses for Chandrayan III. The way the rover crashed on the moon has brought a bad name to the country. Those in-charge of Chandrayan should be pulled up for their failure to land a rover on the moon which many countries in the world have done successfully ...*(Interruptions)* Madam, Chairperson, you seem worried about something. From your facial expression it looks you are not happy.

HON. CHAIRPERSON : From the facial expression its displeasure about what you are saying. I think, you should know the history of all the Moon Missions which have been sent.

PROF. SOUGATA RAY: Madam, I know it.

HON. CHAIRPERSON: Not only about India but abroad also.

PROF. SOUGATA RAY: It was a failure.

HON. CHAIRPERSON: It was not a failure.

PROF. SOUGATA RAY: They were not able to land the Chandrayan on the moon.

HON. CHAIRPERSON: They have done very well. It was a hard landing at best.

PROF. SOUGATA RAY: A sum of Rs. 20 crore has been allocated for other charges for upkeep of shrines, temples etc., protection and upkeep of Ayodhya. So, slowly Ayodhya is being sought to be brought into the agenda. Now the Temple Trust will be formed and we shall see further drama in this area ...*(Interruptions)*

Madam, please do not look so worried. It upsets my equanimity.

HON. CHAIRPERSON: No. But that is what you have to learn.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Is he yet to learn?

HON. CHAIRPERSON: I am saying about this particular aspect that how he disturbs the equanimity.

... *(Interruptions)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर):
यदि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है, तो उसे न मानें ।...*(व्यवधान)*

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, Shri Ray, I am allowing one intervention since the hon. Minister wants to say something.

PROF. SOUGATA RAY: Madam, I am not yielding ...*(Interruptions)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सभापति महोदया, सुप्रीम कोर्ट ने सौ साल से ज्यादा लम्बे मुकदमे पर ऐतिहासिक निर्णय दिया है और उसके बाद सारे देश में कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भी यदि माननीय सदस्य यह बात करेंगे, तो ठीक नहीं है।

प्रो. सौगत राय: ऐसा लगा कि अयोध्या पर ... * मैं यही बात कह रहा हूँ। Madam, a sum of Rs. 3300 crore has been given for the ... * towards their cost of salaries and ration. Now, it is for us to judge. The police, of course, has succeeded in keeping the protestors down in the Union Territory of Jammu and Kashmir, but all over the country the ... * is not looked up to as an ideal Force. ...(*Interruptions*)

श्री राजीव प्रताप रूडी: सभापति महोदया, यह बात उचित नहीं है। इस बात को रेकार्ड में नहीं रखना चाहिए। पूरे भारतवर्ष की पुलिस फोर्स पर टिप्पणी करना अनुचित है।...(*व्यवधान*)

PROF. SOUGATA RAY : A sum of Rs. 1000 crore has been sought for providing additional funds under the scheme of free LPG, under the Ujjwala Yojana. The Ujjwala is good Yojana, it is a vote getting Yojana. But there is a demand for more 'Ujjwala'. So, I would say that if the hon. Minister had allocated more money for this scheme, then it would have been good. On the one hand, the hon. Minister is allocating more funds for the Ujjwala Scheme, on the other the Government has increased the prices of LPG four times in the last four months. So, the Government is pressing the middle class by hiking the LPG prices and they are saying that they are providing LPG connection under the Ujjwala connection.

* Not recorded

The other point that I would like to make is that it is now time for me to look towards the economy. The country has had the worst rate of growth in the last 26 quarters. Growth, dipping to 4.5 per cent, has been coming to what Professor Raj Krishna called the 'Hindu rate of growth'. It is estimated that in the next quarter, the rate of growth will fall even further. We discussed the taxation laws in this House just the other day. Madam Finance Minister has given Rs. 1,45,000 crore of sops to the corporates so that they invest more. Unemployment is at an all-time high of eight per cent. In 45 years, such a high unemployment rate has not been there. The Government has failed to attract investment under any circumstances.

Madam, that is why, I was wondering where from the Government will get this sum of Rs. 1,45,000 crore. The budget deficit will rise anyway. With this huge tax sop and GST earnings not up to the mark, I was wondering from where the Government would find the money to fund these tax sops to the corporates.

I found the answer, Madam. After much thought, I found the answer. The answer is that the Government has decided to sell 11 PSUs. When you are expecting for a better time, and you want to invest in the current business, you sell the family's silver. That is what this Government is doing – indulging in rampant disinvestment. Airports will be sold. Six have already been sold, and six more are in line. Air India will be sold, BPCL will be sold, and there is a further list. It includes BHEL, Andrew Yule & Co., ITDC's Ashok Hotel, Balmer Lawrie Investments and Balmer Lawrie Co., MTNL, National Textile Corporation, FCI

Aravalli Gypsum and Minerals India, Hindustan Copper, MECON, and Braithwaite & Co. This is the family's silver which the Government has decided to sell. We are strongly opposed to this policy of disinvestment by the Government. The Railways is solely being privatised. Even trains have been given to private companies and corporates. Ordnance factories are sought to be corporatized. So, in this very critical situation of the economy, the Government's response is to disinvest, disinvest and disinvest more. We strongly oppose all the efforts of the Government to disinvest in Public Sector Undertakings. ...(*Interruptions*)

Lastly, I would like to say that today, there is some good news for those who love democracy. The former Finance Minister, Shri Chidambaram has been released on bail by the Supreme Court. It is very relevant in the sense that he will be able to take on the current Finance Minister in the Rajya Sabha, and point out the flaws.

The other day, in the Economic Times Summit, the hon. Home Minister promised that we have done all the corrective measures, and now, it will be a free run. It means that they have arrested all those whom they wanted to arrest, those who were going against them, and now, they shall not arrest anymore. That was the message, the hon. Home Minister was speaking in the presence of the hon. Finance Minister, the other day. But fear is the key. This Government is ruling by fear and fiat.

In this situation when there is no social peace, when there is social tension, when investors are afraid to invest, when bank managers are afraid to give loans, when officials are afraid to take decision, in this atmosphere of fear where fear is the key and the fear factor works, investment will not come. If you are really believing in opening up the country, if you are believing in investment coming in and if you are believing in more employment coming with investment, you must free the country of this atmosphere of fear. That is why, I have given cut motions, I am the only one who has given cut motions to the Supplementary Demands. Ultimately, supplementary demands are not voted down to spend extra money and the Government have to obtain the sanction of the Parliament for the same. They have done it in this way, but every aspect of the financial sector is in doldrums.

The Finance Minister has admitted in this House that the total NPAs of banks amount to over Rs. 10 lakh crore. Now, the banks are being put together, maybe into big entities in the hope that they will be competing with global class banks. But that is not to be. Tell me of one particular sector of economy that is working well. Real estate is not selling the flats and the main problem is that there is no consumer demand; consumption is less. I mentioned to the Finance Minister the other day that unless they put more money in the hands of the consumer, they will not buy. So, FMCG will not sell; industries will not work; unemployment will not lessen and we are caught in a vicious cycle where the

different sectors of economy are showing signs of fatigue. Added to it is the scams that are happening now, like the Punjab and Maharashtra Cooperative Bank which we discussed in this House where people are not being to draw their lifetime earnings. She said that 78 per cent of people have withdrawn their investments. All their investments are below Rs. 50,000. But ultimately, the Government does not ensure that the banks are able to return the money to the depositors. How will investors/consumers' confidence come back? You think of the DHFL and IL&FS. These scams have not happened in UPA's tenure. These scams have happened in present Government's tenure. What are you doing to really punish those who sent the ILFS to the present condition? What are you doing about DHFL? These are all in doldrums. I have my full sympathy with the Finance Minister. I am sure that she is hard-working. I also find that she is combative in Parliament. She replies to any criticism very spiritedly. But what I want to say is that all is not well in the state of Denmark in this and as Hamlet would have said, 'to be or not to be' is the question. The question mainly is whether the Government can take the economy out of the doldrums that are presently there. We do not grudge you taking mere Rs. 21,000 crore. You take it. You take it even for putting down the people of Jammu and Kashmir, keeping Dr. Farooq Abdullah in jail, you take it for reviving the IDBI bank which has gone sick. You take it for giving more money to the police; you take it for giving money to the Department of Space, which fails to land its robotic mission on the moon; you take

it because you have to run a Government. We do not grudge you the right to spend more. What we grudge you is that you are hurtling towards a higher fiscal deficit; you are hurtling towards a lower rate of growth; you are hurtling towards more employment.

I do hope that the Government does come to the House with a package of measures that will take the Indian economy out of the doldrums that it is in. In this Supplementary Budget, no extra money has been given for agriculture. It is where 31 farmers are committing suicide in this country every day. The agrarian sector is in the worst crisis that has been there. The Finance Minister sometimes says that green shoots are showing. Why? It is because the automobile sales have increased during the Diwali period. No. You go to the Maruti periods. Thousands of cars are lying there. It is a sea of cars. You go to the JLR motor factory in Tamil Nadu. Thousands of cars are lying there unsold. We have to take the economy out of the morass that it is in.

With these words, Madam, I conclude my speech on the Supplementary Grants. Thank you.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): धन्यवाद सभापति महोदया, सप्लीमेंटरी डिमांड्स के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

महोदया, जैसा कि इस देश की वित्त मंत्री महोदया जी ने अर्थ संकल्प पेश करते समय कहा था कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को हम पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हम सभी सदस्यों ने उनको बधाई दी थी। लेकिन दुर्भाग्य से आज की स्थिति को देखें तो अनइम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, किसानों की हालत बहुत खराब है, व्यापारी परेशान हैं और कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था की आज की स्थिति क्या है, वह हम माननीय मंत्री महोदया जी से जानना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि अपने रिप्लाय में अर्थ मंत्री जी हमें इसके बारे में जानकारी देने की व्यवस्था जरूर करेंगी।

महोदया, इस सरकार ने अनेक अच्छी योजनाएं शुरू की हैं। जैसा कि रुडी साहब ने कहा कि मुद्रा योजना इस देश में रोजगार शुरू करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी थी। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज सबसे ज्यादा एनपीए, कम से कम दस हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा के एनपीए, मुद्रा स्कीम के माध्यम से जिन लोगों ने लोन लिया, उस सेक्टर में हैं। इसके बारे में समाचार पत्रों में जो समाचार आते हैं, उनको पढ़कर मैं बता रहा हूँ, लेकिन असली जानकारी मंत्री महोदया जी द्वारा देने की आवश्यकता है। किसानों के बारे में बात करें तो प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना इस देश में शुरू की गई है। हमें यह योजना बहुत अच्छी लगी। इस योजना की पहली इंस्टालमेंट 11 करोड़ लोगों के अकाउंट में गई। दूसरा इंस्टालमेंट 7 करोड़ लोगों तक गया और दुर्भाग्य से तीसरा इंस्टालमेंट 3.77 करोड़ लोगों तक गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पहला इंस्टालमेंट 11 करोड़ लोगों तक गया तो तीसरा इंस्टालमेंट सिर्फ तीन करोड़ लोगों को ही क्यों दिया गया? इतना ही नहीं, हमारे महाराष्ट्र के भण्डारा जिला के एक आदमी के अकाउंट में पहली

इंस्टालमेंट के दो हजार रुपये गलती से चले गए थे। उसे वापस लेने के लिए वहां सरकार के लोग गए थे। योजना अच्छी है, लेकिन सही तरीके से लोगों के पास नहीं जा रही है। इसके ऊपर कौन लोग काम कर रहे हैं, उनको इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों को गुमराह करने के लिए योजना शुरू नहीं होनी चाहिए।

सचमुच लोगों को योजना का लाभ मिलने की आवश्यकता है। इसीलिए आज किसान पूरे महाराष्ट्र के साथ, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, बंगाल हो, असम हो, इन सभी प्रांतों के किसान जिस तरीके से उध्वस्त हो रहे हैं, दुर्भाग्य से आज तक इस सभागृह में नियम 193 डिस्कशन के लिए नहीं आया है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और माननीय अध्यक्ष जी से भी यह प्रार्थना करता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण विषय को प्रधानता दें और किसानों के हितों के लिए जो डिस्कशन है, उसको भी इस सभागृह में लाने की आवश्यकता है। मैं आपसे यह विनती करना चाहूंगा कि किसानों से संबंधित जो-जो योजनाएं हैं, उसमें कटौती मत कीजिए। जो-जो देना है, उसको ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। जय जवान, जय किसान की घोषणा आदरणीय पंत प्रधान लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी थी, उसके ऊपर सचमुच ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। आज देश में एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस तो बंद हो चुकी है, जेट बंद हो गया है, इंडिगो के अंदर भी झगड़ा चल रहा है। एयर इंडिया को आज बेच रहे हैं, कल बेच रहे हैं, कोई आता है, कोई नहीं आता है। सभी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। ऐसे संकट में फंसी हुई एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार को सही उपाय करने की आवश्यकता है। एक 'उड़ान' नाम की अच्छी स्कीम आई थी। लेकिन इस स्कीम पर जिस तरीके से अमल होना चाहिए था, वह दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है। आम आदमी हवाई सफर करने का सपना देख रहा था। माननीय प्रधान मंत्री जी से उसकी यह आशा थी, लेकिन वह सही तरीके से सफल नहीं हो पा रही है। मेरे महाराष्ट्र का

जो सिंधुदुर्ग जिला है, वहां के एयरपोर्ट के लिए मैं माननीय नागर विमानन मंत्री जी से भी बार-बार मिल रहा हूं। लेकिन पिछले दो वर्षों से एयरपोर्ट पड़ा है, उड़ान स्कीम में उसका डिक्लेरेशन हो गया है, लेकिन वह शुरू नहीं हो पा रहा है। ऐसे जो काम हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, रोड एंड ट्रांसपोर्ट एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। सद्भाग्य से माननीय गडकरी साहब जी के नेतृत्व में इस देश के कई रास्तों का भविष्य बदल गया है। टू लेन से फोर लेन हो गया है और फोर लेन से सिक्स लेन हो गया है। लाखों-करोड़ों की फंडिंग आना शुरू हो गई है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले छः महीनों से रोड एंड ट्रांसपोर्ट को दिया जाने वाला फंड क्यों बंद हुआ है और फंड की वजह से रास्ते क्यों बंद पड़े हैं, इसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस देश में ऐसे कई रास्ते हैं। खासकर मेरे ही क्षेत्र में मुंबई-गोवा रोड है। वह एक महत्वपूर्ण नेशनल हाइवे है। लेकिन वह रास्ता 6-7 महीनों से बंद पड़ा है। गडकरी साहब ने आर्डर दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी फंड रिलीज़ नहीं हो रहा है। गडकरी साहब अच्छा काम कर रहे थे और सभी सांसदों के क्षेत्रों के लोगों को रास्तों की सुविधाएं दे रहे थे। मुझे नहीं पता है कि इतना अच्छा काम करने वाली मिनिस्ट्री कि फंडिंग पर क्यों कट लगाया गया है? क्यों उसमें कमी हो रही है? वह लोगों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। गडकरी जी की जो प्रशंसा हो रही थी, क्या उसमें किसी ने ब्रेक लगाया है? मुझे नहीं पता है।...(व्यवधान) लेकिन मैं यह जानता हूं कि इस देश में रोड्स की आवश्यकता है, रास्तों को बनाने की आवश्यकता है। चाहे बाकी जगहों पर कुछ कम कर दिया जाए, लेकिन रास्तों का प्रोविज़न पूरे तरीके से होने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल की योजना थी। सभी ग्रामीण इलाकों के सांसदों ने पिछली बार भी मंत्री जी से बार-बार यह कहा था और इस बजट में भी माननीय मंत्री महोदय जी ने पीएमजीएसवाई के लिए अच्छे तरीके से प्रावधान करने की घोषणा की थी। लेकिन प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का फेस शरी का काम आज

तक यहां भी चालू नहीं हुआ है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, इन राज्यों ने पीएमजीएसवाई स्कीम में अच्छा काम किया है। जिन राज्यों ने अच्छा काम किया है, उन राज्यों को बोनस देने की बजाय, जिन राज्यों ने अच्छा काम नहीं किया है, उनकी सजा जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको दी गई है, और वहां के भी रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं।...(व्यवधान) मैं अभी की बात कर रहा हूं। मंत्री जी ने कहा है।...(व्यवधान) मंत्री जी को यह स्पष्ट करने दीजिए कि आपने पीएमजीएसवाई के लिए कितनी निधि का प्रोविजन किया है और कितना पैसा रिलीज़ किया है। बजट स्पीच है, आप उसको पढ़ लीजिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं टूरिज्म के बारे में कहना चाहता हूँ।...(व्यवधान) आप ज़रा बजट को पढ़िए।...(व्यवधान) महोदया, टूरिज्म एक महत्वपूर्ण विषय है।...(व्यवधान) अपने देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी साहब ने अपनी कल्पना से स्वदेश दर्शन से एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम शुरू किया था। जिसमें हरेक राज्य के एक-एक जिले का चयन हुआ, जिस जिले का चयन हुआ, उसे कम से कम सौ करोड़ रुपये की निधि देने का प्रावधान उसमें किया था। लेकिन दुर्भाग्य से, दो दिन पहले माननीय मंत्री महोदय से मैंने बात की है।...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी से मैं मिला और बताया कि नरेन्द्र मोदी साहब ने जो घोषणा की थी, वह योजना भी अभी अमल में क्यों नहीं आ रही है? महाराष्ट्र का भी वैसा ही हाल था। अन्य कई राज्यों के हाल वैसे ही थे। अभी मेरी जानकारी में आया है कि स्वदेश दर्शन योजना को स्टे दिया गया है। उसका रिव्यू करने का काम चालू है। लेकिन मेरी विनती है कि प्रधान मंत्री स्वदेश दर्शन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, उसे न्याय देने का काम माननीय वित्त मंत्री महोदय को करना चाहिए और उसमें निधि का प्रावधान भी करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, यूथ एवं स्पोर्ट्स अफेयर्स विभाग की तरफ जाते हुए मैं एक ही बात कहूंगा। इस देश में युवकों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The Minister is saying something. I am allowing her to speak.

श्रीमती निर्मला सीतारमण: मैं सही नहीं समझी। आप मुझसे मिले थे? ...(व्यवधान)

श्री विनायक भाउराव राऊत : नहीं, आपसे नहीं मिला। टूरिज्म मिनिस्टर से मिला था।
...(व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: आप इसको स्पष्ट कीजिए। यह गलतफहमी हो रही है। ...(व्यवधान)

श्री विनायक भाउराव राऊत: मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। मैं टूरिज्म मिनिस्टर से मिला था। मैं आपसे नहीं मिला, लेकिन मिलने की आशा है। ...(व्यवधान) मैं टूरिज्म मिनिस्टर से मिला था।
...(व्यवधान) महोदया, मैं यूथ एण्ड स्पोर्ट्स अफेयर्स पर बोल रहा था। आज देश के करोड़ों यूथ्स को कोई रोजगार नहीं है, काम नहीं है, रास्ते पर भटक रहे हैं। इसीलिए भी प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना को अमल करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने आदेश दिया। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के मंत्रालय का शुरू में पोर्टफोलियो राजीव प्रताप रुढ़ी जी के पास था, अभी डॉक्टर पांडे साहब उसको देख रहे हैं। लेकिन मुझे मंत्री महोदय ने पत्र लिखा कि आपके क्षेत्र में ये-ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कंसन्ड हैं, उनके माध्यम से इस योजना की शुरूआत होगी। तारीख दे चुके, वक्त दे चुके, लेकिन छह महीने से आज तक, छह महीने तो छोड़ो पिछले दो वर्षों से यह स्कीम बंद हो चुकी है। इस देश के बेरोजगारों को आखिर आप क्या देने वाले हैं? एक तो कंपनियां बंद हो ही रही हैं। ऑटोमोबाइल्स सैक्टर बंद हो गया। व्यापारी बाहर आ गए। ऐसे वक्त में रोजगार निर्माण कर युवकों के हाथ के लिए आधार देने की आवश्यकता है। इसलिए रोजगार निर्माण करने के लिए सरकार का एग्जैक्टली क्या रवैया है, वह भी इस माध्यम से हम जानना चाहते हैं। धन्यवाद।

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants.

First of all, I would like to thank the hon. Finance Minister. She was kind enough to waive off GST on tamarind. It is because of the waiver of GST on tamarind, a lot of poor people and lakhs of tamarind workers in my constituency and in my State have benefited. I am sure, Madam, you will have all their best wishes during this turbulent period you are handling this portfolio. Thank you very much.

Coming to the Supplementary Demands for Grants, I would like to put forth my State's perspective more than the national perspective. The Central Government has brought in an Ordinance where corporates have been given incentives in income tax to the tune of Rs.1,45,000 crore. This is a welcome move because it will provide a stimulus to the economy especially during this downturn. I think, this is mitigated to an extent by the transfer of Rs.1,76,000 crore from the RBI as a surplus. But the fact is that all this is going to go into the non-tax revenues and this will not be a part of the devolution of taxes to the States. Our State is already crippling due to lack of finances. We are having huge stress on finances. This will actually impact us to the extent of Rs. 2000 crore. Before this Ordinance was given, our share of taxes was close to Rs. 34,833 crore and with Ordinance, it is going to be Rs. 32,778 crore. So, I request

the Government to take a positive view because we are already stuck with bad finances. We are having a huge revenue deficit. So, I request the hon. Minister to take a positive view on this as a special case for our newly formed State. The bifurcation has resulted in adverse implications for the finances of our State. We inherited 56 per cent of the population, 60 per cent of the debt and we also inherited only 46 per cent of revenues. There is a huge mismatch and there is a huge deficit in the revenues for the State. It would not be inappropriate to say that the bifurcation of the State took place with two promises.

The first promise is the special category status on this floor of this House and second is that they will fulfil all the conditions in the A.P. Re-organisation Act but the fact is that the special category status has not been addressed so far. It was promised on the floor of this House. It was promised in the manifestoes of both the BJP and Congress parties. It was promised not only in the House but was also promised in various meetings by the hon. Prime Minister himself and all the other Ministers who have canvassed in our State. So, I think it is the need of the hour to support our State. We are in huge deficit financially and I think it is time for the Government to keep up the promises made and even though A.P Re-organisation is there, a lot of promises have not been fulfilled. I think the Government should act in time to keep up what all have been promised in the A.P. Re-organisation Act.

I want to just give the magnitude of financial losses that we are incurring. After the partition, we inherited almost Rs. 97,123 crore debt and in the past five years, the debt has risen to Rs. 2,58,000 crore. This is huge and now the current Government, that is, we are facing a huge burden because of this. The interest part alone is Rs. 20,000 crore and the principal amount is again Rs. 20,000 crore. It is like Rs. 40,000 crore that we have to pay every year.

As of now, the Government is surviving purely on debt. We have unviable finances. We are having a huge revenue deficit. I appeal to the hon. Finance Minister to take a positive view and I also urge the Government to help our State very positively.

The only way forward for us is granting special category status. Our YSR Congress Party demands special category status and we request the Government to keep up the word which they had given us. It is not a demand. Whatever we are asking, it is there in A.P. Re-organisation Act. It is not something new which we are asking. All these were promised and we are requesting what has been promised to us.

Madam, I would like to talk about Polavaram project. It is a very important project. Andhra Pradesh is basically an agrarian State. More than 60 per cent of the population thrive on agriculture. But in the past few years, the farmers have been hit with continuous drought and cyclones. The debt of the farmers is Rs. 87,000 crore in 2014 and currently, it is at almost Rs. 1,30,000 crore. We can

understand the plight of the farmers. Andhra Pradesh has the highest indebted farmers in the country. So, it is time for the Government to help us in constructing the Polavaram project which is a part of the A.P. Re-organisation Act. It is a national project which has to be constructed by the Centre. The Centre needs to support with funds. There is almost Rs. 5,000 crore pending for the work already done in the Polavaram project. We are already living on borrowed finances and the interest part on this Rs. 5,000 crore itself is almost close to Rs. 500 crore for our State which is a huge burden on us. So, I appeal to the Government to release this fund immediately. The project is also in full progress. Very soon, it is going to reach the 41.5 metre level for the cofferdam which means that there will be submergence of land and a huge amount needs to go into land acquisition and also for rehabilitation. So, it is time for the Government to release the amount for the State. An Expert Committee was constituted for this project and our new Chief Minister Jagan Mohan Reddy is in the process cutting costs and saving money for the State.

On the advice of the Expert Committee, reverse tendering took place and we have a huge savings of almost Rs.800 crore. I think this is a direct saving to the Central Government. So, please keep all this in mind. Please understand our positive attitude and help build the Polavaram project fast. It is because we do not have such conditions for the national highway projects to happen in our State. Everything is on fast track. The bills are paid in a few days' time whenever the

work is done. But here we have delays for months. It is going to drain the exchequer with additional interest cost.

I would also like to bring to the notice of the hon. Finance Minister that as part of the A.P. Reorganization Act, we were promised a package like Bundelkhand where a backward district gets benefit. In our State, seven districts have been identified and every year Rs.350 crore has to be released in this regard but for the past two years, this amount has been pending and it is pending even for the current year also. So, a total of Rs.1,050 crore is pending for the State. I urge the Central Government to release this amount very soon. I also urge the Finance Minister to re-look into this Backward Area Grant. It is because if you see the actual Bundelkhand package, it is based on the number of districts but in Andhra Pradesh, we have lesser number of districts with a huge population and huge area. So, there is a mismatch in this. So, we urge the Central Government to re-work on this and take it on *per capita* basis.

I will give an example with reference to what has happened in Bundelkhand and what is happening in Andhra Pradesh. If you take the *per capita* grants which Bundelkhand is getting, it is almost Rs.4,115 per person but the same thing in Andhra Pradesh is just Rs.428 per person which is a big mismatch and it is nowhere close to the Bundelkhand package. We are getting only 10 per cent of what we were supposed to get. So, please consider this and re-work on this.

I would also like to bring to the notice of the hon. Finance Minister that during the bifurcation of the State in the first year, that is, 2014-15, it was promised that the revenue deficit will be bridged and it will be paid to the State but so far, of the total revenue deficit of Rs.22,948 crore, only Rs.3,979 crore has been released. Initially, there was a sort of dispute between the Central and the State Governments regarding this figure but the C&AG has ratified that it is only Rs.22,948 crore. There is no dispute on this right now. So, I request the hon. Finance Minister to take a view on this and release the revenue deficit whatever we have been expecting.

As I have already said, ours is basically an agrarian State. So, if you take, we are majorly dependent on River Krishna. Though Godavari passes through our State, we are not able to use much of water from that river. So, as part of inter-linking of rivers, I urge the Central Government to take up inter-linking of Rivers, Krishna and Godavari, as a national project because if you see, in the Krishna River, because of climate change or whatever reason or because of new projects being built, the water inflow into Andhra Pradesh, especially from Srisailem dam, has fallen from 1230 TMC to 456 TMC. This is the average figure I am giving. It is almost one-third of what water we need to get. So, the only way to improve the demographic dividend of the State is to inter-link these two rivers. Kindly support us because ours is an agrarian State and I think this will be the largest

employment generator for the State. It will help, especially the Rayalaseema region which is suffering from continuous years and years of drought.

As part of the A.P. Reorganization Act, we were promised that the Central Government would sponsor and fund a port in our State. But what has happened is, Dugarajapatnam port was found to be unfeasible. Since Dugarajapatnam port seems to be unfeasible, we request that money be given for Ramayapatnam port which is a very crucial port and is part of the Vishakhapatnam-Chennai Industrial Corridor. We also request the Central Government to step forward because our hon. Chief Minister has announced that he will be going ahead with the Kadapa Steel Plant which is part of the A.P. Reorganization Act. Please be kind enough to help our Government. Please help us with the funds to set up this steel plant and whoever comes forward, kindly help us to go ahead with our steel plant.

I think the most successful programme helping the poor is MGNREGA. I request the hon. Finance Minister to increase allocations for MGNREGA. During this tough period, it is going to help a lot of poor people. I also urge upon the hon. Finance Minister not to cut down allocations for PMGSY because it is very important for rural connectivity. I also request the Government to increase the housing allocation to the States, especially Andhra Pradesh because we have a lot of people living below poverty line in our State.

I also request the Government to help Andhra Pradesh in all the initiatives that the new Government has taken. We are going ahead with the renovation of

44,000 Government primary and secondary schools. This is going to help the poor in a big way. Kindly come forward and provide some grant for the development of these schools because it is only possible with good dedication that the poor can be lifted from the troubles they are facing. We are also going ahead with renovation of all the Government hospitals and public health centres. Please provide funds for this also.

Madam, there are many railway projects which have been pending for a long time and are getting crippled with escalation cost. Through you, I request the hon. Finance Minister to take up this cause also.

In the end, I would like to reiterate my request before the Government to keep up its promise of special category status for the State of Andhra Pradesh. With these words, I conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I stand here to deliberate on the Supplementary Demands for Grants which is before us for consideration and passing.

The Finance Minister has moved this extra spending of around Rs.21,246 crore as first supplementary, if I may say so. The Union Budget for Financial Year 2020 presented in July had estimated a total Government spending of Rs.27.86 lakh crore excluding expenses of public sector companies. Though the extra spending would be Rs.21,246 crore, actual cash outgo will be about Rs.19,000 crore.

In the media and also in different circles, the idea that is being floated around for last some weeks is that there is rising fiscal fears and a comprehensive review is needed. There is also a suggestion for the Government to take action in that already a blue print to revive demand and growth in Indian economy is mooted to boost manufacturing and that the Government must send out signals to the bureaucracy, courts, States and investors. That is how we can improve our economic situation.

Madam, I would also like to mention here that the gloom worries economy watchers and that is what has been repeatedly said by our economists. But here I would like to mention that India is now deliberating mostly on the Gross Domestic Product or GDP growth and that is a topic which is repeatedly hounding most of

the economists and thinkers of this country. That is the only measure through which we should aggregate our economic growth or fall.

Madam, I am reminded of the time when Shri Somnath Chatterjee was the Speaker of Lok Sabha. At that time, he had started a lecture series by inviting the world's eminent speakers and economists to speak on relevant subjects. I remember very clearly that there were number of people who had come to address in the Central Hall and a large number of Members of both Houses had attended it. We could hear the then Prime Minister of Bhutan talking about happiness - how to determine the happiness of a society - and that is how he had suggested that instead of just GDP, let us also try to calculate the happiness that ultimately is actually the growth of a society. ...*(Interruptions)* The success of a nation is measured not only by the nation's GDP but by better lives lived by its people.

There has been a gradual global shift towards well-being economics with Bhutan rejecting GDP as the main economic metric in favour of gross national happiness as early as 1971. The United Kingdom has also introduced some elements of it in its economic policy, but recently in June, 2019, New Zealand became the first developed country to make well-being core to its entire budget and the key objective for all its Government Ministries. I believe, we can adopt this as a planning tool not only to achieve our targets for the Sustainable Development Goals like poverty, hunger and health but also to gradually shift our focus on

people rather than on productivity. The economy exists to serve our people and the environment, not the other way round. My friend, Shri Nishikant Dubey, had mentioned it, of course, in his own way. I think, this House should deliberate on this subject in great detail in future.

As the determination of our economic growth even today rests on GDP, I would also like to mention here that India's gross domestic product for the second quarter of the ongoing fiscal year is only 4.5 per cent, the lowest it has been in at least six years. Even growth at current prices is only 6.1 per cent. There is little doubt that the Indian economy is in the midst of a slowdown, one that appears to be driven by both supply and demand side factors. The Government has attempted to revive demand by ensuring welfare growth and seeking to expand other aspects of its own spending, but that strategy is reaching the end of its usefulness.

The Government's final consumption expenditure or GFCE has grown at over 15 per cent year on year and is about 12.4 per cent of GDP. In other words, it contributes almost two percentage points of the 4.5 per cent overall growth in GDP. The non-government sector, therefore, may be growing only at about three per cent. Clearly, therefore, the picture is much worse than the headline number of 4.5 per cent and the Government spending is sucking dynamism out of the private sector. Therefore, the government will have to accept that this is a problem that cannot continue to be tackled by its own spending.

It has already sought to revive some animal spirits in corporate India through tax cuts. However, more is needed. Long pending structural reforms will have to be given some impetus. India is a high cost and risk economy to attract investment. At the moment, risk must be reduced through administrative, regulatory and judicial reforms. Here, I would like to focus on matters relating to my State, which we have been demanding for quite some time.

I would humbly want to bring the attention of this House and, through you Madam, of the Government to the amount of fund that has been transferred to any kind of project for promoting clean energy initiatives. Only Rs. 15,911.49 crore of the total funds relating to coal cess, which is roughly 18 per cent of the total funds, have been utilised for the clean energy projects out of the National Clean Energy Fund. In spite of enough evidence of no action and multiple neglected requests of States to allocate the funds for the State-level projects, it seems to be in impasse.

Supporting the federal structure of our Constitution, I, on behalf of my State, strongly argue for a definitive plan of action from the Government either by preparing a roadmap to spend the remaining unallocated funds within the next year dedicated to improve the clean energy production or by devising a mechanism to share the funds with the States enabling them to come up with more projects required in energy sector.

My next issue is related to various cesses that are being imposed by the Union Government. Since 2014 the Government has imposed multiple cesses for various causes, starting from clean India cess, increase in education and health cess, to increase in clean energy cess up to 800 per cent. Despite the Government's GST vision to promote One Nation One Tax system the cesses are still cleaning the pockets of the citizens. Although the Central Government has failed to explain the non-utilisation of collected cesses on multiple occasions, still there has not been any indication to improve upon the current practices.

I would like to get some clarifications from the Finance Minister on two aspects. First is, how these funds that are allocated are to be utilised? Second is, whether the funds have any negative implication on the States' economic condition. Moreover, I would ask the Government to make a monitoring dashboard for various cesses and surcharges, like funds collected throughout the country and the projects funded through the collected funds in order to review the specific economic loss to the States and particular industries. This model can guide the Government to reduce the cess charges.

There is a need to set up a dedicated expert committee to review all Central charges, except taxes for examining the necessity of these surcharges and cesses and present recommendations to promote more State-specific fund allocation.

I come to specific issues. I would not go into the details. I had marked the allocations relating to the Ministry of HRD, Sports, and Petroleum and Natural Gas. My colleague Prof. Saugata Roy has already deliberated on that. But here I would like to mention only two aspects. One is related to the amount of funds that is actually being spent for IDBI. The capital infusion into the IDBI Bank through issuance of recapitalisation bonds is Rs. 4,557 crore. The other is related to the additional requirement of Rs. 2,500 crore for recapitalisation of insurance companies. While going through that one can understand as to why we need this allocation. But I come to the other aspect which I think is necessary to mention. That is related to the Ministry of Home Affairs, to which around Rs. 8,820 crore have been allocated. A major part of it is for Jammu and Kashmir and Ladakh. It is because of the 14th Finance Commission's recommendation the Union Government is providing this fund. It is necessary. I fully support it. We are all concerned that normalcy should return to Kashmir. But normalcy does not end with Dr. Farooq Abdullah. Normalcy does not end with National Conference or PDP. Normalcy also has to be that we bring back the pandits who were driven out of Kashmir Valley. When are you going to take steps in that respect? A large number of people are staying in Delhi and other parts of the country. Many have gone out of the country and we can hear in international forums as to what their plight is.

Books have already been published. I would like to understand this from the Government. Though it is a supplementary Demand for Grants, you are going to provide all type of support to bring in normalcy in Kashmir. But please think of those people who were driven out of this Valley. We should not forget about their plight. Justice also should be given to them. You have provided only Rs.20 crore for Ayodhya. That is, of course, as per the direction of the Supreme Court.

Here, I would like to come back to other aspects also. I hope that the Government will respond to the points that I have mentioned. Perhaps the most disturbing aspect of the current economic slowdown is that the middle class is not growing, or I would say it has stopped growing. The Government needs to address the overarching issues of agricultural and resultant rural distress. It needs to reform the market for agriculture. There is a need to ignite rural demand for quicker economic recovery. Madam, I have just two more points.

The key problem of the Indian economy is the inadequacy of labour incomes. The share of labour income in manufacturing value added has been going down steadily from the mid-60s and, more sharply after 1990-91. It is now 30 per cent. In the services sector, this share is 52 per cent. There is a need to boost labour income to revive growth. As one is aware, the principal demand impetus for growth comes from the bottom half of the income distribution.

Now, I come to a report of the World Bank which estimated in 2018 that India needs to create around 8.1 million jobs a year to maintain its employment

rate but there is a difficulty in measuring employment in the vast informal sector. As per the Economist Intelligence Unit, the unemployment rate is rising year after year and the rate rose to a three-year high of 8.4 per cent in October, 2019 from 7.2 per cent in September, 2019.

We are supposed to benefit from favourable demographic dividend but, actually, we are lagging behind. Therefore, various blockages in the economy's arteries need to be cleared. These blockages are not limited to the banking sector or real estate sector. The Government and public sector must also start disbursing funds on time. The only way out for the economy is private investment reviving. It will require a genuine effort to increase the fund flow to productive sectors of the economy. With these words, I conclude.

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Madam, I rise to support the Appropriation Bill moved by the hon. Finance Minister. It is a formal procedure for the Finance Minister to come before the House during this Session to seek permission of the House to draw money from the Consolidated Fund of India to meet certain expenditure. I welcome this as the funds are definitely used for some schemes and programmes including Rs.3,300 crore in Supplementary Demands to meet the ration and salaries of police.

The first point I wish to make is that the Finance Minister has proposed to infuse Rs.4,557 crore in IDBI through recapitalisation bonds and Rs.2,500 crore for insurance companies. But, as per the recapitalisation plan, the PSBs were supposed to collect Rs.1.1 lakh crore from the market. I want to know from the hon. Finance Minister how much they could collect out of this in addition to the capital which was supposed to be infused.

The Finance Minister has also proposed to infuse Rs.1,000 crore for the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana to provide LPG connections to the poor. I want to know through you from the Finance Minister whether this Rs.1,000 crore will be sufficient for the demand because what I was told was that, in my State of Telangana, the number of connections which were demanded was much more than nine lakh connections which were given. I was told that the same issue is there in other States also.

17.00 hrs

As we all know that the economy is definitely going through a turbulent phase and the GDP of 5 per cent in the First Quarter and 4.5 per cent in the Second Quarter is definitely the second-lowest after 4.3 per cent of 2012-2013. No one would really want the economy to go down. Everyone would want a growth, which should not be jobless, but we want a lesser growth, which has to create certain jobs for the youth of the country.

As I said yesterday also, the growth story of the country is not dead. As per certain report, the growth in China is stalled whereas the growth in India is still growing, but we know that there is a perfect storm in the country and the storm has engulfed the auto sector, real-estate sector and the manufacturing sector. The immediate concern is the crash in demand, and the Finance Minister has definitely given some tax benefits to the corporate sector to push the manufacturing sector. It is definitely welcome, but the investments have to definitely come from the saved exemptions only.

When it comes to the demand for houses, it is also crashing. I would want to know this from the Finance Minister. How she will take care of it to correct this demand? It is because the money has to come into the hands of poor be it through NREGA wages or MUDRA Yojana or increasing support to the farmers or to increase the threshold of income tax limits.

I have also read in certain sections of the media that a GST Council is looking to rationalise the tax structure. I would definitely recommend 2-3 slabs. I also agree with the hon. Prime Minister who said that 'milk and Mercedes' cannot come under the same rate. The Experts are sitting in the Council, and I am sure that they are good enough to rationalise such good decisions to push the economy.

In yesterday's discussion, when the Amendment was taking place, the Finance Minister had said that there will be a deficit of Rs. 1.4 lakh crore, which will result in a fiscal deficit of 3.8 per cent and 4 per cent whereas the expected deficit was only 3.3 per cent. I would want to make a point here also. The fiscal deficit is there to cross the FRBM limit of 3 per cent, which was pegged at 3 per cent and it may go up to 4 per cent. I also know that it was 5.5 per cent during the UPA regime. The point that I am trying to make here is that the Government of India can cross the FRBM limit of 3 per cent, but when it comes to individual States, a State like Telangana, where the FRBM limit was 3 per cent, it was increased to 3.5 per cent to finance the DISCOMS. But the request of our Finance Minister was to enhance the limit of FRBM to 4 per cent. It is not only my State, but many of the States are requesting to enhance the FRBM limit. I would request the hon. Finance Minister to look into this issue.

I have read in some other article also, which said that : "I really do not know whether such schemes will definitely boost up the economy of the country

because we are going through a lull phase”, but in a country like Indonesia when they have announced a VDS, nearly Rs. 24 lakh crores were collected. They had said that for any undisclosed income only 4 per cent of the tax can be paid and 16 per cent of that amount can be put as a deposit in the country's banks, which are going to release bonds and which will be repaid in the coming five years. If in a country like Indonesia can really collect Rs. 25 lakh crores, then why cannot we also come up with such schemes?

With these observations, I support the Bill moved by the hon. Finance Minister, but I would really request her to support a newly formed State like Telangana by announcing a National status to the Kaleshwaram Project.

17.04 hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

If not the Kaleshwaram Project, then at least consider it for the upcoming Palamuru Rangareddy Project, and also support Mission Kakatiya and Mission Bhagiratha, which were recommended by the NITI Aayog. Thank you for giving me this opportunity.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I think that this week has been Nirmala ji's week. She has been here almost every day with some Bill or the other. I must congratulate her because yesterday what Prof. Saugata Da Ray ji said was true that she is combatively fighting circumstances.

I remember her saying yesterday or day-before-yesterday that she has been called names. She has been called the worst Finance Minister, and how deeply she is in pain and rightly so. I would be, if I were in your place. She was pilloried from her side. But what I feel is – I would like to say one thing to you – that you have got the job in the challenging times. This is not something which you have created. Challenging circumstances were there when you took this job. So, I fully understand and I see you making genuine efforts to make a difference to people's lives. I do appreciate that clearly. But there are a few suggestions and questions I would like to ask you regarding this matter, which have already been come up. So, I would not take too much time in it. But clearly, I would like to seek a little indulgence with a clarification from you regarding the IDBI Bank.

I think, Mahtab *ji* and Saugata *babu* have already talked about it. I just have a little caveat to add to it. You are doing this, I am sure, your intent is very good. Eventually the insurance company is going to pay for this. Who owns the insurance company? It is the common man. So, it is from one pocket to the other.

So, both those organizations may go down. What is the thinking of the Government? What is the policy of this Government to take this forward? I am not sure that this is the solution for the problems that we have because it is the common people's money. Where is this money getting used? Is it for the social sector schemes? Where is it getting used that there is such a big gap or hole? I would like to know.

About the Ministry of Home Affairs, I appreciate the Ladakh MP talking this morning. He was really sounding deeply pained. Here, there is so much money given. I feel, Jammu & Kashmir deserve more than anybody else. It is not just like Mahtab *ji* rightly said, it is not about one human being. It is the Kashmir people who definitely need. So, the entire money that you have asked for, if you ask me personally, it is inadequate. They need a lot more. I still remember, the hon. Home Minister had said over here that in the first three months, they would have a Summit to make investments in Jammu & Kashmir. I do not see that happening. So, what is the status of the entire situation?

In this entire situation, there is one small caveat. Gaurav Gogai *ji* is there. I was actually taking some advice from him. There is this point of promoting industry and internal trade. In that, there is transport freight subsidy that is being given to the North East. If I remember right, when the UPA Government was in power, these subsidies did exist. Then, they were withdrawn. It is a welcome step that you are doing it. But what was the logic of withdrawing them? What were the

reasons? Was it unemployment? Or was it a crisis in the North East? That is why this has happened. I think, none of these decisions that come over the economy should be political. It has to be fair. Whoever governs whichever State, I think, everybody deserves good governance. Till elections, we have differences. Once we have done with our elections, we all work for a common goal of building a good and a strong nation. If she could kindly clarify on this, it would be good.

Even with regard to the CRF, in my own State, Maharashtra, CRF money is not coming. Now, it has been moved from the Transport Ministry. Be it CAMPA, be it USFO, be it the cess, all these cesses and all these monies which the States used to get, we are not getting now.

I would like to quote Rajiv Pratap Rudy *ji*. He was complimenting. I do not know the situation in his State but in my State, it is different and smaller States are totally suffering. In his opening speech, he talked about the GST and the monies that are going and the compensations that are going to the States. My State is not getting any compensation. From whatever little I have read from the media is that the GST collections have dropped in my own State. In today's newspapers, it is about a gap for all the States –Rs.35 crore. In my own State, which is a larger State, it is over Rs.10,000 crore. If my State is struggling, I can imagine States like in the North East where Gaurav Gogai *ji* comes from, how those States are struggling? I am not sure. I request the Minister if she could clarify on this. He has spoken from the Treasury Benches. I would like to ask for a

clarification. Is his State getting something we are not getting? What is the situation of the GST Code on compensation to States?

He talked about the IB Code. We also supported that Code. We all thought that if the system is going to get cleaned up, it is a welcome step. He complimented it. He said that so much money has come back. Well, we have lost more money in it. The whole idea of getting this IB Code is for the stronger economies. I am not sure ours is an economy ready for it.

About the haircuts that are given, there are some haircuts, I am not against them. I do understand. Your intent is very good. Is this the direction because there are some haircuts which are up to 90 per cent that we have given. He talked about the NPAs. On NPAs, he said, 'I do not know where Rs.6 lakh crore has gone, it is up in the air'. Where is it gone? It is not up in the air. He said that the haircuts were given by the Government to clean up. I understand that you are trying to clean up the whole system but I think it is a little bit like Rambo. You are attacking everything. Everything is dying in that process. Hence, the fear psychosis is what one is hearing which is coming from the people. I think the Rambo solution is not going to work. We will have to do it piece by piece, get solution, build confidence and clean up. We are completely supporting the cleaning up of the system but whether that is hurting the economy is something we all have to put our minds to and see where it is going to take us.

Regarding FDI, it was really surprising this morning because in a reply to a question today, it was said that the FDI is only going up. I would like to quote the reply given in the morning: "The FDIs in 2015-16 were 55 US billion dollars and in 2016-17, it was 60.22 US billion dollars". These are provisional figures which is only 60 US billion dollars. So, the growth is from 60 US billion dollars to 60.97 US billion dollars and in 2018, again which is provisional, is 62 US billion dollars. At one time, it was from 55 US billion dollars to 60 US billion dollars. From 60, it should have actually gone up to 66 US billion dollars and from 66 US billion dollars, it should have gone up to 73 US billion dollars but it is completely stagnating. I come from a State where there used to be tall claims but none of those claims is shown here because it is all provisional. A lot can be said in provisional figures but there is no action and there is no investments. FDIs have not come even to my State which is one of the top-performing developed States in the country.

I would like to bring another point to the notice of the hon. Finance Minister. It is again from my State. Poverty has increased in a lot of States like Bihar, Jharkhand and Odisha, but now, even in my State, it has gone up. These are all reports of today. Rural inflation stood at 4.29 per cent in October which was 3.24 per cent in September. Urban food inflation is something I would really like to highlight to the hon. Finance Minister. I even spoke in front of her the last time.

She is a woman who runs her house even though she is a Finance Minister. I do realise that most women who even work do know how the home is run.

The food inflation in the urban areas has jumped to 10.47 per cent and inflation in urban areas is 5.11 per cent vis-à-vis 4.78 per cent last month. Urban food inflation was at 10.47 per cent, that is why, there was an uproar on the prices of onions. Rural inflation is 6.42 per cent vis-à-vis 3.2 per cent last month. Vegetable inflation is at 26 per cent vis-à-vis 15 per cent last month. Even pulses inflation is at 11.74 per cent. What '*Aam admi*' would eat when he has no job and inflation is high. So, what intervention is this Government going to bring? Even the real consumption or expenditure dropped across the entire rural economy. The entire rural economy is in the doldrums. I was actually expecting something more for agriculture but there is nothing substantial unfortunately for agriculture at all in this. The Hunger Index and Poverty Index, both the data show that India is not doing well.

I would like to ask a question to the hon. Minister because, earlier, one of the hon. MPs, I think, Saugata babu, talked about selling the family's silver. Just today, there was a lot of discussion about operating ratios to balance the economy. I agree with the hon. Minister because I have a modern thinking. I feel the economy should be open and vibrant. Even during our Government, Dr. Manmohan Singh ji was in favour of liberalisation. I am not against any of the measures taken for liberalisation and privatisation but at what cost? I still

remember, when this Government came in, they talked about operational ratio which even the Railway Minister himself talked about today. He gave a big explanation on it. They talked about Air India, at one time. BSNL, first, was a blue chip, now they are saying, no, it needs Rs. 70,000 crore. The same thing is happening to Railways. My concern that I voiced before and I reiterate, does that mean that even Railways are going to be privatised? Categorically, it was denied. But what about the operational ratio today? We asked about it. So, which way are we really headed is my serious concern. I would ask the hon. Minister to clarify this. I have two very short points just to clarify for my own self. I remember the CBDT Chairman in a press conference talked about revenue collections which you clarified by saying that the revenue collections have gone up during Diwali, but you said that the tax collections have gone up. Whatever we read in the media and the reports come to us do not show that and the CBDT Chairman himself said that there is a shortfall of Rs. 2.3 lakh crore. Earlier, I think Dr. Shashi Tharoor ji quoted you and there was a little discrepancy in what he said. I still remember you saying that there is a slowdown but we are not in a recession. I could be corrected if I am misquoting you. I do understand that a lot of things are happening. There is a slowdown and the Finance Minister admitted to it, which I appreciate. A lot of suggestions are made. I would urge the Minister to consider them.

There were two Cabinet Committees set up within the two weeks of the Prime Minister taking oath in 2019. One was on unemployment and one was on

economy. What is their status? What is the outcome of those Committees? I do not hear about it or see about it. I really do not know what their status is. I do understand these things but all the Supplementary Demands for Grants are slightly disappointing. I would just like to make a small suggestion and finish my speech, Chairman Sir, you have been very indulgent with time.

There are two books I would request this Government to have a look at and put on the reading list of the Government. One is by the Nobel laureate Richard Thaler called the 'Nudge'. I think this economy does not need just a nudge but it needs a push. But let us start with a nudge and then get a push. The other book is, 'Good Economics for Hard Times' by Abhijit Banerjee, the son of the soil who just got the Nobel prize. I think if we get some ideas through these books, and take some feedback from all the Members it will be useful.

I am sure we are committed to supporting and improving the economy. Even if we are in the opposition, we do not want our country to suffer at the cost of our differences. So, if there is anything more we can do to help, suggest, recommend, we would be happy to help the Finance Minister in whatever way we can. We do support these Grants but we are a little disappointed that the Government did not really do justice for people who really needed the push. Thank you.

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति महोदय, मैं अनुदान की अनुपूरक मांगों 2019-20 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2019-20 के लिए 21,246 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं समझता हूँ कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसकी अनुदान मांगों के अनुसार बजट होना बहुत जरूरी है। आज भारत विकास के मामले में कहीं भी पीछे नहीं है। पूरे विश्व में यदि भारत को विश्व गुरु माना जाए, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस देश के 70 सालों के इतिहास में आज तक जो-जो सरकारें देश में रही हैं, अगर देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के तरीके से काम किया होता, तो आज भारत की स्थिति ऐसी नहीं होती। आज दस साल के अंदर भारत विश्व के अंदर विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए, तो देश के प्रधान मंत्री और इस सरकार को देना चाहिए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश की आजादी के 70 सालों बाद देश के अंदर वर्ष 2014 में पहली बार जब यह सरकार बनी थी, तो उसने ग्राम पंचायत के लिए सीधा पैसा देने का प्रावधान किया था। एक-एक ग्राम पंचायत को 14वें फाइनेंस कमिशन का तीस लाख, चालीस लाख, पचास लाख रुपया यदि किसी ने दिया, तो देश के प्रधान मंत्री ने दिया। जब ये लोग यहां बैठा करते थे, तो साठ साल तक इन्होंने जीवन में कभी नहीं सोचा कि गांव का विकास होना चाहिए। गांव के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। उसके लिए खाने की, उसके लिए पीने की, उसके लिए मकान की व्यवस्था है या नहीं है, इसके बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा। इस वजह से इनका स्थान सदन में यहां से वहां हो गया। मैं कहना चाहता हूँ कि आजादी के 70 सालों बाद पहली बार 14वें फाइनेंस कमिशन का, 15 फाइनेंस कमिशन का पैसा ग्राम पंचायत को सीधे जा रहा है। आज ग्राम पंचायत की सारी की सारी सड़कें बन रही हैं। ग्राम पंचायतें अपने बलबूते पर खड़ी हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर यहां बैठी हैं। इन्होंने जिस तरह से बजट बनाया है,

पहली बार देश की ग्राम पंचायतें पांच साल का बजट तैयार कर रही हैं। इस बात का श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए, तो वह केंद्र सरकार और देश के प्रधान मंत्री जी को दिया जाना चाहिए।

महोदय, अभी हम मुद्रा योजना का जिक्र कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि यह योजना हमारे लिए सबसे अच्छी योजना है। अभी मैं अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर गया था। एक लौहार अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था। उस गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था 'प्रधान मंत्री मुद्रा योजना'। जब मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि देश के प्रधान मंत्री जी ने 'प्रधान मंत्री आवास योजना' और 'मुद्रा योजना' में यह जो गाड़ी हमें लेकर दी है, इसके लिए यदि हमारी उम्र भी देश के प्रधान मंत्री को लग जाए, तो अच्छा होगा। आम लोगों की आज यह सोच देश के प्रधान मंत्री के लिए है। पिछले पांच सालों में देश की सरकार ने देश के लिए जो काम किया है, वह किसी ने आज तक नहीं किया है। आजादी के बाद पिछली बार जब प्रधान मंत्री जी ने सिंचाई का प्रावधान किया, तब 53 हजार करोड़ रुपये इस बजट में रखे थे। मुझे इस योजना के लिए, मेरे संसदीय क्षेत्र में एक केनाल के लिए चार हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने दिए थे। राजस्थान की जीवनदायनी राजस्थान केनाल के लिए चार हजार करोड़ रुपये यदि किसी ने देने का काम किया है, तो देश के प्रधान मंत्री ने किया। वित्त मंत्री जी बैठी हैं, मैं इनके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपने राज्य के लिए पैसा दिया है, लेकिन वह पैसा सही लग रहा है या नहीं, यह देखने की बात है। जब राजस्थान में सरकार बदली तो सरकार बदलने के बाद ऐसे कई डिसिजंस हुए, आज वह काम अधूरा पड़ा है। केन्द्र सरकार ने चार हजार करोड़ रुपये दिए। जो नहरें बननी थीं, वे बन गईं और जो बीच में थीं, वे बीच में रह गईं। ऐसी कई केन्द्र सरकार की योजनाएं, राज्यों में जा कर रुक गई हैं। यहां पर 'आयुष्मान भारत' योजना का जिक्र हो रहा था।

सभापति महोदय, आज सुबह मैं प्रधान मंत्री जी के कार्यालय में एक लंबी लिस्ट लेकर गया। मेरे संसदीय क्षेत्र से एक लिस्ट आई है, वह कैंसर पेशेंट्स की है, उनको पैसा दिया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि प्रधान मंत्री राहत कोष से कैंसर पेशेंट्स से संबंधित 35 केसेज में मदद मिलती है,

लेकिन अभी तक राजस्थान में 'आयुष्मान भारत' योजना चालू नहीं हुई है। यह योजना राजस्थान और बंगाल में नहीं चल रही है। यह एक-दो राज्यों में नहीं चल रही है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए लोगों को फायदा देने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को डाटा भी नहीं भेजा है, आज आम लोगों की ऐसी हालत इन लोगों की वजह से हुई है। मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं है कि आज गांव में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो कई निगेटिव सोच के लोग, कई निगेटिव सोच की सरकारें वहां पर बैठी हैं, जिनकी वजह से लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों के लिए उन्होंने जो किया था, उसे कहने में मुझे कोई शंका नहीं है, मैं वह कह भी सकता हूं कि आप ने कभी जो घोषणा की, उसे आपने कभी पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने 'किसान निधि' योजना की घोषणा की थी, उसका भी डाटा अभी तक राजस्थान सरकार ने नहीं भेजा है और हम लोग कहते हैं कि किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है। अभी सौगत दादा कह रहे थे कि किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है, एक किश्त आई है, दो किश्त आई है या तीन किश्त आई है। जब राज्य सरकार केन्द्र सरकार को डाटा ही नहीं भेजेगी तो केन्द्र सरकार उसे पैसे देने का प्रावधान कैसे करेगी, यह मेरी समझ से बाहर है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन बातों को गंभीरता से लेकर राज्य सरकार पर ध्यान दें, ताकि इन योजनाओं का लाभ, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ, सीधे गांव के लोगों को मिल सके।

अभी 'उज्ज्वला' योजना की बात हो रही थी। गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए किसी व्यक्ति ने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर में गैस का चूल्हा जलेगा। उनके घर में गैस का चूल्हा जलाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज उनके घर में गैस का चूल्हा प्रधानमंत्री जी और

केन्द्र सरकार की वजह से है। मैं अपनी ओर से एवं राजस्थान प्रदेश की तरफ से प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसी योजनाओं की शुरुआत केन्द्र की सरकार ने की है।

प्रधान मंत्री जी ने 'प्रधानमंत्री फसल बीमा' योजना की शुरुआत की थी। जब से इस योजना की शुरुआत हुई है तब से किसानों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात करूंगा। मेरे लोक सभा क्षेत्र में दो जिले हैं। हमारे लोक सभा क्षेत्र में 'प्रधानमंत्री फसल बीमा' योजना के तहत श्रीगंगानगर में किसानों को 227 करोड़ रुपये और हनुमानगढ़ में 34 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। लगभग 60 हजार से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। अगर वह किसी की देन है तो वह इस सरकार और देश के प्रधान मंत्री जी की देन है।

माननीय सभापति महोदय, किसान की जमीन कैसी है? अगर आज देश के किसानों के लिए देश के प्रधान मंत्री जी ने सोचा है। देश में सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत मेरे संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर से हुई थी। हम ने अपने एक जिले में ढाई लाख सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए हैं। हम ने हर जगह लैब्स स्थापित किए, ताकि किसानों को फायदा मिले। हम ने योजना बनाई है, सरकार ने योजना बनाई है। अगर ऐसी योजना सारी सरकारें बनाने लगे तो किसानों का कितना उत्थान होगा, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है।

मैं एक किसान हूं। यह जीडीपी की बात कर रहे हैं। मैं जीडीपी को नहीं मानता हूं। अगर मेरे खेत में प्रति बीघा दस क्विंटल कॉटन हुई है, तो मेरी जीडीपी अच्छी है।...(व्यवधान) किसानों की जीडीपी वही है। जब देश के प्रधान मंत्री जी ने एमएसपी तय कर दिया, उस एमएसपी पर हमारी फसल बिक रही है। जहां पर हमारी सरकार नहीं है, तो उधर बैठे हुए लोग थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो इधर बैठे हुए लोग हैं, ये वहां पर कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। अगर किसानों की फसल सही दाम पर बिके तो मैं कह सकता हूं कि किसान की

जीडीपी वही है। वह किसान आगे बढ़ेगा, वह जिला आगे बढ़ेगा, वह प्रदेश आगे बढ़ेगा, वह देश शिखर के पथ पर आगे बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि कई मामले विचाराधीन हैं, उनको सरकार के रहते हुए पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने जो काम किया है, मुझे वर्ष 1996 में पहली बार यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं कुछ समय को छोड़कर पिछले 25 वर्षों से इस सदन में हूँ। मुझे कई राज्यों में भी जाने का सौभाग्य मिला है।

रेल के इंजन बिजली से चलते हैं। राजस्थान के लोगों ने नहीं सोचा था कि यहाँ भी कभी बिजली के रेल इंजन चलेंगे। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी यहाँ बैठे हैं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र में भी विद्युत के रेल इंजन चल रहे हैं। अगर इतना बड़ा काम किसी ने किया है, तो इस देश के प्रधान मंत्री के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है।

पर्यटन की दृष्टि से भी हम पीछे नहीं हैं। अगर विश्व के पर्यटकों ने सबसे ज्यादा संख्या में कहीं आने की कोशिश की है, तो भारत में आने की कोशिश की है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भारत पर्यटन के क्षेत्र में आगे निकला है। मेरे संसदीय क्षेत्र में ऐसे दो जिले हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत एक सभ्यता कालीबंगा है। जब इनका राज था, तो कालीबंगा सभ्यता में एक कंकाल था, जो नौ फीट का था। उसे भी लोग उठाकर ले गए थे। ये लोग उसको भी नहीं संभाल पाए। मैं कह सकता हूँ कि पर्यटन के क्षेत्र में हम सबसे आगे हैं।

मैं आपके इशारे को समझ रहा हूँ। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जब मुझे बोलने का अवसर मिलता है, तो आप यहाँ पर बैठते हैं। इसलिए मुझे कुछ समय और दिया जाए।

मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं सरकार को सुझाव देना चाहूँगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार ने पूरे राजस्थान के लिए राज्य सरकार और पंजाब सरकार को सिंचाई

परियोजना के तहत चार हजार करोड़ रुपये दिए हैं। हम लोग पंजाब का गंदा पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को कैंसर, पीलिया और थायराइड जैसी बीमारियाँ हो रही हैं। राजस्थान के आठ जिलों के लोग इन बीमारियों से ग्रसित हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ बैठी हैं। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि पंजाब का जो केमिकलयुक्त गंदा पानी राजस्थान में आ रहा है, शुगर मिलों का जो गंदा पानी आ रहा है, उसको रोकने का काम करें। आपने पैसे दे दिए हैं। आप भी पंजाब सरकार से बात करें। इसके साथ-साथ, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में दो जिले हैं। दोनों जिलों में सरकार ने मेडिकल कॉलेजे खोले हैं। मैं इसके लिए सरकार को और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस काम के लिए दोनों जिलों में से प्रत्येक को 325 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा लोक सभा क्षेत्र पूरी तरह से एग्रीकल्चरल क्षेत्र है। यहाँ का पूरा क्षेत्र सिंचाई पर निर्भर है। यहाँ पर तीन नहरें आती हैं। राजस्थान में श्रीगंगानगर ही एक ऐसा जिला है, जहाँ पूरा पानी सिंचाई के काम में जाता है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से यह माँग करता हूँ कि श्रीगंगानगर में एक कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए और एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर खोलने की मंजूरी दी जाए।

मैं वर्ष 2019-20 के लिए अनुदानों की अनुपूरक माँगों का समर्थन करता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity. In the Budget presented for the year 2019-20, the estimated Government expenditure was Rs. 28.86 lakh crore. Now, through this Supplementary Budget, the Finance Minister has asked for an additional amount of Rs. 21,246.16 crore, mainly for the following items: Rs. 2500 crore for Department of Financial Services, Rs. 666 crore for Department of Space, Rs. 1000 crore for Ministry of Petroleum and Natural Gas, Rs. 8820 crore for Ministry of Home Affairs, Rs. 3377 crore for Ministry of Coal, Rs. 565 crore for Department of Promotion of Industry and Internal Trade and Rs. 2000 crore for Defence.

The fiscal deficit estimated by the Government at the time of the Budget was only 3.3 per cent. Sir, due to this additional expenditure, the fiscal deficit is likely to increase to 3.7 to 3.8 per cent. The GDP growth rate fell to 4 per cent, the lowest in more than six years. It has come down from 4.54 per cent to 4 per cent. GDP growth in 2018-19 was 7.1 per cent. In the second quarter of 2012-13, it was 7.49 per cent and now it has come down to four per cent.

Economists like Subramanyam Swamy, a senior leader in BJP and MP also, says that 4.5 per cent GDP growth is not correct. It is only 1.5 per cent. It is a false statement. People around the Finance Minister are not telling the truth.

They are giving an enhanced figure of 4.5 per cent. It is his statement. I do not know whether it is true or not.

The dream of Shri Modi or this Government was to achieve a 5 trillion dollar economy by 2022-2023. Looking at the growth rate, it is estimated that the Government can achieve a five trillion dollar economy only after ten more years, that is, by 2033-34.

Sir, the main reason for the economic slow down is the low investment and unemployment. It is good that our hon. Prime Minister is making frequent visits to foreign countries. More than 100 times he has visited foreign countries. I do not know how many countries he has visited and how many are yet to be visited. People, particularly those in foreign countries, appreciate him. They treat him as the ...^{*}. They are all happy but our people in India are sad because they are not able to see him frequently. Out of 550 districts, there are a number of districts where our Prime Minister has not gone yet but very few countries are left which he has to visit yet. It is good. Let him visit but I would like to know from the hon. Minister the number of agreements signed with regard to FDI with these more than 100 countries which he has visited so far. Which are the countries he has visited so far; what are the agreements, what is the amount signed and what is the amount invested State-wise? I come from Tamil Nadu and I do not know how

^{*} Not recorded

much money is invested in Tamil Nadu. So far as I know, nothing is invested in Tamil Nadu.

I would like to ask about the industrial sector. How many industries have come up with FDI? How much employment opportunities are being created? In America, the working age population of adults is above 67 per cent.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: In India, the working age population of adults is nearly 50 per cent only. Low income, low per-capita consumption, increase in unemployment and slow growth is due to low investment mainly in industrial sector. These are the main reasons. So, growth is not possible without investment in manufacturing industry. How are you going to compensate it? How are you going to increase the economy? So, the Government is planning to sell all the public sector units.

The hon. Finance Minister had her school and college education from Trichy. Madam, Trichy is your place also. I would like to request you to stop selling off the Trichy International Airport. It is in the second list for private sale. Already eleven public sector units, including MTNL, BSNL and also Railways, are going to be sold.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: I am concluding. You are also going to sell more than 51 per cent share to the private partners. The Government is going to

become minor partners in the public sector units. So, I insist that the profit-making public sector units should not be sold.

I just want to make one or two requests on behalf of my State of Tamil Nadu. I would request the hon. Finance Minister to increase the number of days under MGNREGA to 200 days and also increase the salary of the workers to Rs.300. It will help the women folk in rural areas.

As has been requested by another hon. Member, I would also like to request the hon. Finance Minister to increase the funds under the MPLADS. As others have spoken here that for an MLA, it is Rs. 3 crore in Tamil Nadu; it is Rs. 6 crore in Kerala; and in Delhi, they are planning to increase to Rs. 10 crore. So, at least, there should be an increase of Rs. 2 crore per MLA constituency.

HON. CHAIRPERSON: Please listen to me. Kindly conclude. समय का पालन तो करना होगा।

...(व्यवधान)

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: Kindly give me only one minute. In every constituency, there is an office for MLAs. MPs must also have one office in every parliamentary constituency. Rs. 50 lakh can be allotted within the MPLADS fund also.

The unemployed youth should be helped with the monthly allowance until they get employment. In Tamil Nadu, about one crore people are unemployed. More than 30 crore people are unemployed throughout the country. Some

monthly assistance should be given to them till they get employment. During the off-season, farmers and fishermen community should be helped with some monthly allowance. Agriculturalists should be helped with the pension scheme.

HON. CHAIRPERSON: Shri P.K. Kunhalikutty. You will get five minutes. Please be brief.

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Many hon. Members, who have spoken from the other side, were claiming that everything is fine and the country is marching ahead with prosperity. What kind of a prosperity is this? We do not know. We have seen better times. They talk about the prosperity of the nation. But we do not see anything. There is no movement in the market. There are no jobs for the youngsters. We see sleeping towns since there is no buying and selling or anything in the shops. There is no real estate movement. There is no financial movement. There is no purchase or sale or anything. What kind of prosperity is this?

Sir, it seems we are in a very difficult situation. We are not marching ahead to prosperity. The economists are talking that people at large have the doubt that we are going ahead. We are going towards a poverty situation. Look at the situation in the country. The prices of essential commodities are going up. Food is becoming very costly. It is becoming very difficult for the common people to

keep their health. Education is becoming very costly for the people. What kind of prosperity is this?

When the demonetisation was started, Dr. Manmohan Singh, the former Prime Minister, had warned about such a situation. At that time, you did not agree with him. You mocked him and you even said that he is taking bath after wearing raincoat and all that. But actually, that kind of a situation has now emerged in the nation. I am afraid the country is losing its credibility among the comity of nations. There is talk that we are even going below the neighbouring countries like Bangladesh and Pakistan in many areas. Is it a happy situation? The Finance Minister should think about it as it is something which is very serious.

Giving concessions to big business houses again and again will not help. That is what many economists say. So, a real solution has to be thought about. Otherwise, the fear among the people at large is that we are heading towards poverty kind of situation. The price of onion is an example. We know that the common man apart from roti, needs onion and salt. This is a mere need which they have. We know that is not a nutritious food. They cannot buy even onions for a taste. So, you can see what kind of a situation we have landed in. The situation is very serious.

The workers are losing jobs. Major industries are not running. Middle class people are not able to employ people. In the unorganised sector, the workers are losing their jobs. They do not have jobs at all. They are not working at all. Then

how are they going to buy their bare minimum needs every day? So, I would again say that the situation is very serious.

Take for example the small and medium scale industries. This is where we found major jobs. This is a sector where ordinary people are given jobs. But small and medium scale sectors are in great difficulty. Many have said earlier that the GDP is in its lowest stage during the last seven years. Somebody was saying that we need not take into account the GDP. We can take into account the happiness of the people. That is equal to say that we should be contented with what we have. We are happy with what we have. Even if we do not have onion to eat, we should be contented with *roti* only. That is what it is. Should we be a country like that? India was a prospering country. It was a country which was fighting to be a major voice in the world. Now, a stage has come when we are advised that we should be happy with what we have. So, it is a very difficult situation.

Take for example, the situation in the State of Kerala. Kerala is one State where we could find a minimum standard of living. People could buy things and there was no poverty. But even in that State, today reports of poverty are creeping in. So, the economic situation that the country is facing is very serious. Mere eye-washing will not help. The hon. Finance Minister and the people in-charge and the Government should do something very seriously to address this problem, otherwise this country will break down and economically it will rank below our

neighbouring countries. Something has to be done seriously to get out of this situation, rather than just talking politics.

Thank you.

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants.

Sir, I remember what our hon. Finance Minister said in her Budget speech about the GDP growth and achieving a five trillion economy. Presently, our GDP growth rate has fallen to 4 per cent. But even then, the Government says that our country is on way to becoming a five trillion-dollar economy. Our country's economy is now like a time bomb and it can burst at time. The hon. Prime Minister and his dear corporate friends are saying that India is shining. Government is not reducing poverty but are reducing the number of poor in the data sheet. I am saying about withholding of the Consumer Price Index data of 2017 and 2018 published by the National Statistical Institute. Villages of this country in this *Ram Rajya* are facing the worst poverty in the last four decades. But the Government is fooling the people by manipulation and by hiding data. If the Government releases the real data, then the people will get to know the real picture of our country.

Unemployment is another issue that the propaganda makers are hiding under the carpet. More than half of the working age population is out of labour force in India. What was the promise made by this Government? The Government promised 2 crore new jobs a year which comes to 8 crore jobs in four years. But it has generated only 18 lakh jobs during this period.

Sir, no doubt our hon. Prime Minister is a dream-seller. Agriculture has become a death game for our poor farmers in our country. The absence of a supporting system from the Government such as subsidies, credits etc. has pushed more than 3 lakh farmers to suicide. Take for example, the much-touted scheme, namely the *Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana* started in 2016. Astonishingly, the fundamental problems and issues remained almost the same in both the old crop insurance schemes and the new PMFBY. The C&AG has spotted huge gaps in PMFBY and other crop insurance schemes with 45 per cent of the false claims made under this scheme. So far, this scheme is a huge failure. While a sum of Rs. 10 lakh crore of corporate debts have been written off, only 10 per cent of our farmers have gained by way of loan waivers. The question is, with whom is the Government standing – corporates or farmers?

Sir, a 7.5 per cent hike in subsidy for food, fertilizers and petroleum is also hiding facts. A 15 per cent subsidy was announced last year for food, fertilizer and petroleum. There is a cut of Rs. 1000 crore for food and Rs. 413 crore for fertilizer in the current year's Budget.

What is 'Make in India'? It is not 'Make in India', it is 'Selling India'. The Modi Government has penchant for selling our PSUs including one of our Maharatna company, namely, BPCL. MSME is another sector which has been neglected by the Government which has borne the maximum brunt of demonetisation, misadventure and the sub-optimal GST implementation.

Sir, another joke is giving pension under *Pradhan Mantri Shram Yogi* to the workers after 32 years. More than 82 per cent of India's workforce is employed in the unorganised sector in India as noted by the International Labour Union. There is an estimate of about 40 crore workers in this sector. The average life expectancy of an Indian is 68 years. Again, a casual worker who works under precarious conditions will have an average life expectancy much lesser than that. How many would be alive to receive the Government pension after 32 years?

An example of Modi Government's duplicity is visible in the allocation for the much publicised *Beti Bachao Beti Padhao* Programme. Funds for this Programme have been cut from an already embarrassing Rs. 255.9 crore to just Rs. 100 crore. The important Mid-Day Meal Scheme has seen an increase of just Rs. 51 crore, compared with the last year's expenditure. In reality, this means an actual decline, harming crores of school-going children.

What is the attitude of the Government towards the SCs and STs? Dalits and Minorities are the social segments that are worst hit by the policies of the Government. They are having the feeling of fear, fear and fear everywhere.

It is *achhe din'* for corporates. Diversion of funds in the name of banking recapitulation is another tricky game of the NDA Government in favour of the corporates. In reality, all the banks are under debt crisis due to Non-Performing Assets.

Some of the country's biggest banks are reporting losses with lakhs of crores of gross Non-Performing Assets amounting to about 5 per cent of the country's GDP. This has caused due to the non-payment of loans given to the corporates. Last year, Rs. 5 lakh crore have been earmarked for banking recapitulation. This year, it has crossed Rs. 10 lakh crore.

Sir, all the promises of this Government are, therefore, yet an eyewash to fool the people. Through manipulated and inflated data, it hides the grim realities on the ground, and this Government is another example of how crony capitalism could worsen the miseries of the common man.

Sir, I have one request to make. As all the other hon. Members requested, the MPLAD fund may be hiked by at least Rs. 2 crore in an Assembly Constituency. With these words, I conclude my speech.

माननीय सभापति: कुंवर दानिश अली जी ।

माननीय सदस्य, आप थोड़ा संक्षेप में बोलिएगा । भूमिका छोटी रखिएगा और सीधे पॉइंट पर आइएगा ।

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Thank you very much, hon. Chairperson Sir, for allowing me to speak on the Supplementary Demands for Grants.

देश में जो आर्थिक माहौल है, वह बहुत ही गंभीर है। जब इस कृषि प्रधान देश में 31 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हों।...(व्यवधान) यह डाटा है।...(व्यवधान) तो देश में कितना विकास हो रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।...(व्यवधान)

महोदय, अभी तो मैंने अपना भाषण शुरू भी नहीं किया है और ट्रेजरी बेंचेज से रनिंग कमेंट्री शुरू हो गई है।...(व्यवधान) जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूँ, तो ये क्यों परेशान हो जाते हैं? ... (व्यवधान) जब भी मैं यहाँ पर किसानों की बात करता हूँ, दलितों, वंचित समाज की बात करता हूँ, तो ये ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए लोग परेशान हो जाते हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात बोलिए।

कुंवर दानिश अली: महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर जो सरकार है, 'सबका साथ सबका विकास' की बात करने वाली हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार है।...(व्यवधान) जीडीपी का क्या हाल हुआ? अब जीडीपी 4.5 परसेंट रह गई। अभी एक माननीय सांसद, हमारे साथी ने यहाँ कहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा कि 4.5 परसेंट ... * बोल रहे हैं, केवल 1.5 परसेंट है। मैं उनकी बात पर कभी यकीन नहीं करता, लेकिन कभी-कभी कोई आदमी ठीक बात भी कर देता है। उन्होंने जीडीपी को 1.5 परसेंट बताया है और वे खुद बीजेपी के सांसद हैं। बैंकों का क्या हाल हुआ है? एनपीएज कितने हैं? जो बैंक घाटे में थे और जो बैंक सही चल रहे थे, उन दोनों को मर्ज कर दिया। अब यह होगा कि जो बैंक सही चल रहे थे, उनको भी डुबाने का काम यह सरकार करने जा रही है।

* Not recorded.

महोदय, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना इस सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मैं जब अपने क्षेत्र में 'दिशा' की बैठक में गया तो यह पता चला कि इस योजना से किसानों को कोई फायदा नहीं होता, इस देश में जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कम्पनीज हैं, अल्टीमेटली उन्हें फायदा पहुंचाने की यह स्कीम है। मैं उसका जिलावाइज आंकड़ा दे सकता हूँ कि किसानों से प्रीमियम के नाम पर कितना वसूला गया, सरकार ने कितना शेयर दिया और उसके रिटर्न में किसानों को क्या मिला। पर, मैं उसकी डिटेल् में नहीं जाना चाहता।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब सच्चाई बोली जाती है तब दर्द होता ही है।...(व्यवधान)

यह सरकार 'मेक-इन-इंडिया' की बात करती है, लेकिन 'मेक-इन-इंडिया' में क्या हो रहा है? यहां पर जो बन रहा था, जो प्रॉफिट-मेकिंग पी.एस.यूज. थे, उन्हें भी डिसइंवेस्ट किया जा रहा है। बी.पी.सी.एल. को बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। यहां पर आप ही के एक वरिष्ठ मार्गदर्शक सांसद डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट थी कि दिल्ली एयरपोर्ट में कितना घोटाला हुआ। उस रिपोर्ट को भी इन्होंने नहीं देखा। उसके बाद भी ये और एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी का भी कुछ टाइम है। मैं उसी हिसाब से आग्रह कर रहा हूँ। डिमॉनेटाइजेशन हुआ, जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस देश में नोटबंदी की तो सब लोगों को लगा कि शायद यह एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि जो नकली नोट्स हैं, वे सब इसमें खत्म हो जाएंगे। पर, पता यह चला कि 99 प्रतिशत से ज्यादा नोट्स वापस आ गए और जो लोग आर.बी.आई. के सेन्टर्स पर इसके लिए लाइन में लगे थे, उन्हें लाठियों से भगाया गया वरना 100 प्रतिशत से भी ज्यादा आ जाते और पता चलता कि असली के चक्कर में नकली भी अन्दर आ गए। अभी भी कितने

आए, यह मुझे नहीं मालूम है ।...(व्यवधान) उसका क्या नतीजा हुआ? पूरे देश की इकोनॉमी नोटबंदी के चलते गड़बड़ा गई ।...(व्यवधान)

ये 'सबका साथ, सबका विकास' की बात करते हैं । ये सबके विश्वास की बात करते हैं । मुझे यह बता दीजिए कि जो शिड्यूल्ड कॉस्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और माइनॉरिटीज़ की स्कॉलरशिप्स थीं, उनमें आपका क्या एलोकेशन है?... (व्यवधान)

सभापति जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ । उत्तर प्रदेश के अन्दर पहले एस.सी. और एस.टी. को स्कॉलरशिप्स मिलती थीं, उनके एडमिशन डायरेक्ट होते थे, कॉलेजों में पैसे जाते थे । पर, इस वर्ष एस.सी., एस.टी. के स्टूडेंट्स के एडमिशन नहीं हुए क्योंकि स्कॉलरशिप्स नहीं आईं ।

माइनॉरिटीज़ के लिए एक मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम भारत सरकार की है कि उसमें भारत सरकार उर्दू टीचर्स के लिए अपना शेयर देगी, लेकिन वह पैसा केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दिया । अकेले मेरी कंस्टीट्यून्सी में ऐसे हजारों उर्दू टीचर्स हैं, जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं ।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि आप कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं । आप किसानों को दीजिए, लेकिन किसानों की जो असली समस्या है, उसे देखिए । किसानों को उसकी फसल का वाज़िब दाम दिलाइए । किसानों को जो आप तीन हजार रुपये और छः हजार रुपये देते हैं, उसमें किसान उस छः हजार रुपये में उलटा और साठ हजार रुपये कर्ज लेकर अपनी खेत में फसल बोने का काम करता है । ऐसा वह इस विश्वास में करता है कि जब मेरी फसल आएगी तो उसका मुनासिब दाम मुझे सरकार दिलाएगी और बाज़ार से मिलेगा । लेकिन, जब उसकी फसल आती है तो न तो सरकार खरीदती है और न ही जो बिचौलिए मार्केट में बैठे हैं, वे ही खरीदते हैं ।...(व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इसकी ओर दिलाना चाहता हूँ ।...(व्यवधान)

کنور دانش علی (امروہ): Thank you very much hon. Chairperson Sir, for allowing me to speak on the Supplementary Demands for Grants.

محترم، ملک میں جو معاشی حالات ہیں وہ بہت ہی گمبھیر ہیں۔ جب کس کرشی پردھان ملک 31 کسان روز خود کشی کر رہے ہوں۔ (مداخلت)۔ یہ ڈاٹا ہے۔ (مداخلت)۔ تو ملک میں کتنا وکاس ہو رہا ہے، یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ (مداخلت)

جناب، ابھی میں نے اپنی تقریر شروع بھی نہیں کی اور ٹریزری بینچ سے رننگ کمینٹری شروع ہو گئی ہے۔ (مداخلت)۔ جب بھی میں بولنے کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ جب بھی میں یہاں کسانوں کی بات کرتا ہوں، دلتوں و نچت سماج کی بات کرتا ہوں تو یہ ٹریزری بینچز پر بیٹھے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں (مداخلت)۔

جناب، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہاں پر جو سرکار ہے، سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرنے والے ہمارے عزت مآب وزیر اعظم صاحب کی سرپرستی میں یہ سرکار ہے (مداخلت)۔ جی۔ڈی۔پی۔ کا کیا حال ہوا؟ اب جی۔ڈی۔پی۔ 4.5 فیصد رہ گئی ہے۔ ابھی ایک معزز ممبر، ہمارے ساتھی نے یہاں کہا ہے کہ سبرامنیم سوامی صاحب نے کہا کہ 4.5 فیصد ؟؟؟؟؟ بول رہے ہیں، صرف 1.5 فیصد ہے۔ میں ان کی بات پر کبھی یقین نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی کوئی آدمی ٹھیک بات بھی کر دیتا ہے۔ انہوں نے جی۔ڈی۔پی۔ کو 1.5 فیصد بتایا ہے اور وہ خود بی۔جے۔پی۔ کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں۔ بینکوں کا کیا حال ہوا ہے؟ این۔پی۔ایز۔

کتے ہیں؟ جو بینک گھاٹے میں تھے، اور جو بینک سہی چل رہے تھے، ان دونوں کو مرج کر دیا گیا۔ اب یہ ہوگا کہ جو بینک سہی چل رہے تھے، ان کو بھی ڈُبائے کا کام یہ سرکار کرنے جا رہی ہے۔

جناب، پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا اس سرکار کا ایک فلیگشپ پروگرام ہے۔ میں جب اپنے حلقہ میں دشا کی بیٹھک میں گیاتو پتہ چلا کہ اس یوجنا سے کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس ملک میں انشیورینس سیکٹر ہے، جو ملٹی نیشنل انشیورینز کمپنیز ہیں، الٹی میٹلی انہیں فائدہ پہنچانے کی یہ اسکیم ہے۔ میں اس کا ضلع وائز آنکڑا دے سکتا ہوں کہ کسانوں سے سے پریمیم کے نام پر کتنا وصولا گیا، سرکار نے کتنا شیر دیا اور اس کے بدلے میں کسانوں کو کیا ملا۔ پر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔

محترم چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب سچائی بولی جاتی ہے تب درد ہوتا ہی ہے (مداخلت)۔

یہ سرکار میک۔ان۔انڈیا کی بات کرتی ہے، لیکن میک۔ان۔انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر جو بن رہا تھا، جو پروفٹ میکنگ پی۔ایس۔یوز تھے انہیں بھی ڈس انویسٹ کیا جا رہا ہے۔ بی۔پی۔سی۔ایل۔ کو بیچا جا رہا ہے، ائر پورٹس کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ ہی کے ایک سینئر رہنما ممبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر مرلی منوبر جوشی جی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رپورٹ تھی کہ دہلی ائر پورٹ میں کتنا گھوٹالا ہوا۔ اس رپورٹ کو بھی انہوں نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد بھی یہ اور ائرپورٹس کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں۔

محترم چیرمین صاحب، میری پارٹی کا بھی کچھ وقت ہے۔ میں اسی حساب سے گزارش کر رہا ہوں۔ ڈیمونیٹائزیشن ہوا، جب عزت مآب وزیر اعظم صاحب

نے اس ملک میں نوٹ بندی کی تو سب لوگوں کو لگا کہ شاید یہ ایک بڑا انقلابی قدم ہے کہ جو نقلی نوٹ ہیں وہ سب اس میں ختم ہو جائیں گے۔ پر، پتہ یہ چلا ہے کہ 99 فیصد سے زیادہ نوٹ واپس آ گئے ہیں اور جو لوگ آرہی۔آئی۔ کے سینٹرس پر اس کے لئے لائن میں لگے تھے، انہیں لاٹھیوں سے بھگایا گیا ورنہ 100 فیصد سے بھی زیادہ آ جاتے اور پتہ چلتا کہ اصلی کے چکر میں نقلی بھی اندر آ گئے۔ ابھی بھی کتنے آئے، یہ مجھے نہیں معلوم ہے (مداخلت)۔۔۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پورے ملک کی ایکونامی نوٹ بندی کے چلتے گڑبڑا گئی (مداخلت)۔ یہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں۔ یہ سب کے وشواس کی بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو شیڈیولڈ کاسٹس، شیڈیولڈ ٹرائبس اور اقلیتوں کی اسکالرشپ تھی ان میں آپ کا کیا ایلوکیشن ہے (مداخلت)۔۔

چیرمین صاحب، میں اتر پردیش سے آتا ہوں۔ اتر پردیش کے اندر پہلے ایس۔سیز اور ایس۔ٹیز کو اسکالرشپ ملتی تھی، ان کے ایڈمیشن ڈائریکٹ ہوتے تھے، کالجز میں پیسے جاتے تھے۔ پر اس سال ایس۔سی۔، ایس۔ٹی۔ کے طلباء کے داخلے نہیں ہوئے کیونکہ اسکالرشپ نہیں آئے۔

اقلیتوں کے لئے ایک مدرسہ ماڈرنائزیشن کی اسکیم بھارت سرکار کی ہے کہ اس میں بھارت سرکار اردو ٹیچرس کے لئے اپنا شیر دے گی، لیکن وہ پیسہ مرکزی سرکار نے اتر پردیش سرکار کو نہیں دیا۔ اکیلے میرے پارلیمانی حلقہ میں ایسے ہزاروں اردو ٹیچرس ہیں جن کے گھروں میں چولہیں نہیں جل رہے ہیں۔

محترم چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے صرف اتنی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ بینیفٹ اسکیم میں

کسانوں کے کھاتوں میں پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ آپ کسانوں کو دیجئے، لیکن آپ کسانوں کی جو اصلی سمسٹیا ہے، اسے دیکھئیے۔ کسانوں کو اس کی فصل کا واجب دام دلائیے۔ کسانوں کو آپ جو 3 ہزار روپیئے اور 6 ہزار روپیئے دیتے ہیں، اس میں کسان اس 6 ہزار روپیئے میں اُلٹا اور 60 ہزار روپیئے قرض لے کر اپنے کھیت میں فصل بونے کا کام کرتا ہے۔ ایسا وہ اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ جب میری فصل تیار ہو کر آئے گی تو اس کا مناسب دام مجھے سرکار دلائے گی اور بازار سے ملے گا۔ لیکن جب اس کی فصل آتی ہے تو نہ تو سرکار خریدتی ہے اور نہ ہی جو بچولئیے مارکیٹ میں بیٹھے ہیں وہ ہی خریدتے ہیں (مداخلت)۔

محترم چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے سرکار کا دھیان اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔

माननीय सभापति: अभी बोलने वाले माननीय सांसदों की लंबी सूची बाकी है, इसलिए इस विषय पर चर्चा के लिए, अगर सदन की सहमति हो तो एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाए। क्या फिलहाल एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

माननीय सभापति: ठीक है।

18.00 hrs

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Hon. Chairman, Sir, some of the hon. Members referred to the situation in Kashmir and the steps taken recently. The revocation of special status of Jammu and Kashmir does not only injure and violate the fundamental principles of Indian polity, what about the unilateral breach of the pledges made in 1947, 1952 and 1975, that is, Kashmir Accord, Delhi Accord? It violates the fundamental principles of federalism. The decision also tramples upon the Constitution.

It was expected that once the Constitution Bench of the Supreme Court has decided to examine the constitutional validity of all the steps, the Government will put things on hold and allow the hon. Supreme Court to examine the matter and wait for its decision. Be that as it may. The decision of 25th August has been marketed by untruths. I would not say 'lies' because that may not strictly be as per parliamentary conventions.

Here, one of the hon. Members has said that now CBI is there. CBI was all along there. We had two police stations of CBI all along there right from 1956. One of the hon. Members said that now a university is there in Ladakh. But we already had a university in Ladakh; and its Vice-Chancellor was Mr. Phunsog, someone from Ladakh. They say that now discrimination is over. We already had the Ladakh Hills Development Council headed by someone from Ladakh running the administration of Ladakh.

Same way, Jammu has fair share of opportunities ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please speak on Supplementary Demands.

SHRI HASNAIN MASOODI: This was marketed by all the untruths. It was, in detail, referred to by one of the hon. Members.

Mr. Mahtab said that 'liberty does not start with Dr. Abdullah and end with it.' It is not a question of Dr. Farooq Abdullah only. It is the question of 10 million people, who are without internet facilities, without prepaid phone facilities for the last more than four months.

Article 21 does not only promise animal existence but a quality life; and a quality life you cannot conceive of without internet in the modern days.

Secondly, tomorrow, the 5th December, is the Birthday of Sheikh Mohammad Abdullah. I am told that the District Administration has allowed a few people to go and pray at his *Mazaar*. See, this is the kind of normalcy!

Now, let me come to the subject ...*(Interruptions)* He mentioned about the situation there. So, I have a right to respond ...*(Interruptions)*

माननीय सभापति: मसूदी साहब, मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Hon. Chairperson, even though the hon. Member is entitled to put across his views, and though it is not related to the debate that we are having, but we should not be misled by what somebody says.

Firstly, CBI jurisdiction was there. But after the UTI comes into being, that rider of taking consent is not there.

You would recall, just two years back, we had a very notorious Kathua Rape Case, which was covered all over India through all channels. It enraged the conscience of the entire Indian nation, but the then Government refused to refer it to CBI. That is one difference between then and now that the arrangement has been in put in place after 31st October ...*(Interruptions)*

I am telling you. I am not contradicting anything else. I will just put the record straight on technical points.

Secondly, as far the internet is concerned, it has been, time and again, reiterated by the hon. Home Minister in both the Houses that it is because of certain restrictions like internet that many of the untoward incidents could be averted. And, I tell you, how. I will give you two incidents. From Lakhnampur, which is the border town between Jammu and Kashmir and Punjab, there were militants on the run, who were being chased by the Forces.

There is another half-truth. Internet is not being suspended in Jammu Region. Only mobile network is suspended. People are using wi-fi. That is what is common practice these days, the moment youngsters entered into a mall or a corporate office, they immediately ask for the password if it does not automatically switch over. So, because of the absence of the mobile network, these militants, who were under chase, lost their way because they could not have their coordinates. They have a mechanism. This militancy, being sponsored by Pakistan, is following a pattern and, therefore, they got liquidated.

Similarly, there was another incident two months back when there were militants on the run from Kishtwar. The hon. Member, hailing from that place, would recall that there were serial killings happening in Kishtwar over the last one or two years. First, there were two BJP workers killed. Then, there was another social worker killed. So far, they could not be apprehended. Finally, when those killers were nabbed, they were on the run. They reached a place called Batote and when the forces were chasing them, because of the absence of mobile

network, they could not find their coordinates and, therefore, in desperation, they tried to stop a car. This car was being driven by a youngster who was very fast. He drove away and went to the nearby CRPF camp and the CRPF personnel then started chasing them. I am just giving you the evidential facts which you can check. The CRPF personnel chased them. They again lost their way. In confusion, they entered into a small street and entered into a house of a person who happened to be one of my booth workers. Luckily, this person was rescued and they were liquidated. All this has happened in the interest of the control of militancy. There is evidential proof. Since 5th of August, it has been by and large a violence-free season and, I think, in one of the most peaceful festive seasons in the last 20 years or 30 years. We had Eid. We had Ramzan. We had Independence Day. Then, we had another Eid. Now, the pain is that of some of the leaders are under arrest. There is also a view in a section that this peace has persisted because they have been under-arrest and this is not even house arrest. When Congress put Sheikh Abdullah under house arrest, I am sure the Members would bear me out.....(*Interruptions*)

कुंवर दानिश अली: यह चर्चा करनी ...(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: यह चर्चा करनी जरूरी है । ...(व्यवधान) It is because a point has been raised....(*Interruptions*) No, I am concluding now.(*Interruptions*) But I am entitled to put the record straight.(*Interruptions*) I have to put the record

straight. When I am entitled to put the record straight, I would rather say....(*Interruptions*) Adhir da, I am concluding....(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The Minister can intervene. Please sit down.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : अधीर बाबू बैठिए । दानिश अली जी बैठिए ।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): We have a right to respond....(*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: Yes, you have a right and I have a right to put the record straight....(*Interruptions*) Adhir da, I am, now, concluding with just two sentences....(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: You cannot encroach the territory of an hon. Member. ...(*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप बैठिए ।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record. Hon. Members, your words are not going on record.

...(*Interruptions*)... *

* Not recorded.

DR. JITENDRA SINGH: I am concluding. ...(*Interruptions*) I am not yielding. ...(*Interruptions*) Let me conclude. ...(*Interruptions*) I would rather say that Amit Shah is one of the most kind-hearted Home Ministers India has seen....(*Interruptions*) He has violated the definition of *jurisprudence*, putting these people under house arrest in their own houses!....(*Interruptions*) Look what Congress Party did when Sheikh Abdullah was put under house arrest. He was his party's patriarch. ...(*Interruptions*) He was sent 2,000 kilometers away to Kodaikanal. That is called house arrest. ...(*Interruptions*) That is the *jurisprudence* definition of house arrest. ...(*Interruptions*) Where is this house arrest? I think, Amit Shaw is being very kind....(*Interruptions*)

माननीय सभापति : अधीर रंजन साहब, आप बैठिए ।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : अभी क्या हो रहा है? ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अभी क्या है?

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अभी कुछ नहीं हुआ है । अभी वे आराम से घर पर बैठे हैं । ...(व्यवधान) These allegations are misplaced. ...(*Interruptions*) There are visuals every day in the newspapers. ...(*Interruptions*) The Sunday market is so crowded. ...(*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सदन को गुमराह कर रहे हैं । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मसूदी साहब, आप स्टार्ट कीजिए ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठिए ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मसूदी साहब, आप बोलिए ।

...(व्यवधान)

SHRI HASNAIN MASOODI : Sir, allow me to complete. ...(*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्लीज, आप डिमांड पर बोलिए ।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you are a very learned person.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Adhir da, after getting the permission from the Chair, the Minister can speak and he can intervene. ...(*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: I am just putting the record straight. ...(*Interruptions*) The Member has tried to mislead the House....(*Interruptions*) The Member has tried to mislead the House. ...(*Interruptions*)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: The Chair has given him permission. ...(*Interruptions*) He is a Minister. ...(*Interruptions*)

माननीय सभापति : चेयर की परमिशन से बोल रहे हैं । He is an hon. Minister. He can intervene.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: मसूदी साहब, प्लीज आप बैठिए ।

...(व्यवधान)

SHRI HASNAIN MASOODI: Sir, it is the entire population including 1.5 million students who are without net facilities. ...(*Interruptions*) By denying them net facilities, they cannot access the Prime Minister Scholarship Scheme and things like that. ...(*Interruptions*)

माननीय सभापति: मसूदी साहब, एक सेकंड बैठ जाइए । जितनी बार चाहेंगे रोक सकते हैं । This right is with the Chair.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): The hon. Minister is also a Member of this House. ...(*Interruptions*) He has got all the right to intervene and he is intervening. ...(*Interruptions*) What is wrong in it? Has he not got a right? ...(*Interruptions*)

माननीय सभापति: अधीर बाबू, आप बैठ जाइए; you are not permitted. Please sit down.

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Only the hon. Minister. Please cooperate.

... (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I have a request. Let him complete his speech.

After that, I would request you give five minutes to Dr. Jitendra Singh *sahib*.

...(Interruptions)

18.12 hrs

(Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष: आपकी हो गई बहुत डिबेट। अब आप शुरू कीजिए।

प्रो. सौगत राय: अध्यक्ष महोदय अब आप आ गए।

माननीय अध्यक्ष: हां, अब मैं आ गया हूँ।

SHRI HASNAIN MASOODI: Let me complete, Sir. I will take another five minutes only.

माननीय अध्यक्ष: हां, आप पांच मिनट बोलिए।

SHRI HASNAIN MASOODI: Now, let me come to the Appropriation Bill.

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): महोदय, हम भी आपकी पनाहों में पड़े हैं।

माननीय अध्यक्ष: आपको भी बुलाएंगे।

श्री अधीर रंजन चौधरी: स्पीकर साहब के आने से रौनक बढ़ जाता है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी बात रखें, आप जितना चाहेंगे उतना सदन चला लेंगे, लेकिन आप ही थोड़ी देर के बाद कहने लगेंगे कि माननीय मंत्री जी का जवाब होना चाहिए। आज किसी का क्लेरिफिकेशन नहीं होगा, जो बोलना है पहले ही बोल लें। मंत्री जी, आज किसी का क्लेरिफिकेशन नहीं होगा इसलिए क्लेरिफिकेशन का जवाब नहीं देना।

SHRI HASNAIN MASOODI: Sir, it is said that a provision of Rs.8,000 crore is made for Jammu and Kashmir. It is far less than what was promised and the dreams that were shown to the people of Jammu and Kashmir. In any case, whatever are the projected figures, they do not reflect the concerns of Jammu and Kashmir. To illustrate in civil aviation, the Awantipora Airport in south Kashmir stands transferred to civil authorities; no provision is made for that. Jammu and Kashmir produces 2.5 million metric tonnes of fresh fruit. There is infrastructure only for five per cent of the fresh fruit produced. There are no allocations or no demands for the Ministry of Food Processing industries and there is no provision for Jammu and Kashmir.

In the same way, coming to the Ministry of Health and Family Welfare, in far flung areas, we do not have any facility for basic health amenities to meet acute health problems like dialysis. Middle income families end up spending Rs.2 lakh to Rs.3 lakh on dialysis without any source to support.

If we talk about the Ministry of Road, Transport and Highways, Jammu and Kashmir highway remains blocked for 150 days in a year. Four tunnels are to be constructed. One tunnel is under construction and three tunnels are proposed. We do not have any promises made or any allocations made on the roads and highways.

Again, tourism is the backbone of Jammu and Kashmir. We do not have any fresh commitments and adequate allocations in this Bill. Nothing is earmarked to promote tourism in Jammu and Kashmir.

Now, I come to the Ministry of Women and Child Development. It is almost a non-starter. We had seven commissions there. One of the untruths on which the 5th August, 2019 decision was marketed was that they do not have a Women Development Commission and they do not have an Information Commission. We were pushed to stone-age. Jammu & Kashmir was projected as the place where there is maximum women participation. They are touching new heights. It was only after two months, there was a u-turn and they told us that you are living in stone-age and we are now going to push you on the path of development. In any case, seven commissions were wound up which were in existence. Hon. Minister knows about it. Nothing has been provided about that.

Again, in the case of Railways, a promise was made for Baramulla – Kupwara railway line. Nothing has been achieved on the ground and no provision is made in this Bill.

These are the key areas. There should have been thrust and focus on these areas in the current Bill but unfortunately, Jammu and Kashmir does not get the attention that was promised on the day of revocation of special status, that is on 5th August, 2019. They tried to market untruths projecting that all these facilities are available in Jammu and Kashmir and they wanted to push Jammu

and Kashmir on the path of development. So, from the view point of Jammu and Kashmir, it is disappointing. We expect hon. Minister to respond to all these things at the time we get the reply from the Minister to whatever has been projected.

Sir, I would take this opportunity to make a request for the discussion on Jammu and Kashmir. Hon. Prime Minister has promised on day one that we will go for a short duration discussion on Jammu and Kashmir. Time and again, we have been making a request. I would take this opportunity to make a request to hon. Speaker to ask the Government to agree to a short duration discussion so that all these points that are now to be dilated upon by the hon. Minister can be dealt in a dispassionate manner, in an objective manner, and in a fair manner during that discussion.

Again, tomorrow is birthday of baba-e-kaum, we call him father of the nation - Sheikh Mohammad Abdullah. Some unconfirmed reports are there stating that district administration will not allow even a small group of people to go to the *mazhar* to just offer prayers. This is the level of normalcy that is being projected. After all, he was the leader who went all the way to UN Security Council and Dr. Farooq Abdullah is the person who was deputed to Geneva to defend human rights of the country. Shri Omar Abdullah is the person who was the Minister of State in the Ministry of External Affairs under the Vajpayee Government.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बजट के अलावा शून्य काल में बोल लीजिएगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राजेन्द्र अग्रवाल जी चेयर पर बैठे थे, तब यह इश्यू चल रहा था।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य को दो मिनट बोल लेने दीजिए। इसके बाद दूसरे माननीय सदस्य बोलेंगे, फिर माननीय मंत्री जी बोल लेंगे। जम्मू-कश्मीर पर नई डिबेट शुरू हो जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, इन्होंने सिर्फ दो मिनट में क्लेरिफिकेशन करनी है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मसूदी जी, आप जम्मू-कश्मीर पर दो मिनट और बोल लीजिए।

SHRI HASNAIN MASOODI: Hon. Minister did reply to whatever I said earlier. There is no occasion for him to reply again. My request was that this cannot be a substitute for short duration discussion because that is going to be a frank, fair and dispassionate discussion where everybody will have a chance to speak. But now, in the name of normalcy, whatever is being stated, that is far from reality. How can you justify the arrest of political leaders across all the political parties?

Internet facilities for the 1.5 million students, hoteliers and businessmen are stopped. They cannot communicate with the rest of the world. They cannot receive orders. Businesses were affected badly.

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट में just to put the record straight because आपने ठीक कहा कि यह कोई शॉर्ट टर्म चर्चा नहीं है और इसको बनाना भी नहीं है। हमें सदन की मर्यादा के अनुकूल चलना है। पहली बात तो यह कहा गया कि कोई एक्ट नहीं लगे थे। वास्तविकता यह है कि भारतीय संविधान के 854 एक्ट हैं। There are 854 Central Acts. Out of which, less than 200 were implemented in the erstwhile State of Jammu and Kashmir and that too in truncated form. आपने कहा कि सारे एक्ट लगे थे। आपका जो करप्शन एक्ट था, वह आपने खुद ही नेशनल कांग्रेस ने बनाया था। अभी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसके अमेंडमेंट्स भी डीओपीटी लाई थी। ...(व्यवधान) अब आप ठहर जाइए, मुझे दो मिनट बोलने दीजिए। मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ। The amendment was brought in this House. As per that amendment, the bribe-giver is also now culpable to punishment and there is a fixed timeline of two years. यह सब नहीं था। इसके अतिरिक्त आपके यहां चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं लगाया गया। Now tell me, in which part of the world, which section of society will have objection to the Child Marriage Act? डौरी एक्ट आपके यहां नहीं था, राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट आपके यहां नहीं था। जो एक्ट लगाए गए थे, वे by default, truncated अपने ढंग से लगाय गये थे। आपको जो सुविधा लगी, उसको आपने लगा दिया। इंदिरा जी के काल में, इमरजेंसी में विधान सभा को छः साल करने के लिए 42 वां और 43 वां अमेंडमेंट आया। आपकी सरकार थी। शेख अब्दुल्ला ने तुरंत उसको छः साल कर दिया। जब मोरारजी भाई ने उसको रिवर्स किया, तब आपने नहीं किया। So, you were actually misusing this provision. शेख अब्दुल्ला साहब के जन्मदिन की बात आई है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। That is a whole political issue. It was an arbitrary subjective decision by the National Conference

Government to declare Sheikh Abdullah's birthday as well as his death anniversary as holidays. I am not raising objection to that. But simultaneously, there was a demand to have a holiday on the death anniversary of Shyama Prasad Mookerjee who had died in Kashmir. There was a demand to have a holiday on the birthday of Maharaja Hari Singh who had signed the Instrument of Accession. So, all these decisions were taken by pick and choose which suited a particular political party. We will talk about it in the Short Duration Discussion.

आपके यहां अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट अब लगा है । ... (व्यवधान) आप सीबीआई की बात कर रहे हैं । सीबीआई का पहले और अब का फर्क यह है, अध्यक्ष महोदय आपकी स्मृति में होगा, अभी दो साल पहले कठुआ कांड हुआ था । ... (व्यवधान) हां, वह मैंने बोला । आपकी सरकार, वहां दूसरी पार्टी की थी, लेकिन वह सरकार कश्मीर के अधीन थी, उसको रेफर नहीं किया । Now the CBI has a direct jurisdiction. अब पीड़ा इस बात की हो रही है कि जब सेन्ट्रल एक्ट सीधे-सीधे लग जाएंगे तो वहां जो कश्मीर केंद्रित राजनीति होगी या जो भी पार्टी होगी, वह अपनी सुविधा के अनुसार सीबीआई को रेफर नहीं कर पाएगी ।

जहां तक आपने हाउस अरेस्ट की बात कही है, मैं इस बात को कहकर समाप्त करता हूं कि ।

do not want to interfere with the debate on the Supplementary Demands for Grants. I would again reiterate this that Amit Shah Ji is one of the kindest Home Ministers we have ever seen. क्योंकि जब शेख साहब को नेहरू जी ने in spite of his personal bonding, sent him for a house arrest. He was sent 2000 kilometres away to Kodaikanal for 11 years. जहां तक हालात का ताल्लुक है, आप रोज विजुअल्स देख रहे हैं । जिस प्रकार की वहां संडे मार्केट है, It is such a busy Sunday market happening in

Srinagar. I do not think these visuals are required to be contradicted. The pictures speak the story.

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं एक प्रस्ताव लाना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में किसी पोलिटिकल लीडर को नहीं जाने दिया जाता है। वहां यूरोपियन एम्पीज़ आते हैं। मेरी तरफ से एक प्रपोजल है कि स्पीकर के नेतृत्व में ऑल पोलिटिकल डेलिगेशन एक बार जम्मू-कश्मीर चले। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जब मुझे जाना होगा, मैं चला जाऊंगा।

...(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, I start from where the hon. Minister left. In the Supplementary Demands for Grants, Rs.8,820.62 crore has been allocated for the Union Territory of J&K. Now this pitiable amount itself exposes the hallow claim of this Government to develop the Valley. I am sure the Minister knows what the Jammu and Kashmir Chamber of Commerce and Industry has said. It has said that since the removal of Article 370, economic loss of more than Rs.10,000 crore has happened. I am sure that you have forgotten that. But it is a statement of the Chambers of Commerce and Industry, Jammu & Kashmir that there has been an economic loss of Rs.10,000 crore.(Interruptions) सच्चाई चुभती है, मुझे मालूम है ।(Interruptions) I am not yielding.(Interruptions)

Now, I come to another point of disinvestment. The disinvestment target of the Government was Rs.1,05,000 crore. But they have realised only 17 per cent as of now.

Thirdly, I strongly oppose this infusion in IDBI Bank through recapitalization bonds. IDBI is a black box. LIC is a piggy bank. The Government has forced LIC in January 2019 to spend Rs.21,000 crore to buy 51 per cent equity in IDBI. Why IDBI? It is because of the scam of Shivashankaran. You are not able to pay the compensation to the States, the rightful share of the States in GST, which is constitutionally mandated, but you are very much interested in IDBI. I do not know

why. What is there in IDBI that the States cannot get their share of compensation? I strongly oppose the infusion of Rs.4557 crore in IDBI.

Fourthly, the revenue collection in April 2019 to October 2019, that is, seven months period, is Rs.9.3 lakh crore. The Budget Estimate is Rs.20.8 lakh crore in 2019. I want to know from the hon. Finance Minister what magic she has that she would collect the balance amount of Rs.11.5 crore in the remaining period of this financial year.

Coming to the net tax revenue, to meet the Budget targets, the Government needs to collect Rs.9.7 lakh crore in the period from November 2019 to March 2020. In the same five months last year, the Government could collect only Rs.6.6 lakh crore. Who are you fooling? Last year during the same period, the net tax collected was Rs.6.6 lakh crore and now you are saying that you will collect Rs.9.7 lakh crore from November 2019 to March 2020.

Let me now take corporation tax. The Government targets to collect Rs.4.9 lakh crore from November 2019 to March 2020. During the same period last year, you collected only Rs.3.9 lakh crore. These are data figures. I know you do not like the truth. Same is the case with income tax. To meet the target, the Government needs to collect Rs.3.2 lakh crore in the period from November 2019 to March 2020. In the same period last year, this revenue collection was only Rs.2.3 lakh crore.

So far as GST is concerned, to meet the Budget target, the Government needs to collect Rs.3.2 lakh crore in the period from November 2019 to March 2020. In the same period last year, the Government could collect only Rs.2.5 lakh crore. You are also foregoing Rs.4.5 lakh crore in Corporation tax. I want to know from the hon. Finance Minister whether the Government is going to the World Bank for this revenue shortfall or again you are going to fall back on LIC to make up your revenue shortfall and dress up your fiscal deficit.

Sir, LIC's cumulated investment in public sector was Rs.11.9 lakh crore in 2014. When the Modi Government came to power in 2014, they have done a great job. मुबारक हो आपको । At the end of Financial Year 2018-19, it jumped to Rs.22.6 lakh crore. I mean, from 1956 to 2014, the cumulated investment of LIC was Rs.11.9 lakh crore and within six years, you had utilized Rs.10.7 lakh crore of LIC. Amazing, Sir!

Sir, my last point is about the terms of reference of 15th Finance Commission. It is a very strong point, which I want to make over here. The Government is saying that defence and internal security allocation will be looked into. You are violating fiscal federalism. What have the States got to do with defence expenditure? It is a subject of the Union Government. What have the States got to do with this security aspect? Allocation to defence is the responsibility of the Union Government. That is why I say that it is against the spirit of parliamentary control over expenditure allocations.

I hope when the hon. Finance Minister stands up, she will definitely talk about the question which I have put to her.

Lastly, I was really surprised when the Minorities Minister made a public statement that 10 lakh people of minority communities would get scholarships. What is this, Madam? In fact, you have already cut down Rs.180 crore from Pre-Matric, Post-Matric, Merit-Cum-Means, and all these scholarships. What you are saying is not matching up with your budgetary allocations. I end up by saying - 'लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई।'

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात दो-दो मिनट में कह दें। जो माननीय सदस्य रह जाएंगे, उन्हें भाषण सभा पटल पर रखने की इजाजत दे दूंगा। लेकिन सभी ज्ञानी, माननीय सांसद दो-दो मिनट में अपना ज्ञान बोल दें।

डॉ. मनोज राजोरिया, आप दो मिनट में बात समाप्त कीजिएगा।

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अनुदान की मांगें, 2019 पर बोलने का अवसर दिया, लेकिन दो मिनट की समय सीमा रखी, इसके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप इस सीमा को बढ़ाएं।

माननीय अध्यक्ष : कोई गुंजाइश नहीं है।

डॉ. मनोज राजोरिया: अध्यक्ष महोदय, आज आपका भारतीय तिथि के अनुसार जन्मदिन है, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने 21,246 करोड़ रुपये की अनुदान की मांगों का बजट सदन में प्रस्तुत किया है, इसमें सरकार ने सभी पहलुओं का ध्यान रखा है, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कोई भी अन्य क्षेत्र हो। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के 50 करोड़ लोगों का पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा किया गया, वैसे राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उसे अभी तक लागू नहीं किया है। यह बात आम जनता के हित से जुड़ी है, इसलिए मैं आपके संरक्षण में आग्रह करूंगा कि इस विषय को गंभीरता से लें कि जो प्रधान मंत्री जी की नीयत है कि प्रत्येक गरीब परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले, उसमें राजस्थान सरकार सहयोग करे और आयुष्मान भारत योजना वहां जल्द से जल्द लागू हो। चाहे डिफेंस सर्विसेज हों या फाइनेंशियल सर्विसेज हों, मोदी सरकार ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से गरीबों को, युवाओं को रोजगार देकर पैरों पर खड़ा करने का काम किया है। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में लोन मेले लगाए हैं। जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, उसके लिए भी इस बजट में बहुत अच्छा एलोकेशन किया है। देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 और अयोध्या को लेकर गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से कुशलतापूर्वक देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी दुश्मनों से देश की रक्षा की है, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता

हूँ। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि गृह मंत्रालय के लिए आवश्यक बजट देने में उन्होंने कोई कंजूसी नहीं की। मैं अपने क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, यह बजट नहीं है, यह सप्लीमेंटरी डिमाण्ड है। आप बजट के समय मांग रखना।

...(व्यवधान)

डॉ. मनोज राजोरिया: महोदय, मेरे क्षेत्र में प्रधान मंत्री जी ने दो मेडिकल कॉलेज दिए हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : देखिए, माननीय सदस्य, हमें सांसदों को प्रशिक्षित करना ही पड़ेगा कि बजट क्या है और डिमाण्ड क्या है। यह संसद के अंदर ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगले सत्र में तैयारी करा देंगे।

श्री प्रहलाद जोशी: कभी भी सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स पर चार घण्टे डिसकशन नहीं हुआ है। आपने इजाजत दी है, अभी चार घण्टे हो गए हैं, इसलिए अब रिप्लाय करवा दीजिए।...(व्यवधान)

डॉ. मनोज राजोरिया: माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में धौलपुर और करौली, दो जिले आते हैं। प्रधान मंत्री जी ने दोनों जिलों के लिए मेडिकल कॉलेज दिए हैं, उनके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोनों जिलों को इसके लिए 325-325 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

मेरे राज्य की दो महत्वपूर्ण मांगें हैं और एक मांग मेरे संसदीय क्षेत्र की है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है। साथ ही, मेरे संसदीय क्षेत्र धौलपुर-करौली, गंगापुर सिटी रेल लाइन का एक विषय है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वित्त मंत्री जी इन पर भी ध्यान देंगी।

महोदय, बहुत सारे विषय थे, बजट के लिए बहुत सारी बातें थीं, लेकिन आपने दो मिनट की सीमा बांधी है, उसमें जो बातें अपने संसदीय क्षेत्र और राज्य से संबंधित थीं, उनको मैंने आपके सामने रखा है। आशा करता हूँ कि आप हमें अगली बार और समय देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमारी तरफ से एवं इस सदन की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह हमेशा मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें, यह हमारी इच्छा है।

सर, मैं अपनी पार्टी का अकेला स्पीकर हूं, इसलिए मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। I would like to use this opportunity to raise the 'Demands for Grants' for the State of Andhra Pradesh which have been pending for the last six years, since the time of bifurcation. Any Member who is present here from the previous Lok Sabha would also remember that whenever a Parliamentarian from the State of Andhra Pradesh was speaking, he or she had always raised these demands and that was part of his or her agenda. It is still an agenda. It has become a tradition which we are not able to break off even today because the Central Government has not fulfilled its part of the deal.

The assurances that were made as part of the Andhra Pradesh (Reorganisation) Act are still pending the way they were pending in the year 2014. That is why I reiterate my demands. One of the most important demands is the demand for special status. The assurance for special status has been given by the Party which is in power right now. They had spoken about it. They had assured the people of Andhra Pradesh that it will be granted when they come into power. But it is still pending. I take this opportunity to demand that as soon as possible the State of Andhra Pradesh should be granted the special status.

Let me inform this House, the Government, and the hon. Finance Minister also that there is no difference of opinion among the people of Andhra Pradesh about this. People cutting across caste, colour, community, creed, religion, and party are unequivocally demanding special status.

Other than that, educational institutions were promised. They were all granted. But that is not enough. Just granting of institutions is not enough. Allocating funds to build these institutions is also necessary. The agreement was to build these institutions in ten years. But six years have already passed. Only four years are left. It is the responsibility of the Central Government to complete them before this term. So, proper roadmap and planning should also be provided by the Central Government in completing these educational institutions.

A railway zone was also promised. Of course, South Coast Railway Zone has been established. But for starting this Railway Zone, adequate Budget allocation is very important. I have spoken with the Railway officials. They said that it would be put in the Supplementary Demands for Grants, but it is not seen anywhere. So, I would request again, through this House, that proper allocation for the new Railway Zone to the State of Andhra Pradesh also be made so that the initial infrastructure that is needed for starting the Railway Zone is built.

My next issue is Polavaram project. Around 72 per cent of the work has been completed. Our leader and also the former Chief Minister of Andhra Pradesh, Chandra Babu Naidu garu, was committed to this project. He took pride

in completing this project. As I said, 72 per cent of the work has been completed. So, the funds should continue to be given to this project. Proper release of funds should be ensured. Timely completion of this project be ensured for the welfare of the people of Andhra Pradesh. ...(*Interruptions*)

Other than that, I want to mention about the Capital, Amaravati. It is a very prestigious project not just for the State of Andhra Pradesh but also for the whole country. It is a futuristic Capital. It is a Capital of world-class facilities. The Andhra Pradesh (Reorganisation) Act specifies that funds will be allocated by the Central Government for the creation of this Capital. That is still pending.

Let me now come to Backward District Fund. The district that I come from, that is Srikakulam, was supposed to get an allocation of Rs. 50 crore per year. The fund was given for the first three years, but it was stopped for the next three years. Seven districts in Andhra Pradesh were notified as backward districts. I request that fund also be released.

Then, highway projects are very important. Many of the projects interlinking various parts of the State to Amaravati, the Capital, are also pending. For one project in my constituency, that is the NH 16 six-lane project, adequate funds have not been provided. I request that also may please be speeded up.

Several other prestigious projects like the Kakinada Petro-chemical complex have been mentioned in the Andhra Pradesh (Reorganisation) Act. All the assurances should be fulfilled by the Central Government. I request the

Finance Minister to reassure, in her reply, that all the assurances made in the Andhra Pradesh (Reorganisation) Act will be fulfilled by the Central Government in a timely manner.

I want to raise a couple of issues regarding the Supplementary Demands for Grants.

माननीय अध्यक्ष : नो ।

कुलदीप राय जी, आप अंडमान-निकोबार की मांग रखिए । आप एक मिनट में अपनी मांग रख दीजिए ।

नायडू जी, आपको बोलने के लिए तीस सेकेंड का समय दिया जाता है ।

...(व्यवधान)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: I want to raise only a couple of issues. I will take only one minute.

माननीय अध्यक्ष : आप इतनी देर से सप्लिमेंट्री डिमांड्स फोर ग्रांट्स पर क्यों नहीं बोल रहे थे?

...(व्यवधान)

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु: सर, वह आंध्र प्रदेश का सप्लिमेंट्री डिमांड था, अभी यह नेशन का है ।

माननीय अध्यक्ष : नो ।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु: सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात तीस सेकेंड में समाप्त करें ।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: While speaking on the Supplementary Demands for Grants, all the hon. Members who spoke before me made a mention

about the crisis that our country is facing right now, and about the state of the economy. That is why I would like to say that rather than looking at temporary solutions, I think it is time we look at permanent solutions on how to get the economy back on track. Unemployment is a very serious issue for the youth today. I hope the Central Government takes necessary steps to curb unemployment and also to improve the investments that are happening to improve the micro and medium level industries that are facing a lot of difficulties since demonetisation. These are some of the important aspects that the Central Government should look into.

The figures that are being spread regarding GDP, inflation etc., are very dubious. Different figures are coming out. So, the Central Government should give a proper picture, a clarity because unless we understand the problem, we cannot think about the solution.

So, the Central Government should come clean on the figures that are there right now. There should be no dubious figures. It should clearly pave the way for the future. There is two months' time for the Budget also. All the suggestions that have been given by all the different Members should be taken seriously and proper measure should be taken so that India gets back on its economic track. Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा जी, आप सीधे अंडमान और निकोबार के लिए जो माँगें हैं, वे रख दें।

श्री कुलदीप राय शर्मा (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं अंडमान और निकोबार की पूरी जनता की ओर से आपको जन्मदिन की बधाई देता हूँ।

माननीय वित्त मंत्री महोदया यहाँ पर बैठी हैं। जब मैंने सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को देखा, तो मुझे उसमें अंडमान और निकोबार के लिए कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मंत्री महोदया से मेरी माँग है कि अंडमान और निकोबार को एक साल में पाँच हजार करोड़ रुपये का बजट मिलता है, उसको बढ़ाकर कम-से-कम दस हजार करोड़ रुपये किया जाए। 10 हजार करोड़ रुपये इसलिए किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों मैं देख रहा था, जब दमन दीव और दादरा तथा नागर हवेली को मर्ज किया गया, तो वहाँ के सांसदों ने कहा कि दोनों यूटीज सात हजार करोड़ रुपये रेवेन्यू जेनरेट करते हैं। यह खुशी की बात है कि जो उनके पास रिसोर्स है, उनसे वे सात हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू जेनरेट करते हैं। अंडमान और निकोबार हर साल पाँच-छः हजार करोड़ रुपये के लगभग सेन्टर से लेता है। अंडमान और निकोबार के पास इतनी क्षमता है कि अगर फिशरीज़, टूरिज्म और अंडमान सी में जो गैस है, उसको सही तरीके से कैश किया जाए, तो हम लोग हर साल 10 हजार करोड़ रुपये सेन्ट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं। इस तरह से, हम पाँच वर्षों में 50 हजार करोड़ रुपये सेन्ट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं। हमको जो पाँच हजार करोड़ रुपये मिलते हैं, पाँच साल में 25 हजार करोड़ रुपये को मिला दें, तो 75 हजार करोड़ रुपये अंडमान और निकोबार देश को दे सकता है। हमारे प्रधान मंत्री जी पाँच ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, उसमें अंडमान और निकोबार कम-से-कम 75 हजार करोड़ रुपये कंट्रीब्यूट कर सकता है।

दूसरी बात, सप्लीमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात क्यों की जा रही है? आप देखिए, 1 लाख 47 हजार मिट्रिक टन फिशेज़ अंडमान सी में हैं। उसके लिए बजट में केवल 10.99 करोड़ रुपये एलोकेट किया गया। इतना बड़ा फिशरीज़ का स्कोप है और मात्र लगभग 11 करोड़ रुपये ही देंगे, तो इससे क्या होगा? इस तरह के बहुत-से इश्यूज हैं। आपने मुझे बहुत कम समय दिया है, मैं अन्य बातों में नहीं जाना चाहूँगा। एक मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूँगा। आप ज़ीरो आवर में तो दो मिनट का समय देते हैं, इसलिए कम-से-कम आज तो मुझे दो बातें बोलने का मौका दीजिए।

अंडमान और निकोबार में बहुत-से इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इश्यू अनएम्प्लॉयमेंट का है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट एलाउंस दिया जाए। हमारे यहाँ जो ओल्ड एज विडोज और हैंडिकैप्ड लोग हैं, उनको सिर्फ दो हजार रुपये भत्ते के रूप में मिलता है। महंगाई को देखते हुए, इसे बढ़ाकर पाँच हजार रुपये किया जाए। ऑगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और प्री-प्राइमरी टीचर्स को तीन हजार रुपये और नौ हजार रुपये मिलते हैं, उनकी सैलरी बढ़ाकर 15 हजार रुपये की जाए। ये सभी बेसिक डिमांड्स हैं। आज एक गरीब आदमी को जीने के लिए इतने पैसे की जरूरत है। एक आशा वर्कर मात्र तीन हजार रुपये में कैसे अपना परिवार चलाएगी? अपने परिवार को देखना, घर का किराया देना कभी बीमारी हुई, तो उसमें खर्च होता है। आप सभी बातों को समझते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। इस तरह के जो इश्यूज हैं, उन पर ध्यान दिया जाए।

मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अंडमान और निकोबार में 84 परसेंट फॉरेस्ट एरिया है। अगर वहाँ पर एक फॉरेस्ट कॉलेज खोला जाए, तो देश के लिए अच्छा होगा। हमारे यहाँ चारों तरफ पानी है, वहाँ मेरिन बायोलॉजी और फिशरीज़ के कॉलेज खोले जाएं, तो अंडमान और निकोबार के लिए बहुत अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। इस तरह के काफी इश्यूज हैं, जिन पर हमको काम करना है। इसके लिए पैसे की जरूरत है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप वहाँ पर वन-टाइम इनवेस्टमेंट कीजिएगा, तो उसके बाद अंडमान और निकोबार सेल्फ एफिशिएंट हो जाएगा और उसको सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir. This is the first batch of supplementary Demand for Grants of the second NDA Government of Rs.21,246 crore. For its sanction, approval of Parliament is required.

Out of the Rs. 21,246 crore, the cash outflow is Rs. 19,000 crore. The major demand is Demand No. 46 of Rs. 8,820 crore, that is, 40 per cent of the total Supplementary Demands for Grants is for the newly formed Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. We fully approve and support Demand No. 19 of Rs. 2,000 crore for Defence. I also fully support Demand No. 29 of Rs. 2,500 crore towards the recapitalization of the State-owned Insurance Companies. As regards Rs. 4,557 crore for capital infusion for IDBI, the matter has to be clarified as rightly stated by the hon. learned Member.

Regarding the Union Budget for the Financial Year 2019-2020, it was presented in the month of July and stamped by the Parliament in the month of August. Subsequently, Rs. 27.86 lakh crore have been stamped by the Parliament for spending by the Government. Out of this, from April to October, that is, in seven months you have already spent 59.5 per cent of the full year's

target. I would like to know from the hon. Minister that the Budget was passed in August, and day-before-yesterday we have discussed about the corporate income tax being reduced as a result of which Rs. 1,45,000 crore corporate tax is deducted. Now, you are coming with an additional expenditure of Rs. 21,000 crore as Supplementary Demands for Grants.

My question is this. The criticism that we had made during the course of discussion of the General Budget was that the Budget for 2019-2020 miserably failed in addressing the concerns of economic slowdown as well as the issues and concerns that were expressed in the Economic Survey of 2019. Those two criticisms are being ratified now. I am saying this because with regard to the economic slowdown the Minister and the Government are not accepting it and they are saying that there is no recession, but some issues are there.

I am confining my speech to two points regarding the GDP and fiscal deficit. Mr. Nishikant Dubey is not here. He has made a new philosophy regarding the GDP and I am not going into the details of it. If you see the first quarter GDP, it was 5 per cent and in the second quarter, it has come down to 4.5 per cent. GDP numbers have been declining for seven consecutive quarters. The hon. Minister, day-before-yesterday while replying to the Bill, has elaborately discussed that in 2018 also there was a decline, but subsequently it increased. But during the last seven consecutive quarters this has been declining, and it will be worst in the third quarter. This is being said by the economic experts. In the second quarter of the

year 2018-2019, it was 7.1 per cent. All this shows that we have lost the economic momentum in our country, and the fiscal position of both the Union and the State Governments are worrying with no clear solution in sight. This is the problem that we are facing.

Coming to the second point regarding fiscal deficit, it is only numerical. We are all common men, and we are not economic experts. Madam, while presenting the Budget, expected a fiscal deficit target of 3.3 per cent, but after all your stimulative measures, it is being expected that it will go up to 3.7 per cent or 3.8 per cent. It is not my opinion, but most of the economic experts in their research and study have stated that it will go up to 3.7 per cent or 3.8 per cent because of Rs. 1,45,000 crore corporate tax deduction and additional spending of Rs. 21,000 crore.

My specific question to the hon. Minister is this. How are you going to address the fiscal deficit target envisaged in the Budget for the year 2019-2020? Regarding tax collection, the data presented in the Parliament shows that direct tax collection plunged 17 per cent in October. This means that gross tax collection slipped further from 4.7 per cent in the first half of the year against the expected growth of 17 per cent for the full year. This is an alarming situation as far as tax collection is concerned, and the GST collection is also not encouraging. How are you going to address the basic issue of fiscal deficit? This is the basic issue that I would like to know.

I would like to make one more point. The Government is finding a solution in disinvestment like with BPCL. The UPA Government has invested Rs.20,000 crore in BPCL; the NDA Government subsequently, in the last year, invested Rs.20,000 crore. In total, Rs. 40,000 crore have been invested in BPCL. Now, concerning BPCL, 100 per cent proposal is there. How will that be legitimately explained by the Government after investing the huge money of the country in the BPCL? Now, it is for 100 per cent sale. Now, I would like to state that selling of the PSUs is not an option to address the fiscal deficit and the growth of the GDP. Please review the policy of disinvestment of BPCL and 11 other PSUs. Otherwise, this would be called selling of the national wealth. So, please review the policy. With these words, I conclude.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : महोदय, इस चर्चा में मेरा नाम लगातार लिया जा रहा है। भारत एक ऐसा देश है, जो कि दुनिया को रास्ता दिखाता है। पूरी दुनिया में रुपये की जो कनवर्टिबिलिटी है, वह वर्ष 1971 के बाद डालर में चली गई है। लेकिन जब भारत को अपने दोस्त रूस की मदद करनी थी, जब पूरा यूएसएसआर टूट-फूट गया था, तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश था, जिसने रुपया और रूबल की कनवर्टिबिलिटी स्टार्ट की थी। आप अमेरिकापरस्त कम्युनिस्ट राज्य से आते हैं, लेकिन जब आप अमेरिकन थ्योरी को अपनाते हैं, तो उसने ईरान और इराक पर बहुत बड़ा सैंक्शन इम्पोज़ कर दिया था। ईरान के साथ पूरी दुनिया में कोई भी बिजनेस करने को तैयार नहीं था। भारत ही एक ऐसा देश था, जिसने रुपये के साथ ईरान का साथ दिया और अमेरिका की बात नहीं मानी थी। पूरी दुनिया में अमेरिका की जीडीपी की जो थ्योरी है, उसके खिलाफ एक माहौल है और लोग यह चाहते हैं कि वह

थ्योरी बदले। कांग्रेस का, कम्युनिस्ट का और अपोजीशन का माइंडसेट ऐसा है कि वे उसको बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। महोदय, मेरा आग्रह इस सदन और आपसे यह है कि एक बार जीडीपी के बारे में चर्चा हो जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, एक मिनट।

माननीय अध्यक्ष : इनको भी एक मिनट बोल लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट के लिए बोल लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने इनको एक मिनट बोलने की परमीशन दी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैडम, आज आप किसी भी क्लैरिफिकेशन का जवाब मत दीजिएगा। मैंने यह व्यवस्था दे दी है कि आज आपके जवाब के बाद किसी का भी क्लैरिफिकेशन नहीं होगा।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, इस सदन में चर्चा के दौरान मैंने हमारी वित्त मंत्री जी को, जिनका नाम निर्मला है, उनको 'निर्बला' कहा था। हमारे ग्रामर में मैस्क्युलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर है। मैं निर्मला बोलने के पहले क्यों बोल रहा हूँ, मैंने इसके बारे में भी बयान दिया है। निर्मला जी, मेरी बहन जैसी हैं और मैं उनका भाई जैसा हूँ। अगर भाई की किसी बात पर मेरी बहन को कोई चोट पहुंची है, तो मैं उस पर खेद प्रकट करता हूँ।...(व्यवधान) दो बातें हैं।...(व्यवधान) महोदय, बस एक मिनट।...(व्यवधान)

महोदय, इस सदन में बहुत चर्चा हो रही है। मैंने ऑलरेडी एक प्रपोजल दिया है कि हमारे स्पीकर के नेतृत्व में एक ऑल पार्टी डेलिगेशन को कश्मीर में जाना चाहिए। हम यह देखना चाहते हैं कि कश्मीर की हालत क्या है। दूसरी बात यह है कि प्रेमचन्द्रन जी ने अभी-अभी प्राइवेटाइजेशन की बात की है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात की है। देखिए आज रोड का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सिविल एयरलाइंस का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अभी रेल में भी प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हो गया है। मैडम, आज रेल की हालत बहुत बुरी है, आपको उतनी जानकारी नहीं है कि ऑपरेटिंग रेशियो 140 प्रतिशत है। मतलब रेल को 100 रुपये कमाने के लिए 140 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। रेल का ऑपरेटिंग रेशियो 140 प्रतिशत है। आज 150 ट्रेनों को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। एयरलाइंस प्राइवेटाइज, रोड प्राइवेटाइज, रेल प्राइवेटाइज, यह नौबत कभी न आ जाए कि हमारी सरकार भी प्राइवेटाइज हो गई है। इसीलिए, मैं यह चाहता हूँ कि आप रेल के प्राइवेटाइजेशन को रोकने का इंतजाम कीजिए। पूरे हिन्दुस्तान की जो आर्थिक हालत है, वह जर्जर है। Under the leadership of Prime Minister, Shri Narendra Modi *ji* country has been facing the worst economic crisis.

***DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN):** I would like to express my views on behalf of my party Shiv Sena on the First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2019-2020 which has been brought by the Hon'ble Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman Ji and Minister of State Mr. Anurag Singh Thakur Ji. We are discussing additional grants to the tune of 21246 crore which include 17441 crore of revenue expenditure and 3804 crore of capital expenditure.

The Appropriation Bill has listed out the amount and purpose for this additional expenditure by various ministries.

The Government has been talking about a 5 trillion dollar economy but the recent GDP figure point to a grim picture and though our country is now ranked 77 in Ease of doing Business, but there are certain sectors of the economy which have witnessed decrease in demand and consumption resulting in slowdown in the economy. From the fastest growing economy we have now shifted to lowest growth rate in 6 years. There are certain systemic issues that the Government needs to tackle.

Some major provisions under this demand include:

The historic decision in the Monsoon Session to abrogate Article 370 and 35A taken by the Government has led to a new beginning for Jammu, Kashmir

* Speech was laid on the Table.

and Ladakh. This is a fulfillment of the dream of the founder of our Party Balasaheb Thackeray Ji and the Chief Minister of Maharashtra Uddhav Thackeray Ji. Shiv Sena has been consistent on its stand to remove Article 370 which created a barrier in the efforts to develop these regions. The Government is allocating Rs. 8820 crore as mandated by the award of 14th Finance Commission which include share of Revenue deficit grant ('5892.50 crore @1178.50 crore/month), local body grant ('725 crore) and SDRF ('139.50 crore) and State Share of net proceeds of taxes for month of November and December, 2019 ('2063.62 crore). The Government should now focus on developing the economy of these states keeping in mind their unique history and strategic location.

A big challenge that our economy is currently facing is the rise in NPA's and negative impact on banking sector. The Standing Committee on Finance in its 68th report has remarked in its report on the banking sector in India, where it observed that banks' capacity to lend has been severely affected because of mounting NPAs.

According to the latest RBI data, the flow of funds from banks and non-banks to the commercial sector has been Rs. 90,995 crore in 2019-20 so far (April to mid-September) against Rs. 7,36,087 crore in the same period last year.

Bank credit growth continues to languish, with similar trends observed in the NBFC space. There has been a fall in consumption demand, especially in home loans, auto and service segments; and decline in industry credit, primarily on account of risk aversion on the part of banks to lend to MSMEs.

The 2019 Nobel Prize winner for economics Abhijit Banerjee has said the current crisis in the Indian banking sector is frightening. Overall risk management at Public Sector Banks needs to be taken in a higher level. This certainly requires strengthening of PSB boards. We need to induct more high-quality professionals on PSB boards and compensate them better.

The case of IDBI is a glaring example of how banks are running into losses and Government is trying to revive them through recapitalization. After fresh capital infusion through this grant, IDBI Bank is expected to be able to subsequently raise further capital on its own and come out of the RBI's Prompt Corrective Action (PCA) framework which restricts a bank's normal lending. The IDBI Bank stock has dropped 53% so far in 2019, reflecting its poor balance sheet. It reported a loss of '3,801 crore for Q1 FY-20 compared with '2,410 crore in the year-ago quarter.

The Government has made a provision for recapitalization of IDBI Bank and state-owned insurance companies for which a provision of 2500 crore has been made.

1500 crore will be spent as additional expenditure towards payment of pay and allowance of armed forces and another Rs. 666 for meeting expenditure of Department of Space which includes Chandrayaan III, Polar Satellite Launch Vehicle Continuation Project, Liquid Propulsion Systems Centre, Laboratory for Electro Optics Systems and GSAT.

Major launches by ISRO during the last few years include Microsat-R, Kalamsat-V2, GSAT-31 India's Communication Satellite launch from French Guiana, PSLV-C45 successfully launched EMISAT and 28 customer satellites, PSLV-C46 successfully launches RISAT-2B and the landmark Chandrayaan Mission has made the country proud.

Our scientist and team at ISRO has made the whole country proud by their achievement and I would like to thank our scientist and ISRO on behalf of my party and the House for their role and dedication towards making India a technological superpower.

However an area of concern is the lack of funds for Department of Space which has seen a marginal hike in the budgetary allocation from Rs. 11,200 crore in 2018-19 to Rs. 12,473 crore in 2019-20. I would also request the Government to enlighten this house on the budget announcement of Public Sector Enterprise, New Space India Limited (NSIL) which has been incorporated as new commercial

arm of Department of Space to tap the benefits of the Research and Development carried out by ISRO.

One of the visionary schemes announced by our Prime Minister which not only changed the lives of women in rural areas but also promoted sanitation and healthy practices was UJJWALA yojana under which our Government provided free LPG cooking gas connection to the poor and I would congratulate the Ministry for reaching the target of 80 million connections in September this year, six months ahead of the planned deadline of March 2020. Through this demand the Government is also providing around Rs. 1,000 crore as additional funds under the scheme.

The economic survey 2018-19 has stated that ensuring that Ujjwala Yojana beneficiaries keep using clean cooking gas is a key task for the Government. A Petroleum Ministry study shows that the high cost of refills for a 14.2 kg cylinder is one of the main reasons why lower number of LPG cylinders are being used by BPL families. Therefore, I would request the Government to come up with Ujjwala 2 which includes provision for 5 kg cylinders and also a subsidy on refill to further expand the scheme and help rural household.

According to the Petroleum Planning and Analysis Cell, India's LPG consumption in financial year 2014-2015 stood at 18 million tonnes. During the

financial year 2018-19, LPG consumption rose of 24.92 mt, just 38 per cent higher than the 2014-2015 levels despite the number of connections doubling.

I would now like to bring to the attention of the honourable Minister certain issues which require the consideration of the Government:

In response to an RTI application it has been revealed that in the first quarter (April-June) of financial year 2019-20, the railways earned a revenue of Rs. 13,398.92 crore from passenger fare. This dipped to Rs. 13,243.81 crore in the July-September quarter.

Similarly, in the first quarter, the railway earned Rs. 29,066.92 crore from freight loading. In the second quarter, the earnings from freight came down to Rs. 25,165.13 crore. The slowdown also affected the ticket bookings, which witnessed a 1.27 per cent decline in April-September 2019, as compared to the corresponding period last year. Even suburban rail travel figures showed a decline of 1.13 per cent during this period, as compared to last year.

The Indian Railways recorded its worst operating ratio in 10 years in 2017-18 at 98.44%, as per the Comptroller and Auditor General (CAG) report laid yesterday in Parliament. The audit analysis of the finance accounts of Indian Railways revealed a declining trend of revenue surplus and the share of international resources in capital expenditure. The net revenue surplus decreased by 66.10% from Rs. 4,913.00 crore in 2016-17 to Rs. 1,665.61 crore in 2017-18.

The Minister Piyush Goyal Ji has today while replying in the question hour stated about the reasons for the same and how Government will address this issue and one of his suggestions of segregating the public utility and commercial functions during budget allocation needs active consideration.

As per Economic Survey 2017-18 (Volume -2), public health expenditure as percentage to GDP in 2017-18 (BE) was 1.4% as compared to 1.2% in 2013-14. Government has increased the total public health expenditure (Centre and States) from Rs. 1.49 lakh crore in 2014-15 to Rs. 2.25 lakh crore in 2017-18. In India, 65 per cent of health expenditure is out-of-pocket, and such expenditures push some 57 million people into poverty each year.

Budget Allocation of other countries as percentage of GDP-2017

Country	Percentage
USA	17.8
Switzerland	12.3
France	11.5
Germany	11.3
Sweden	10.9
Japan	10.7
Canada	10.4

Research by Observer Research Foundation stated that "new challenges posed by non-communicable diseases, are posing an additional burden on the healthcare delivery system, which is still geared more towards and communicable, maternal, neonatal and nutritional health conditions. Adapting to the fast-changing disease transition requires significant additional financial resources within the health sector.

A study by the Center for Disease Dynamics, Economics and Policy indicates that India has a shortage of an estimated 600,000 doctors and two million nurses. A lack of skilled labour in administering antibiotics is preventing patients from accessing life-saving drugs and contributing to a crisis of antibiotic resistance in the country. The lack of skilled labour is pronounced in the healthcare sector, with around 25 percent of India's healthcare workforce lacking the necessary qualifications.

This staff crunch across the country needs to be addressed at the earliest to ensure an effective healthcare delivery system. Can providing insurance through Ayushman Bharat work, if there is a lack of quality service being provided?

The Lancet Commission finding for India claims that a \$ 1 investment in health would yield at \$ 10 increase in GDP by 2035. At a time when India is struggling with an employment crisis and economic slowdown, it is imperative to

utilise the healthcare sector as a growth driver along with acting as a catalyst to improve the social well being of its population.

I would also like the Government to give a status report on the Budget Announcement related to Healthcare from 2014 and what is the progress in the same.

Year	Announcements
2014	<p>1.Free Drug Service and Free Diagnosis Service to achieve "Health For All".</p> <p>2. 12 new government medical colleges to be set up.</p>
2016	1.National Dialysis Service Program with funds through PPP mode to provide dialysis at all district hospitals.
2017	1.Mahila Shakti Kendra will be set up with an allocation of Rs. 500 crore in 14 lakh ICDS Anganawadi Centres. This will provide one stop convergent support services for empowering rural

	<p>women with opportunities for skill development, employment, digital literacy, health and nutrition.</p> <p>2. Additional 5,000 Post Graduate seats will be created per annum to ensure adequate availability of specialist doctors to strengthen Secondary and Tertiary levels of health care.</p>
2018	<p>1. 24 new Government Medical Colleges and Hospitals will be set up, by up-grading existing district hospitals in the country. This would ensure that there is at least 1 Medical College for every 3 Parliamentary Constituencies and at least 1 Government Medical College in each State of the country.</p>

The MoHUA has already released INR 99.4 billion to states under the Smart Cities Mission as revealed by the government data of February 2018. An outlay of INR 500 billion has been earmarked for AMRUT for five years ending 31

March 2020, INR 5 billion has been set aside for HRIDAY, while the Swachh Bharat Mission – Urban has received INR 27.5 billion just for FY 2019-20. However, these schemes provide external sources of funding and do not address the important issue of revenue enhancement of municipal corporations, which form the backbone of these cities. While they end up tackling some aspects of urban rejuvenation, none of these schemes address the root of the problem by solving issues of municipal funding.

Today, the municipal revenues of cities in India account for 0.75 percent of the country's GDP, against cities of BRICS countries such as Brazil (8 percent) and South Africa (6.9 percent).

The 74th amendment of the Constitution, under its 12th schedule defined 18 functions of Municipalities. It is seen that only 12 of 18 functions have a corresponding finance source while the municipal corporation is expected to take care of all functions. A 2014 Reserve Bank of India study titled 'Municipal Finance in India – An Assessment', studied the finances of 35 ULBs in India and found the "mix of municipal revenues in India – taxes, user charges and fees, transfers and loans – is narrow compared to international benchmarks with regard to the financing of local public services.

Several projects aimed at making train commute smoother and expanding capacity of the suburban network are yet to take off.

One such project is the segregation of the long-distance and local train traffic sanctioned under the Mumbai Urban Transport Project (MUTP) 2 in 2010. The aim was to create additional lines and stop trespassing to reduce the pressure on suburban lines and improve the frequency and speed of trains. However, the work on the fifth and sixth lines between Kurla and Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT), and the Thane and Diva has been going slow, with the deadline for the latter being extended from 2019. Also, there is not much progress on the work on the sixth line between Mumbai Central and Boriveli.

Sanctioned in 2015-2016, MUTP-3 is another project that is stuck. It includes doubling the existing Panvel-Karjat railway line, quadrupling of Virar-Dahanu railway line and acquiring 47 new AC local trains. The Railways are yet to make loan arrangements to begin the work. The land acquisition for the project is expected to start in a few months.

I will conclude my speech with the suggestion that the Government should take urgent steps to fix the issues plaguing the economy and not deny it.

***SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI)** : Hon'ble Finance Minister presented the first Supplementary Budget for 2019-2020 to the tune of Rs. 21.246 crore to meet various expenditure.

The Indian GDP now is 4.5%, I urge upon the Government to take serious steps to save the Indian economy.

Two days back when the taxation law was passed I demanded to know from the Government what impact it has on reduction of corporate tax especially in the investment, job creation and public spending. But, there has been no impact. Instead of job creation more youths are losing the job instead of investment, more companies are reducing the employment then what is the need for reducing the corporate tax.

This Government is making tall claims that economy will grow into 5 trillion dollar in 2024 but what steps taken to achieve this, the Government claims that it would invest 100 lakh crore infrastructure I want to know whether it is possible considering the current situation. LPG price is going up every month having severe impact on the Budget of middle class and poor people.

* Speech was laid on the Table.

The pinch will be largely felt by the salaried and professionals, about income tax rates? Why they have not been decreased? If the Government decreases the personal income tax, people would have more money in their hands and the consumption would increase and the economy would be revived. But the Government is clueless about reviving the economy. The Government is taking ad hoc measures, but they have not taken any concrete steps. Again, in the next budget, they will tinker the taxation system because they do not have any taxation policy or any programme or roadmap to revive the economy.

Many of the other home appliances, the GST is levied at the rate of 18% in order to give a boost to the consumerism which would result in more economic activities in the country the Government should reduce the GST to 5%. On some of the home appliances the GST is levied at the rate of 28% even. For example, a smart TV is levied at the rate of 28% GST. This rate should be reduced to 18%.

Restaurants and others have to pay 18% GST on rent which results in increase in the price of goods and services they offer. I request that the GST to be reduced to 5% in order to provide relief.

In Madurai there is a proposal to set up an AIIMS at the cost of Rs. 1264 crore but for this year I want to know how much money has been allocated I understand that only 5 crore has been allocated. With this rate this project will

never see the end of the day even after 5 years how the project is proposed to be finished by 2022.

Last year the then Minister of Chemical and Fertilizer made the state that NIPER would be set up at Madurai at the cost of 1100 crore but so far no single rupee has been allocated I want to know from the Government. This Government makes only announcements but takes no action to fulfill it.

I also made a request for allocation of money for the following long pending public demands, in my Constituency:

To promote tourism projects, to setup Helipad at Kanyakumari and Airport at Swamithoopu; Rs. 178 crore for upgradation of Government Hospital at Nagercoil to Multi Specialty Hospital; to repair and maintenance of NH-47 and NH-9 from Kaliyakavilli to Kavalkinaru. Request to widening the service lanes under the Marthadam flyover. And also FOB is required at Thengapattinam to Iraiyananthurai to save the fishermen at the time of emergency; to save the fishermen village and their house from sea erosion, the 72 kms. Length of sea shore to be covered by concrete walls and Tetrapod to save the concrete walls. To set up number of Fisheries harbour at Kanyakumari; to set up Coastal Guard station at Kanyakumari; to set up Rubber Park, Industrial cluster for rubber product to save the Rubber Industry and Honey Research Centre; long pending public demand in Railway to upgrade Kanyakumari, Nagercoil station to be world-

class standard, and a train between Chennai to Kanyakumari in Night time, and also to construct ROBs and RUBs in my Constituency, like Kappiyarai, Kuzhithurai-Eraniei, Virikoddu, Marthandam, Agastheeswaram; (Over bridge is required at Inter-locked level Crossing No. 15 KM 215/500-600 between Kuzhithurai and Eraniei Railway Stations near Viricode on Marthandam – Karungal Road. Sub-way (Foot over bridge) near Kuzhithurai Railway Station to cross over the Railway Line for the use of General Public. Over bridge is required at Kappiyarai-Karavilai Railway level crossing no. KM266/3-4 and Br. No. 207 between Kuzhithurai and Eraniei stations. Underground Tunnel Road is required at Madathuvilai Railway level crossing No. KM263/9 near Palliyadi Railway Station. Underground Tunnel Road is necessary to cross over to other side (agricultural land) at Nagercoil Town Railway Station No. KM285/10-11 for the convenience of local public.) To set up a National Tourist Circuit to join Kanyakumari; to remove the legal hurdle points in Neyyar channel for getting water for the benefit of people of my Kanyakumari Constituency; in the AVM Channel, necessary maintenance has not been taken up, with the result that salty water gets mixed with the general supply; to set up facilitation center with free legal aid and also Toll free number at all Indian Embassy to save the Indian Citizen at foreign land;.

I demand the Government to allocate necessary funds and to take concrete steps to complete all the projects in my Kanyakumari Constituency. I urge upon the Government to revive the economy at the earliest.

***SHRI SAPTAGIRI SHANKAR ULAKA (KORAPUT):** Through the Supplementary Demands for Grants, I would like to put some key demands of my constituency-Koraput (Odisha) that required urgent attention of the Government:

(1) Rs. 935 crore was allocated for Gunupur-Therubali railway line in the Central Budget. Unfortunately, this project has gone on the back burner citing negative RoR and only Rs.10 lakh was allotted in the current budget. I would urge on the Government to allocate more funds to this project and revive the project.

2. A new day time train from Jeypore/Koraput to Bhubaneswar via Rayagada has been a long-standing demand. I would request the Government to approve the same with necessary allocations.

3. Jeypore-Malkangiri and Jeypore-Nabarangpur rail project needs the urgent attention of the Government. I would request the Government to allocate necessary funds to fast track the projects.

4. I welcome the decision of creation of Rayagada Division. With development, comes the responsibility of rehabilitation. I would urge on the Government to help rehabilitate 3000 plus families.

* Speech was laid on the Table

5. I have repeatedly stressed on the necessity for the construction of Rail-cum-Road bridge over Kolab reservoir between Suku and Koraput under Kothavalasa-Kirandul Railway line. Due to submergence by the Kolab reservoir about 25,000 residents have to cross 60-70 kms via Nandapur and Semiliguda to reach Koraput. I would request Rail-cum-Road bridge in 500 meters section in Kolab region which will allow road connectivity to these cut off areas.

6. Six GPs of Lamtaput and Koraput blocks are detached from main land due to storage of water in the Kolab reservoir for construction of Kolab Dam project. The request is for immediate construction of 1200 meters road over Kolab reservoir under CRF.

7. NH 26 and NH 326 are in dilapidated status due to heavy rainfall and wear and tear. I would request Government to allocate necessary funds and repair the roads. Also the bypass around Jeypore Koraput and Rayagada needs to be completed at the earliest. Also I would require the approval of new bypass road in Kakiriguma (NH 326).

8. The road between Bhawanipatna to Parvatipuram via Rayagada needs to be declared as National Highway and four lane construction needs to be taken up immediately.

9. Rayagada and Koraput districts in Southern Odisha are filled with rich tribal culture, lush valleys, wildlife, religious and historical heritage and provides huge

potential for development of tourism and job creation. I would urge upon Mithe Government to approve 'tribal' and 'religious' circuits under 'Swadesh Darshan Scheme' that has huge potential for development of tourism.

10. I would request the Government to consider and accord 'Bali Yatra' festival status of 'National Maritime Heritage Festival'.

11. The Ministry of Tourism has identified 17 sites in 12 clusters for development under Iconic Tourist Sites Development Project. Unfortunately, key tourist destinations in Odisha couldn't find a place in list of iconic tourist sites. Kindly consider 'Puri' or some key tourist destination in Odisha in the list of iconic tourist site.

12. History of Indian freedom struggle is full of stories of courage and determination. Papadahandi in Nabarangpur District is one such place which still carries the scars of one of the bloodiest massacres in Indian history. I would request you to kindly consider declaring 'Sahid Minar' in Papadahandi a 'National War Memorial'.

13. Mobile connectivity is not available in most of the areas in my constituency. No single tower has been constructed by BSNL in my constituency since last 2-3 years. 51 GPs in Koraput district and 69 GPs in Rayagada district have little or no network coverage. I would urge Government to advise BSNL to provide mobile connectivity by setting up mobile towers. Also I would request Government to ensure BSNL provides 4G connectivity in these areas.

14. The Cabinet Committee on economic affairs chaired by PM has given its approval for establishment of 75 additional Government Medical Colleges by 2021-22 attached with existing district/referral hospitals under Phase-111 of ongoing Centrally Sponsored Scheme. Rayagada being one of the most deserving districts given the social and economic condition, I would request the Government to approve the establishment of Medical College at Rayagada attached with Rayagada DHH.

15. 1500 villages in Rayagada and Koraput districts are still not connected by all weather roads under PMGSY. Kindly provide additional funds to construct roads and connect the villages.

16. KBK special fund, IAP and other centrally sponsored schemes are discontinued. I would urge upon the Government to provide special funds for undivided Koraput District which needs all the support from the Government.

***SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR):** प्रति सप्ताह, माननीय सदस्यगण जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय दुर्दशा पर अपनी आवाज़ उठाते हैं । India ranks 120 among 131 countries in female labour force participation rates and rates of gender-based violence remain unacceptably high. It is hard to develop in an inclusive and sustainable way when half of the population is not fully participating in the economy; in India labour force participation of women is quite low. There are many reasons and one of them is insecurity. Women just don't feel safe to go to school or to go to work. It is a fixable problem. It requires a commitment to make it safe. International Monetary Fund Managing Director Kristaline Georgieva said recently multiple research studies have shown that safety along the route of offices and colleges plays a major role when women are assessing their education and professional options. Innumerable number of women don't join educational institutions they're eligible for, jobs they are qualified for simply because it is not safe for them to get there; there are umpteen reports of rapes and molestations across media channels on daily basis. How is it that we are a country that is safer for cows than women? Even after spending an additional 3387.5 crores on revenue expenditure of police over and above the budgetary allocation, why is it that there is no improvement in the safety conditions of women; be it in rural or urban areas? According to Mckinsey, increasing women's labour force participation by 10 percentage points could add \$ 770 billion to

* Speech was laid on the Table.

India's GDP by 2025; Reaching gender parity would have a bigger impact in India than in any other region in the world; by not ensuring a safe environment for our women, we are not only hurting them but also the economy of the entire nation.

I would like to ask the Honourable Finance Minister, what is being done to boost consumer demand? As many members of the House have already mentioned, until we get

मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि लोगों की जेबों में पैसा डालने के लिए ये सरकार क्या कर रही है ? नोटबंदी और GST के खराब परिपालन के बाद, मेरे क्षेत्र के तमाम युवा बेरोज़गार ।

According to Nielsen, a global market research firm, rural household consumption slumped to a 7-year low in the September quarter which is a sign that the prolonged agrarian distress and near-stagnant rural incomes have eroded demand for consumer goods.

We have now entered the 6th consecutive quarter of slowing growth. For a nation that was supposed to overtake China and become one of the world's superpowers by now, we're doing awfully poor.

Himanshu, a professor at Jawaharlal Nehru University's Centre for Economic Studies and Planning, said: "In the last five decades at least, there has never been a period that consumption expenditure in real terms has declined. This data clearly shows that poverty levels would have gone up substantially. A

back of the envelope calculation would suggest that the percentage of population in poverty would have gone up by at least 10 percentage points."

न जल के राख हुए हैं, न आग भड़की है
न पूछ कैसे मंजिल से हम गुजर रहे हैं
हवा में जहर की यूं हो गई है मिलावट
कि सांस लेते हुए भी हवा से डर रहे हैं ।

***श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** सरकार अनुदानों की पूरक मांग लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी । इसलिए जिन मांगों का उल्लेख वार्षिक बजट में शामिल नहीं था । उस समय उन आवश्यकताओं को दृष्टिगत सरकार के संज्ञान में नहीं था, लेकिन अब जब सदन में माननीय सदस्यगण नियम 193 के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में दैवी आपदा एवं किसानों के फसलों को हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग उठ रही है, इसलिए सरकार ने एडीशनल एलोकेशन टू द स्टेट गोवर्नमेंट फॉर द नेशनल डिसेस्टर रिलीफ, फंड के लिए इस अनुपूरक अनुदान में दस हजार (10,000) करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । इससे परिलक्षित होता है कि सरकार किसानों के लिए अतिसंवेदनशील है इसीलिए सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता में किसान हैं । भारत में हमारी सरकार ने जम्मू काश्मीर से धारा 370 एवं 35ए को समाप्त किया है । आज जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, दो नये यूनियन टेरिटरी का सृजन हुआ है । इसलिए यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 14वें वित्त आयोग के अवार्ड के बेसिस पर रेवेन्यू डेफीसीट के लिए 5892 करोड़ दिया जा रहा है । जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के विकास के लिए सरकार ने कइ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिससे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में केन्द्र सरकार ने 12 लाख मीट्रिक टन सेव उत्पादकों को खरीदने का काम करेगी जो प्रदेश के कुल उत्पादन का 60% है । केन्द्र सरकार ने 85 केन्द्रीय योजनाओं को लागू किया गया । केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए फौज में 2780 की भर्ती होगी । बी.एस.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ. में 1356 भर्ती होगी करीब 45000 करोड़ रुपयो के योजनाओं को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में स्थापित किया जायेगा । भविष्य में लद्दाख सोलर इनर्जी का पावर हब बनने जा रहा है करीब 7500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लद्दाख में लगाने का निर्णय केन्द्र सरकार ने किया है । जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में यूनिवर्सिटी, मेडिकल

* Speech was laid on the Table

कालेज एवं स्टेडियम केन्द्र सरकार ने स्वीकृत किया है । भविष्य में 80% योजनाओं को स्थानीय लोगों के द्वारा स्थापित किया जायेगा । इसी तरह आईडीबीआई बैंक (इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया) को 4557 करोड़ रुपया रिकैपिटलाइजेशन के लिए दिया जा रहा है जिससे उसमें जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सके तथा उनका पैसा सुरक्षित रहे ।

हमारी सरकार ने अपकीपींग ऑफ श्राइन, टेम्पल इत्यादि (प्रोटेक्शन & अपकीपींग ऑफ अयोध्या के मंदिरों के संरक्षण एवं आयोध्या के रख रखाव के लिए 20 करोड़ का प्रावधान अनुपूरक अनुदान में किया गया है । हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस सदन के सदस्य हैं भविष्य में इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि हमलोगों ने नये लोक सभा के डेवलपमेंट और रिडेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए 33.3 करोड़ रुपये का प्रावधान इस अनुपूरक अनुदान में केन्द्र सरकार ने व्यवस्था की है । देश के गरीब एवं निर्धन महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय को 1000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है । इस अनुपूरक अनुदान में आर्मी एयरक्राफ्ट एंड इंजीनियरिंग के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है । नेवी के लिए 1250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है देश के छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एयरपोर्ट ऑथरिटी की रिजनल कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ रुपया दिया जा रहा है जिससे चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में हवाई यात्रा कर सके ।

इस अनुपूरक अनुदान में साइक्लोन (फेन) के लिए (इंडियन कौंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च) 41.7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के लिए (Tribal Area) के लिए 85 करोड़ रुपया की व्यवस्था की गई है कृषि के प्रसार के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । पहली बार फॉर्मेशन एंड प्रोमोशन ऑफ फारमर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के गठन के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । ऑर्गेनिक वैल्यू चेंज डेवलपमेंट फार्मिंग

(एन.ई.) के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था की गयी है । नेशनल ससटेनेबल एग्रीकल्चर के लिए 14.8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । देश के सैनिकों के पेमेंट एवं एलाउन्सेज के लिए आर्मी को 1500 करोड़, नेवी के लिए 300 करोड़ तथा एयरफोर्स के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । अतः हमारी सरकार ने जिन योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान नहीं था लेकिन आज उसकी आवश्यकता पड़ने पर प्रथम अनुपूरक अनुदान लाकर के उन योजनाओं को पूरा करने का संकल्प लिया है । इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले सभी जो सांसदगण हैं, nineteen of them, जिन्होंने इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के विषय पर चर्चा में भाग लिया, उन सबको धन्यवाद कहना चाह रही हूँ। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जिनको एक माननीय सदस्य ने उठाया, उसी को दूसरे और तीसरे माननीय सदस्य ने भी उठाया है। मैं हर विषय पर जवाब देने की कोशिश करती हूँ। अगर आपके आदेश के अनुसार, पिछली बार मुझे याद है, आपने कहा था कि जिन सदस्यों ने प्रश्न पूछा है, अगर वे सदस्य अभी जवाब के समय नहीं हैं तो उनका जवाब देना आवश्यक नहीं है। मैं उसका पालन करना चाहती हूँ। इसीलिए 19 लोग हैं, उनके नाम मैं स्पीडीली पढ़ लेती हूँ। डॉ. शशि थरूर, श्री राजीव प्रताप रूडी, it is not in a particular order, श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., प्रो. सौगत राय, श्री विनायक भाउराव राऊत, श्री पी. वी. मिथुन रेड्डी, श्री भर्तृहरि महताब, डॉ. जी. रणजीत रेड्डी, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री निहाल चन्द, श्री सु. थिरुनवुक्करासर, श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, कुंवर दानिश अली, श्री हसनैन मसूदी, श्री असादुद्दीन ओवैसी, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री राम मोहन नायडू किंजरापु, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, और आखिर में श्री अधीर रंजन चौधरी जी ने ज्वाइन किया था।

Specifically, Supplementary Demands for Grants do come once or even twice in a financial year. This is the first batch of Supplementary Demands for Grants....(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मैं एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ। एक मिनट विराज जाएं। मैं बीच में टोकूंगा, वह ठीक नहीं लगेगा, इसलिए अभी समय की व्यवस्था दे देता हूँ। आज सदन का समय आप सब की सहमति हो तो विधेयक पास होने तक बढ़ाया जाए?

...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ महोदय । ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : सर, उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल भी पास करना है । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बिल पास होने तक नहीं, बिल की समाप्ति तक सदन का समय बढ़ाया जाता है । यह टैक्निकल शब्द किसी ने मुझे बताया था कि पास होने तक नहीं, बिल समाप्ति तक होता है । पारित हो या नहीं हो यह तो हमें पता नहीं है न ।

... (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the first batch of Supplementary Demands for Grants of 2019-20 is what have been discussing for the last couple of hours. In this discussion, about sixty-four grants out of hundred and two appropriations have been discussed. So, not all of them are on discussion. In these demands and appropriation, authorisation is being sought for gross additional expenditure of Rs. 21,246.55 crore. Some come under capital expenditure and some come under revenue expenditure.

For just one minute, I would like to elaborate on the three heads under which Supplementary Demands normally come. The first, wherein you were talking about cash Demand for Supplementary Grants, comes under the cash outgo head, the second comes under the technical supplementary and the third comes under token supplementary. So, as always and forever, in the scheme of budget and budget process, Supplementary Demands for Grants which normally derive from the Budget, which have been passed normally not beyond the Budget, is only under these three categories.

Now, why do they get categorised under these three categories? I just want to broadly tell you about the cash outgo under which comes the J&K, if I take that example. The allocation of Rs. 8,820 crore comes under a different heading altogether. Although we are dealing with the 14th Finance Commission's awards and this is the last year of that award, the award amount is, as decided by the formulation, given by the 14th Finance Commission. I will tell you the reason why we have to now state it. Let me please dispel this notion that this is all being given for J&K, not at all.

19.00 hrs

Under the 14th Finance Commission award, this being the last year, whatever has been given for Jammu & Kashmir as a State now has to also go to a different Head or a line which puts Jammu & Kashmir as a Union Territory with an Assembly and which puts Ladakh as a Union Territory. So, what was given for the united State of Jammu & Kashmir has now got to go to a different Head for Jammu & Kashmir as a Union Territory with Assembly and for Ladakh as a Union Territory. Hon. Members will obviously be aware, I do not want to say it here in so many different words, that Union Territories draw from the Centre's Pool, and States get it directly from the Consolidated Fund of India because they are devolved directly post the Finance Commission's awards.

In the course of 14th Finance Commission's tenure itself it so happens that the Union Territories have come into being from the 31st of October. So, the devolution should happen to it even within the term of the 14th Finance Commission which has already dealt with it as one State. So, naturally the line or the Head under which it has to go has to be redone. Therefore, we are now putting it under the Supplementary Demands. It is not that we are just giving only Rs.8,000 crore and the story has ended. The need for it to come is because, as all hon. Members are aware, any small change in the Budgetary Heads, vertically or horizontally, will have to come for approval in this hon. House. Therefore, Jammu & Kashmir comes here. So, let me please remove this thought from all your minds that this is all that we give to Jammu & Kashmir, they need a lot more. Obviously, they need a lot more and that will now come through the 15th Finance Commission's recommendations like everybody else is going to get it through the 15th Finance Commission's recommendations. This is for the last year. So, that is one of the reasons why the amount is what it is. It is part of what it was in the larger Budget of July. We have now only sought to appropriate it through a different Head because the status is different; it is no longer a State, it is a Union Territory. That is one explanation.

Now, recapitalisation for the insurance company also comes under this net cash outgo head, the first heading under the Supplementary Demands for Grants, so do the pay and allowances and so does the space project. I was a bit hurt to

hear Prof. Sougata Roy tell the whole House that you need to give ISRO the space programme now that they have failed at Chandrayaan-2. Professor, you are fairly familiar with how experiments work, especially in frontier sciences. Do you think one hard landing is a sign of failure? The entire world admires our ISRO. I would not want a senior Member like you to come and say in this House - which feels extremely proud of ISRO and I am sure, going back home you will feel extremely proud about ISRO – why should you give this money. ...(*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: Somebody should reply for the failure, why it broke down. ...(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: That is a different story. But then to deny them funds, I do not think anyone would suggest. I am sure your intention is not to punish ISRO; your intention is also to say, please do it next time better. But that does not mean that we should stop the money which should go to them. I am sure the entire House and you too in your heart of hearts agree to it. So, I will allow that.

So, this is the way we explain what goes out under cash supplementary, which is the first heading under which we come for any Supplementary Demands for Grants.

The second is the technical supplementary under which we have quoted Rs.2,249.37 crore of which Rs.1,000 crore go to the local bodies as grants and the other part goes for the LPG for poor households. Now, why does the technical

supplementary happen? Technical supplementary happens when there is a change from one to another within a particular Ministry, if there is some expenditure here and moves over, which I would call not so technically a horizontal movement from one heading to another within a particular scheme. It could be revenue which was voted for revenue moving to capital which is voted for capital, or the other way round. So, the need for us to come to the House for an approval or ask for a supplementary grant, clearance from this House is needed because the heading change is there, revenue to capital or capital to revenue.

The final one is the token supplementary. Within a particular grant and within the same section which is within the same silo, if it moves from one heading to another, then this token supplementary happens. That is why Rs.1.28 crore are being sought here for approval under the token supplementary.

So, supplementary demands for grants is looked at from these different silos. This is nothing beyond what July Budget has given us and the hon. House has cleared for us. So, we are not going to say here we give additional, there we do not. It is not like that. It is only a reallocation on very many heads and recategorization because of which the House has to be informed and House's permission has to be sought. So, I just want to make that absolutely plain when we are talking about supplementary grants.

Now, I just move from one to another on the various questions which very many Members have asked. It was mentioned by one hon. Member that only after 5-6 months of July Budget, you have come with a change in allocations and your revenue is all not being up to mark. I just want to give you this particular data. Before that, the first speaker, Shashi Tharoor mentioned even for fisheries, you have not even done anything, whereas you have promised that you would give a separate Ministry. A new Department of Fisheries has been started, and in the BE of 2019-20, Rs.804.75 crore have been allocated for them. As on date, that department, which is specialising only in fisheries has expenditure already cleared for Rs.291.99 crore. It is not that we have not given money. We have allocated money and it is also getting spent.

There were some questions about revenue receipts and questions about what is the kind of expenditure. I just want to give you a figure which is relevant up to October 2019. These are all estimates but actual expenditures, what I am giving you are subject to correction. There is a growth of 15.06 per cent in revenue receipts and up to October 2019, it is Rs.9,07,634 crore. So, please let us at least, in this House take the data that it is going up and not coming down. Revenue expenditure which is important, especially, when I have heard a lot of hon. Members saying Government should spend, consumption needs boost, you have to give consumption stimulus. Revenue expenditure has gone up by 13.61 per cent and capital expenditure has also gone up by 13.7 per cent. So,

Government and its expenditure is not remaining still. In order to boost consumption from the Government side, we are really moving ahead with clearing the bills, paying all the dues, and so on.

Then, it was mentioned in MGNREGA, you have cut down wages, rural consumption is very poor, rural demand is lying low, you have to do something. Even two days ago, while responding to the Taxation Bill, I said how much has the loan outreach by the public sector banks both in October and in November have extended to the various categories of people who want it. But then, you said that is low, what are you doing regarding MGNREGA's wages, in fact, you have cut it. No, we have not cut it and I will give you the data for it. Actually, GNREGA has received funds like never before. I will start from the year 2012-13. In 2012-13, the Budget Estimate was Rs. 33,000 crore, Revised Estimate was Rs. 29,387 crore and the actual expenditure was Rs. 30273.60 crore. In that order, it was Rs. 33,000 crore in 2013-14, Rs. 34,000 crore in 2014-15 and so on. What is it now? It is Rs. 60,000 crore. You would say that is the Budget Estimate and let us go to the Revised Estimate and the actual expenditure of the previous year. In 2018-19, which is the last financial year, the Budget Estimate was Rs. 55,000 crore, the Revised Estimate was Rs. 61,084 crore and the actual expenditure was Rs. 61,829 crore. I will read this out for all the years. But Dr. Shashi Tharoor asked about his State Kerala and later I heard Supriya ji ask about Maharashtra. I have

just managed to cull out something urgently. In 2013-14, for Kerala, it was Rs. 1277 crore. In 2018-19, it was Rs. 2,355 crore. ...(*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR: The workers are not getting the money.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Workers are not getting it? I will come to that also. DBT is actually making the actual workers rich, and not the *dalals*. ...(*Interruptions*) There is no *dalal*, no cheating and it actually goes to workers. ...(*Interruptions*) There is no *dalal* anywhere.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): There are no *dalals* in Kerala. ...(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: When we talk about Kerala, what was the expenditure in 2013-14? It was Rs. 1,277 crore. What is it as on 4th December 2019? It is Rs. 2,199 crore. Now, I come to Maharashtra. ...(*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I did not ask about it. I asked about the GST collection.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: That is all right. If you are convinced, I lay it here and you can always take it. So, MGNREGA is better implemented, gets more money, it goes through DBT to workers themselves, there is no *dalaal*, and therefore, be sure that we are actually doing well on that. Let me also say this on this particular data which will be of interest to all of us. Does DBT really mean that we are saving money? Are we not letting go any leakages unattended? No, every leakage has been plugged. What are the total savings since DBT has started

getting implemented under different headings? It may have started earlier under one heading, and a bit later under some other heading. But on an average, for the last five years, DBT is active. An amount of Rs. 1,41,676 crore is what has been saved by stopping leakages. For that, the data is available under different headings of schemes. I leave it on the table of the House for any Member who will be interested.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Do we have the data of average days of employment?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I will give you all the record. Money would not go to workers for sitting at home, Sir. Money goes to them only when they are working. I will come again to MGNREGA. In 2019-20 up to now, 6.2 crore individuals have been provided employment and they belong to 4.4 crore households.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: How many days per year have they got employment?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am coming to that. Please listen to me. 169.71 person-days of employment have been generated. Sir, 169.71 person-days of employment has been created. That is the performance of MGNREGA.

DR. SHASHI THAROOR: But the payments have been derailed....(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon. Member Shri Senthilkumar from Dharmapuri, raised an issue about the establishment of AIIMS in Madurai. The

Union Cabinet has approved establishment of AIIMS in Madurai at a cost of Rs.1264 crore in December 2018. The Ministry has appointed RITES as the agency to carry out the pre-investment work. The work is going on. The project was approved and taken under the rolling plan by the Department of Economic Affairs for external development assistance under the Japanese International Cooperation Agency (JICA).

As on 2019-90 an amount of Rs.5 crore has been transferred by the Ministry of Health and Family Welfare to AIIMS, Madurai for the construction of boundary wall. The preparatory survey work by JICA is expected to be completed by the first week of January, 2020. That is just the status of AIIMS Madurai for you to be informed because you did raise the question.

Hon. Member, Shri Senthilkumar again spoke about rural sanitation and wondered how many toilets are still being used. He said that they are all being constructed but they may not be under use. The National Annual Rural Sanitation Survey of 2018-19 has found that 96.5 per cent of all households, having access to a toilet, use them regularly. And, therefore, let us not have apprehension about it.

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. : You can send a team for inspection. I can challenge that not 10 per cent of the toilets constructed are in use in my constituency.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Maybe, your constituency is one among the several constituencies which are surveyed....(*Interruptions*) Your intention and the Government's intention are not very different. But this is not my survey. It is done by an independent agency.

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. : That is why I am saying that you can send a team....(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am not here to inspect any constituency. You are the MP of that area. I am sure, you can take care of it....(*Interruptions*) You are the MP of that area and you will ensure that the Government's money, which is spent for the public cause of sanitation, will have its right fruits. You are the MP. You are the elected person there. You should take care that the public money, which comes from both Centre and State Government, is spent properly. You are there representing all of us. I am sure you will talk in your concerned Committees about it.

SHRI S. S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): He has already taken his seat. You can continue with your reply.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I will continue with my reply. Thank you very much. That is very considerate.

I will go back to talking about the outreach. The concern expressed by Members is about rural demand, rural economy and money not reaching rural areas. I just want to highlight it. In November and October, MSMEs, NBFCs,

corporates, retails, agriculture sector borrowers, all of them have been reached through the loans which were given to them. MSME loans alone totalled to Rs.37,210 crore in October and Rs.35,775 crore in November. So, nearly, Rs.72,000 crore has been given only to MSME in those two days. NBFCs, who will further lend money to customers, were given Rs.17,163 crore in October and Rs.25,005 crore in November. Then, home loans were Rs. 12,166 crore in October and Rs. 15,088 crore in November; vehicle loans were Rs. 7,085 crore in October and Rs. 4,003 crore in November; education loans were Rs. 425 crore in October and Rs. 686 crore in November; agriculture loans were Rs. 40,504 crore in October and Rs. 37,870 crore in November and there are other loans. So, totally, Rs. 2,52,589 crore in October were disbursed for all these headings and Rs. 2,39,245 crore were disbursed in November. As I have said earlier, this happened in 400 districts of the country in the hinterland and not in the metropolitan cities.

There was also this concern that FDI inflows are all affected. We are not getting money. Professor, I remember your very strong words, 'fear everywhere, no investment will come'.

PROF. SOUGATA RAY: Fear factor.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yes, fear factor is fear. That is what you have said, 'fear everywhere'. ...(*Interruptions*)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): I need to seek one clarification from Professor Sougata Ray.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, if you permit. ...(*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Professor Sougata Ray Ji is not a Minister. ...(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I would like to talk about FDI inflows. I am talking about the net inflows. I am not even giving the gross figures. The net FDI inflows were 17 billion dollars in H1 of 2018-19 and in H1 of 2019-20, which is this year's first half, it is 20.9 billion dollars. That was 17 billion dollars and this is 20.9 billion dollars. Professor Sougata Ray, the 'fear factor' does not exist. So, that is one figure for you, particularly about investment.

PROF. SOUGATA RAY: It should have been 25 plus.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: It can be 550 plus. I agree. It can be even more.

The capital infusion to banks has happened and as you are aware, I had announced this in the Budget also, inclusive of IDBI. We had to give that money to the IDBI. I want to give a bit of a detail on it. That is a bit of a long answer. But before I go to talking about the IDBI, I want to talk about onions. Season-wise area and production estimates of onions, as given by the Horticulture Division, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, as on 15.11.2019 are as follows. The hon. Minister is here. There has been definitely a reduction in the area of

cultivation. In 2017-18, the area for the Kharif was 2.68 acre and in 2018-19, it was 3.30 acre, which is more. But in 2019-20, it has come down to 2.60 acre. So, the area of production has come down.

Now, I come to the production quantity. In 2017-18, it was 44.08 lakh metric tonnes; in 2018-19, it was 50.64 lakh metric tonnes. This year, the first estimate and the advanced estimate is 38.87 lakh metric tonnes. There is a shortfall. There is also a shortfall for late Kharif. Acreage has come down from 1.63 acre to 0.81 acre and the production has come down from 30.18 lakh metric tonnes to 13.19 lakh metric tonnes. There is a drastic fall in the output in the late Kharif. In the Rabi season, the area under cultivation was 8.54 acres in 2017-18 which in 2018-19 was 8.23 acres. I cannot give you the acreage now because sowing has just started. Therefore, the assessments are yet to be received. So, there is a reduction in the area of cultivation and also reduction in the output. ...(*Interruptions*) I have not finished.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: The market is on fire.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I have not finished yet. I will tell you what steps the Government has taken in this regard. I am stating the background and what kind of steps we have taken to ensure that onions reach the market.

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप बाजार में दाम में कटौती कीजिए, अवेलेबिलिटी बढ़ाइए, बाजार में आग लग गई है। ...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन चौधरी जी को एक शब्द याद है – आग लग गई।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : 140 रुपये किलो दाम हो गया है। लोग कैसे खरीदेंगे? लोगों की जेब खाली और सरकार बजाए ताली, ऐसे नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the Price Stabilisation Fund has been used and a buffer stock of about 57302.90 MT of onions was built and this was based on the Rabi harvest of April and May, 2019. From the State of Maharashtra 48,184 MTs and from Gujarat 9189 MTs of onions were procured for that purpose, out of which quantity a quantity of around 26,842 MTs which is about 46.78 per cent of procurement was supplied to the various Governments, agencies, cooperatives and sold in various *mandis* through open auction during the period ending October, 2019. So, it is not as if we have not taken some steps. You have mentioned some steps and I am telling you some of the steps which we have taken ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी के अलावा किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

*
...

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: A quantity of around 11,513 MTs which is again 20 per cent of low quantity onions were disposed by NAFED in local markets. I just want to give you the figures as a percentage also. Total procurement, buffer stock position of Rabi based onions as on 2nd December,

* Not recorded.

2019 is 57,372.90 MTs. That is the total quantity procured. Total storage is 56,000 and so on.

I want to let you know the steps which we have taken other than procurement. Distribution is happening through open auction in *mandis* such as Kolkata, Bhubaneswar, Lucknow, Hyderabad and Chennai. Onions also have been supplied to States and other agencies for retailing, distribution and supply to Delhi NCR through Mother Dairies. For direct retailing at regulated prices, NCCS and NAFED and Government of NCT of Delhi have been distributed. Also, I want to say that the export of onions has been banned by the DGFT's notification in September, 2019. The notification was on 29th of September and so it must have come into implementation by the fag end of September, 2019. Stock limits on onions have been imposed through that same notification of 29th September, 2019. Under the Essential Commodities Act a limit of hundred quintals on retail traders and 500 quintals on wholesalers have been invoked. Government has decided to import or procure from open market 1 lakh MT of onions from surplus countries and regions. In this regard, you must have seen in the media that MMTC has already floated the tenders.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: But it has no tangible impact on the market. In spite of all the measures that you have taken, it has no tangible impact on the market ...(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: NAFED was directed to procure surplus onions from Rajasthan and other distribution centres and to send it to deficit States. So, that activity is also going on. Dispatch of onions from Alwar, Rajasthan is the information which I want to give you, because that procurement has definitely gone to certain parts. If we talk about Delhi, 28 truck loads have gone to Delhi, directly from Alwar. 442 metric tonnes of onions have come from there. Eight truck loads have gone to Bihar, that is, 263.03 metric tonnes of onions have been sent from Alwar directly to Bihar. Five truck loads have been sent to Jharkhand, that is, 179.64 metric tonnes of onions have gone to Jharkhand directly from Alwar. There are many other propositions that MMTC is importing it from Egypt, MMTC has placed an order from Turkey, and they are also coming in. So, I just want to let you know that various steps have been taken for the distribution of onions in the shortage-ridden areas. These are some steps which I have talked about. There are many others which the concerned Ministry will also speak about. ...(*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: 50 per cent of the stored onions have been damaged. ...(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Then, Supriyaji also raised this question that agriculture has not been included in the Supplementary Demands for Grants. I just want to say that allocation for agriculture, in the BE of 2018-19, was Rs. 46,700 crore, whereas in the BE of 2019-20, it has risen to Rs. 1,30,485 crore, which

is 250 per cent increase for agriculture allocation between last year and this year. So, I just want to draw hon. Member Supriyaji's attention to this.

I am not sure if the Member who raised this issue is here around but for the benefit of the House, without taking his name, as per your order, hon. Speaker Sir, I will just respond. One Member did say passionately that the allocation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are coming down. I just wanted to reply to him. Is he here? ...*(Interruptions)* I cannot see him. ...*(Interruptions)* Okay, you are here. It is alright. ...*(Interruptions)*

I just want to let you know, Sir, that the allocation for Scheduled Castes as per the actuals of 2017-18 Budget was Rs. 49,492 crore, which went up to Rs. 56,618.5 crore in the BE of 2018-19. In the RE of 2018-19, it was reconciled to be Rs. 62,473.86 crore. Just for you, before you ask me the question, I can see you waiting to ask me a question, these allocations are across all demands. Those number of demands in the Budget are about 100. All put together is what I am giving you the figures. Hence, not of one particular Scheme. Is it alright? If that is in RE of 2018-19, BE of 2019-20, which is what is going on now, hon. Members will be happy to know that what was Rs. 49,492 crore in 2017-18 has now in the BE of 2019-20 gone up to Rs. 81,340.74 crore. This is only for Scheduled Castes.

Now, I will come to the Scheduled Tribes. Actuals of allocation for Scheduled Tribes for 2017-18 is Rs. 31,913.72 crore. I will not go step by step but BE was Rs. 39,134 crore for the next year, Rs. 41,093 crore for the RE of 2018-

19 but what is it now, that is, BE of 2019-20. From Rs. 31,913.72 crore, it is now Rs. 52,884.82 crore. So, allocations for SCs and STs have only grown and grown substantially, for hon. Member Ritesh to be sure. Is it alright? ...*(Interruptions)* You can always move on to something else. I just have last two points. ...*(Interruptions)*. Since you have raised it, I will finish this. ...*(Interruptions)*.

Now, I come to IDBI. I am sure all of us will like to hear this क्योंकि 2008 से लेकर 2014 तक, इनके समय में सब कुछ फोन पर चला, इनको दो, उनको दो, लोन देते जाओ, चाचा, भतीजा, भाई, बहन, सबको मिला । ...*(व्यवधान)*. So, due to the aggressive lending between 2008 and 2014, gross advances of IDBI Bank increased from Rs. 82,664 crore to Rs. 2,03,376 crore. Rampant!! सबको दे दो, सबको दे दो, यह हुआ । दूसरा देख लीजिए, अभी क्या हो रहा है, एक महीने के बाद अगर इंस्ट्रेस्ट नहीं दिया तो कानूनन, प्रूडेंशियल नॉर्म्स के तहत इंस्ट्रेस्ट नहीं दिया तो स्ट्रेसड लोन, फिर स्ट्रेसड-1, स्ट्रेसड-2, फिर एनपीए हो जाता है । यह हम सबको मालूम है । Stressed loans were not even recognized as NPAs. छोड़ दिया, हमारा है । छोड़ दो, खाएगा पैसा । छोड़ दिया गया । IDBI's loans were all left without being categorized as NPA, stressed accounts continued, the loans kept going. Under Asset Quality Review, stressed loans were recognized as NPA transparently since after 2015. उससे पहले नहीं हुआ and losses were provided for. अभी भी सब लोग पूछते हैं कि लॉसेज दे रहे हो, मतलब राइट ऑफ कर रहे हो, राइट ऑफ नहीं करते हैं, मगर हिसाब-किताब मेंटेन करने के समय, any Chartered Accountant will know that one has to provide for the books to be balanced, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि उनको छोड़ देते हैं । उनके पीछे पड़ते हैं, उनकी सम्पत्ति को जब्त करते हैं और उसे ऑक्शन करके उस पैसे को वापस ले

आएंगे। मगर यह सब कार्यक्रम 2015 से शुरू हुआ। उससे पहले नहीं हुआ। आईडीबीआई की हालत के ऊपर इतने सारे लोगों ने, क्रोकोडाइल टियर्स शेड कर रहे हैं, कैसे शेड कर रहे हो? और सुनिए। As a result, gross NPAs of the banks rose from Rs. 12,685 crore. उधर से मार्च, 2015 को इतना एनपीए हमने रिकग्नाइज किया। 12,685 करोड़ रुपये हमने 2015 में रिकग्नाइज किया, वह बढ़ते-बढ़ते कहां तक पहुंचा – सितम्बर, 2018 तक 60,875 करोड़ रुपये। यह आईडीबीआई की हालत थी। ...(व्यवधान). प्रोफेसर जी का प्रश्न यह है कि 2018 का मतलब है कि आपका टाइम है। तब का लोन मेच्योर होते-होते एनपीए बना हमारे टाइम में, लेकिन यह लोन आपकी देन है। ...(व्यवधान) आपके समय का लोन है, वह बाद में आकर एनपीए हुआ। ...(व्यवधान). Yes Supriya Ji.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I have two small questions. I appreciate everything that you are saying but a lot has been said about the Mudra loans. So, my question to you very humbly is, since Mudra was started by you, according to the data that is accessible to us, about 53 per cent of the loans are NPA which is Rs. 4 lakh crore. ...(Interruptions). महिला सक्षम है, महिला सबला है।...(व्यवधान). She does not need to be defended. There is one more small question. Since you talked about onions, I just have a small query. I appreciate that you managed getting onions from Egypt. I come from Maharashtra, which is the largest pool collector of onions.

Firstly, why has the production of onion come down? Bharati Pawar is sitting right here. She represents Nashik; and she will agree with me here. This is not at all a political point that I am making. But when the onion prices had hit

rock-bottom, that was the time they needed support. Was that the reason that they did not get the right price because the MSP was not good, and hence the production went down? I take great pride in being an Indian, I am proud to be an Indian, which feeds every Indian's mouth. So, why has the production come down? I am not happy eating Egyptian onions. Why should India do it? We export rice; we export milk and many other products. We are the second largest producer of rice and wheat in the world. Why are we doing this? Is it not a regressive step? If you could kindly clarify both the points about the Mudra loans NPAs as well as the onions. The onion grower is a small farmer. The onion farmer is not having 20 acres or 30 acres. He is a small farmer with less water. So, he really needs to be protected. That is my request ...(*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Do you eat onions?

श्रीमती निर्मला सीतारमण : मैं लहसुन, प्याज नहीं खाती हूँ। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ, जहाँ लहसुन, प्याज से मतलब नहीं रखते हैं। So, do not worry.

Hon. Member, Supriya-ji, I must say that from 2014, I have also been part of some of the Group of Ministers, which monitored the ups and downs in onion markets. Sometimes, when there was a surplus of crop, we have also facilitated by giving the support to those people, who want to export it. I have, overnight, passed orders for helping with five to seven per cent assistance for exporting it.

There are severe structural problems related to onions. One is, we do not have scientifically advanced methods of storing; and I must appreciate the effort,

Nitin Gadkari-ji, my senior colleague in the Cabinet, has made. He even went to the extent of getting the Bhaba Atomic Research Centre to come and tell how through radiation, we can remove the moisture content of the onion and preserve it for a longest shelf-life. There was a great effort of Nitin Gadkari-ji. So, that is one of the things.

So, we need to have greater scientific storage facility for onions, and we have started working on it.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Your stand on research for GE is of the Government. So, they are not so keen.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: No, no. One minute. Not every radiation, as much as I know, is harmful. Particularly, for perishable food items, there are scientifically accepted levels, which do not harm the human element. All that is kept in mind.

PROF. SOUGATA RAY: Dr. Bharati Pawar is from your party.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: It is all right. Supriya-ji is not from my party, but still I hear her. Professor, do not worry ...*(Interruptions)*

So, you know about the storage capacity, the type of storage that we have. I think, most of us have heard about Lasalgaon. Thanks to Nitin-ji. Again and again, he has spoken to us about the freight that is in terms of onion capacities. So, we are looking at ways in which we can improve the post-harvest capacities for onions. This year, particularly, we have also had some of these districts with

undue weather conditions, flooding, as a result, the acreage has come down. Therefore, I think, we have to keep the context in mind. I would want to, and as a matter of fact all of us will have to look at the way in which onion, which is a seasonal crop and does not have a long shelf life is truly a perishable vegetable. So, it is something, where all of us will have to look at ways.

The last point is about the IDBI. After four hours, I have repeatedly spoken ...*(Interruptions)*

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैं कहना चाहता हूँ कि जब अनियन का शार्टफाल हो रहा था, तो प्रिवेंटिव मैजर के तहत तुरंत बाहर से अनियन क्यों नहीं आयात किया गया? अगर समय पर अनियन का आयात किया जाता, तो आज यह हालत नहीं होती।

दूसरी बात यह है कि आप स्वयं कहते हैं कि बिचौलिए आ गए, जमाखोर आ गए। अनियन शार्टफाल की क्या वजह है, क्या बिचौलियों के कारण, जमाखोरी के कारण या आपकी सरकार के रवैये के कारण? सरकार के काम-काज की कमियों के चलते, बिचौलियों के चलते, जमाखोरों के चलते या सही वक्त पर आयात नहीं किया गया, इसके चलते, वजह क्या है, हम यह जानना चाहते हैं।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Onion is not the only issue here.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: No, I am addressing everything also....*(Interruptions)* Premachandran ji, I am addressing every issue. I am also addressing the issue raised by one of the hon. Members and, therefore, you should have the patience to listen to that also....*(Interruptions)* I will listen to you. ...*(Interruptions)* Onion is something, which, even Adhir ji and Maharashtra MPs

raised, so, it is my duty to respond to them also...*(Interruptions)* You just hold on.
...*(Interruptions)*

So, in four hours, we adopted reorganising, restructuring and recognising that there was an NPA problem. The recapitalisation was done by the Government by infusing Rs. 21,157 crore into IDBI since 2015, after we came, and LIC infused Rs. 21,624 crore. So, both put together have given Rs. 42,781 crore to the IDBI only because of the rampant loan largesse which happened during 2008 and 2014. Now, this has reduced the net NPAs. Therefore, the NPA ratio from the peak of 17.3 per cent in September, 2018, has come down to 5.97 per cent in September, 2019. So, it has come down from 17.3 per cent to 5.97 per cent which is below the RBI's 6 per cent net NPA threshold. Therefore, under the prompt corrective action, IDBI has come out because of this infusion of cash done by the Government and also by the LIC. Therefore, if the Supplementary Demands for Grant comes in, it is only because we are constantly correcting those errors, those largesse, those benefits, which were given between 2008 to 2014 as a national responsibility. So, I hope that address the majority of the questions.

There were questions raised on railways which I do not want to take too much time. I will probably stop with this.

There is a question of insurance companies. I have given you one on the IDBI. There are a few other things which I would like to explain....*(Interruptions)*

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: There are certain other things....(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am coming....(*Interruptions*) There is something which you have flagged today. I am not giving it as an assurance but that is something which I have heard from you. I am, certainly, not giving an assurance but I will have to go back and see. You have given me some data. I will have to go back to see where does it come from. Is it all NPA? What is it? I have to see that. So, let me go back to see that.

As regards the last word, Sir, इसे मैं समाप्त करूंगी, to maintain the regulatory minimum solvency across the three public sector general insurance companies, the United India Insurance, the National Insurance and the Oriental India Insurance, this solvency is required. That which has been claimed here under the Supplementary Demands for Grants and, therefore, I want this infusion be cleared as a Supplementary Demands because to write any new business, the pressure being faced by these companies on their balance-sheets and margins will have to be eased-out. To bring in sustained growth and momentum to these companies, we need this infusion and that is where the Supplementary Demands for Grants includes Rs. 2,500 crore....(*Interruptions*) I have not finished....(*Interruptions*) I have not even sat down, Mr. Kodikunnil Suresh. ...(*Interruptions*) I have not even sat down. ...(*Interruptions*) I have not even sat down. ...(*Interruptions*)

As regards NPAs on MUDRA, I have just been given something which I can share as a preliminary input. I will, of course, have to come back. Against the total loans disbursed under MUDRA, 2.52 per cent is all that we have as NPAs. Against the total loans given under MUDRA, 2.52 per cent only is the NPA against the total amount outstanding. How much is outstanding? Six per cent is all that is outstanding. So, outstanding is something beyond due time. But I have already given you the input. So, with that I suppose, Speaker, Sir, आपने मुझे बोलने के लिए इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे इलैबोरेटली जवाब देने का मौका मिला। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हाउस के मेम्बर्स सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रंट्स को पारित करें, जिससे सरकार चलाने में सुविधा हो।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय ने वर्ष 2019-2020 के लिए अनुदानों की अनुपूरक माँगों के संबंध में कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 7 प्रस्तुत किए हैं। मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के समक्ष मतदान के लिए रख रहा हूँ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं वर्ष 2019-2020 के लिए अनुपूरक अनुदानों की माँगें – प्रथम बैच को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

“कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में माँग संख्याओं 1 से 4, 7, 8, 10, 11, 14 से 17, 19, 20, 22 से 27, 29, 32 से 34, 38, 40 से 44, 46 से 49, 51, 53, 56 से 58, 60 से 62, 64, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 79, 82 से 84, 86, 89 से 91, 93, 94 और 96 से 100 के सामने दिखाए गए माँग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियाँ भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएँ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अनुपूरक अनुदानों की माँगें – प्रथम बैच पारित हुआ।

19.54 hrs

APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2019*

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2019-20.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I introduce** the Bill.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 19. विधेयक पर विचार किया जाना है।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

“That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 04.12.2019

** Introduced with the recommendation of the President.

the services of the financial year 2019-20, be taken into consideration.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 और 3

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

“कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

19.57 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 5,
2019/Agrahayana 14, 1941 (Saka)*
